ಶುಭ್ ಲಾಭ್

खबरें जो सोच बदल दे

शुभ लाभ

DAILY

हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

कर्नाटक में मुस्लिम आबादी 18.08 प्रतिशत सर्वे में 8 प्रतिशत आरक्षण की ... @ नम्मा बेंगलूरु

Postal Regd.No. HQ/SD/523/2023-25 । सोमवार, 14 अप्रैल, 2025 । हैदराबाद और नई दिल्ली से प्रकाशित । website : https://www.shubhlabhdaily.com । संपादक : गोपाल अग्रवाल । पृष्ठ : 14 । मूल्य-6 रु.। वर्ष-7 । अंक-102

राष्ट्रपति के शीर्ष संवैधानिक आसन की सुप्रीम कोर्ट ने की अवमानना

सुप्रीम कोर्ट ने ताक पर रख दिया देश का संविधान!

संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार, राज्य का राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा होता है। राज्यपाल जब किसी बिल पर सहमति देता है तब वह कानून बन जाता है। इस तरह कानून बनाने, उसे पारित करने और उस पर सहमति देने का कार्य पूरी तरह से विधायी प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय विधायी प्रक्रिया में न्यायपालिका का सीधा हस्तक्षेप है।

सुप्रीम कोर्ट ने स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार शीर्ष संवैधानिक आसन राष्ट्रपति को आदेश देने की अवमानना की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल की ओर से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर फैसला लेना ही होगा। राष्ट्रपति के फैसले के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने की घोषणा कर देश में विधायी अराजकता फैलाने की शुरुआत कर दी है। तमिलनाडु से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा की ओर से भेजे गए बिल पर राज्यपाल को एक महीने के भीतर फैसला लेना होगा। और अगर वह राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेजा जाएगा तो राष्ट्रपति को भी तीन महीने के अंदर फैसला लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला आठ अप्रैल को लिया और उस पर सुनियोजित रूप से विचार करने के बाद 11 अप्रैल 2025 को सार्वजनिक किया।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में संविधान के अनुच्छेद 201 का हवाला दिया गया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने इसमें कहा है, राज्यपालों द्वारा भेजे गए बिल के मामले में राष्ट्रपति के पास पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और न्यायपालिका बिल की संवैधानिकता का फैसला करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को उस बिल को स्वीकार करना होगा, उस पर राय देकर देकर वापस भेजना होगा या फिर अस्वीकार करना होगा। यह सब कुछ तीन महीने के भीतर करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि राज्यपाल द्वारा भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को बार-बार लौटाने की प्रक्रिया भी रोकनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हदें लांघते हुए यहां तक कह दिया कि अगर राष्ट्रपति समय-सीमा के भीतर कार्रवाई करने में विफल रहते हैं तो प्रभावित राज्य सीधे अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल की संवैधानिकता के मामले में कार्यपालिका को जज नहीं बनना चाहिए। ऐसे मुद्दों को अनुच्छेद 143 के तहत निर्णय के लिए सुप्रीम कोर्ट भेजना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के प्रसंग में देश के लोगों को यह जानना-समझना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय कानूनी है या गैर कानूनी। सुप्रीम कोर्ट का ताजा फैसला शीर्ष संवैधानिक आसन को चुनौती देने वाला है, लेकिन यह फैसला सुप्रीम कोर्ट की संविधान-पीठ का नहीं है। जबकि संविधान के अनुच्छेद 145 (3) में यह अनिवार्य प्रावधान है। अनुच्छेद 145 (3) में कहा गया है, संविधान की व्याख्या के संबंध में विधि के किसी सारवान प्रश्न से संबंधित किसी मामले का निर्णय करने के लिए या अनुच्छेद 143 के अंतर्गत किसी संदर्भ की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या न्यूनतम पांच होना अनिवार्य है। इसमें कोई वैकल्पिक प्रावधान भी नहीं है, यानि इस नियम का सुप्रीम कोर्ट को पालन करना ही होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 की व्याख्या करके दिया है। जबकि विडंबना यह है कि सुप्रीम कोर्ट की यह बेंच न तो संवैधानिक थी और न ही इसमें न्यूनतम पांच जज शामिल थे। ऐसे में संविधान के अनुच्छेद 145 (3) का उल्लंघन करके सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय वैध है या नहीं, इसे आसानी से समझा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कार्यपालिका को खुद जज नहीं बनना चाहिए, उसे संवैधानिक मामलों से जुड़े मामलों को अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट भेजना चाहिए। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि संविधान के मसलों से जुड़े ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए संविधान के निर्माताओं ने उसमें अनुच्छेद 145 (3) का प्रावधान किया था, ताकि उस पर विद्वान जजों की बहुमत द्वारा विश्लेषण किया जा सके।

▶10 पर

सुप्रीम कोर्ट के दो जजों ने खुद को संवैधानिक पीठ समझ लिया

शुभ-लाभ चिंतन

सुप्रीम कोर्ट के फैसले से देश में विधायी अराजकता शुरू

राज्यपाल की मुहर के बिना पारित हो गए 10 विधेयक

चेन्नई, 13 अप्रैल (एजेंसियां)। सुप्रीम कोर्ट ने देश में विधायी अराजकता की शुरुआत कर दी है। अब कोई भी राज्य मनमाने तरीके से फैसले लेगी और विधेयक पारित करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आघात करते हुए राज्यपाल और राष्ट्रपति के औचित्य पर भारी संकट ला खड़ा किया है। इस अराजकता का फायदा उठाते हुए तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने शनिवार को सभी 10 विधेयकों को अधिनियम के रूप में अधिसूचित कर दिया।

राज्यपाल की सहमति के बगैर ही तमिलनाडु सरकार ने शनिवार को 10 कानूनों को अधिसूचित कर दिया। इन्हें पहले राज्यपाल ने रोक दिया था। यह कानून उनकी सहमति के बिना ही प्रभावी हो गए। 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि का 10 विधेयकों को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखने का फैसला अवैध और गलत था, जबकि राज्य विधानसभा ने उन पर पुनर्विचार कर लिया था। कोर्ट ने राज्यपालों के लिए उनके सामने पेश विधेयकों पर फैसला लेने के लिए समय सीमा भी तय की थी। पिछले साल राज्यपाल ने विधेयकों को मंजूरी देने में देरी की थी और रोक लगाई थी। इनको तमिलनाडु की विधानसभा ने फिर से पारित किया था। इन्हें राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन्हें पारित मान लिया गया। सरकारी राजपत्र के माध्यम से औपचारिक रूप दिया गया सरकार का यह कदम, केंद्र-राज्य संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ है व संघीय ढांचे में शक्ति संतुलन को फिर से परिभाषित करता है।

इसे ऐतिहासिक घटनाक्रम बताते हुए मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डीएमके का मतलब इतिहास बनाना है। इन अधिनियमों में से एक तमिलनाडु मत्स्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 2020 है। इसके तहत विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉ. जे. जयललिता मत्स्य विश्वविद्यालय कर दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों में कुलपतियों की नियुक्तियों में राज्यपाल का दखल खत्म हो जाएगा। इससे उम्मीदवारों को सूचीबद्ध करने और उनकी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव तय करने की शक्ति सरकार को मिल गई है। इतना ही नहीं अब राज्य के सीएम यूनिवर्सिटी के कुलपति होंगे।

राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट में डीएमके के वकील पी विल्सन ने कहा कि इतिहास रचा गया है क्योंकि ये भारत में किसी भी विधानमंडल के पहले अधिनियम हैं जो राज्यपाल-राष्ट्रपति के साइन के बिना बल्कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बल पर प्रभावी हुए हैं। हमारे विश्वविद्यालयों को अब सरकार के कुलपतित्व के तहत स्वच्छ बनाया जाएगा और एक नए स्तर पर ले जाया जाएगा। मामले के जानकार अधिकारियों के मुताबिक, डॉ. एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी,

▶10 पर

तमिलनाडु सरकार को मिल गया सुप्रीम कोर्ट का बहाना

उधर ममता बनर्जी फैला रही हैं पश्चिम बंगाल में अराजकता

वक्फ कानून का बहाना मकसद अस्थिरता फैलाना

कोलकाता, 13 अप्रैल (एजेंसियां)। पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के नाम पर इस्लामी भीड़ की हिंसा लगातार जारी है। इस्लामी भीड़ सुरक्षाबलों को भी निशाना बना रही है। पुलिस के बाद उसने अब कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर मुर्शिदाबाद पहुंची सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को निशाना बनाया है। बीएसएफ जवानों पर फायरिंग की गई है। हिंसा के बीच हिंदू मुर्शिदाबाद से पलायन को मजबूर हैं। बेकाबू हिंसा की स्थिति में बंगाल के संवेदनशील जिलों में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट (अफस्पा) लागू किए जाने की मांग प्रबल हो रही है। राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा के कारण राज्य की पुलिस पूरी तरह निष्क्रिय है। कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर केंद्रीय अर्ध सैनिक बलों ने मोर्चा संभाला है लेकिन कानून एवं व्यवस्था के पालन में राज्य प्रशासन या पुलिस से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है।

मुर्शिदाबाद में शनिवार को बीएसएफ की टीम पर इस्लामी भीड़ ने हमला किया। यह हमला मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज इलाके में हुआ। यहां तैनात जवानों को निशाना बनाया गया। वक्फ के नाम पर प्रदर्शन कर रहे इस्लामी कट्टरपंथियों ने बीएसएफ जवानों पर पत्थर बरसाए और उनकी गाड़ियां तोड़ दीं। रविवार को धुलियान इलाके में भी बीएसएफ के ऊपर कट्टरपंथियों ने फायरिंग की। इस फायरिंग में दो बालक घायल हो गए। बीएसएफ के किसी सुरक्षाकर्मी के घायल होने की सूचना नहीं है। मुर्शिदाबाद में इस्लामी भीड़ की हिंसा रोकने में पश्चिम बंगाल पुलिस के नाकाम होने के बाद कलकत्ता हाई कोर्ट ने शनिवार को केंद्रीय सुरक्षाबलों की तैनाती के आदेश दिए थे। इसके बाद मुर्शिदाबाद में बीएसएफ तैनात की गई थी। हिंसा में पहले पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। बीएसएफ के पहुंचने के बाद इस्लामी भीड़ ने उन्हें भी निशाने पर लिया।

दक्षिण 24 परगना के बारुईपुर में तुलसी की माला पहने एक हिंदू व्यक्ति को मुस्लिम भीड़ ने बुरी तरह पीटा और अधमरा कर दिया। उसकी एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें वह अस्पताल में इलाज के दौरान अपनी पीड़ा बता रहा है। भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने बताया है कि मुर्शिदाबाद के शमशेरपुर में इस्लामी भीड़ के हमलों से बचने के लिए सैकड़ों लोग भाग कर दूसरी जगह जा रहे हैं। अपना घर-बार छोड़ने वालों में अधिकांश महिलाएं हैं। बड़ी संख्या में बच्चे और पुरुष भी इलाका छोड़ रहे हैं। इससे पहले मुर्शिदाबाद में इस्लामी भीड़ ने एक हिंदू पिता-पुत्र की हत्या कर दी थी। वह लोग मूर्तिकार थे। इस्लामी भीड़ के हमले में 15 से अधिक पुलिसकर्मी भी घायल हैं। वहीं इस दौरान भी राज्य में लगातार वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति ममता सरकार दिए जा रही है। मुर्शिदाबाद में इस्लामी कट्टरपंथियों की हिंसा में तीन लोगों की मौत हो चुकी है,

▶10 पर

हिंदुओं की हत्या और लूट जारी बीएसएफ पर भी हमला

सियाचिन के वीर सपूतों को भारतीय सेना ने दी सलामी

सियाचिन, 13 अप्रैल (एजेंसियां)। सियाचिन दिवस की 41वीं वर्षगांठ पर भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्धक्षेत्र सियाचिन पर तिरंगा फहरा कर वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी। हर साल 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो 1984 में शुरू किए गए ऑपरेशन मेघदूत की याद दिलाता है। यह वह दिन है जब भारतीय सेना ने दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे कठिन युद्धक्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर अपने शौर्य के झंडे गाड़े थे।

वर्ष 1984 में पाकिस्तान की संभावित सैन्य कार्रवाई की जानकारी मिलने के बाद भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर रणनीतिक स्थानों को सुरक्षित करने के लिए ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। 13 अप्रैल 1984 को भारतीय सैनिकों ने बिलाफोंड ला और सियाला दर्रों पर कब्जा कर लिया और पूरे सियाचिन क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया। यह ऑपरेशन लेफ्टिनेंट जनरल एमएल छिब्बर, लेफ्टिनेंट जनरल पीएन हून और मेजर जनरल शिव शर्मा के नेतृत्व में शुरू हुआ था।

▶10 पर

बांग्लादेश में हिंदू संस्कृति की शिनाख्त मिटाने का फैसला

ढाका, 13 अप्रैल (एजेंसियां)। बांग्लादेश में मुहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली कट्टरपंथी इस्लामी सरकार ने बांग्लादेश से हिंदू संस्कृति की शिनाख्त मिटाने की ठान ली है। यूनुस सरकार लगातार हिंदुओं और उनसे जुड़ी परंपराओं, प्रतीकों और संस्कृतियों को नष्ट करने की कोशिशों में लगी हुई है। सनातन परंपराओं को इस्लामी परंपराओं को अनुसार ढाला जा रहा है। इसी क्रम में बांग्लादेश ने यूनेस्को से मान्यता प्राप्त मंगल शोभायात्रा का नाम और कंटेंट बदलने का फैसला किया है।

यूनुस सरकार ये सारे बदलाव इसलिए कर रही है क्योंकि उसे लगता है कि ये हिंदू संस्कृति को दिखाता है। इसलिए 14 अप्रैल को बंगाली नववर्ष 1432 मनाएगा। बंगाली नववर्ष के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस मंगल शोभायात्रा के नाम को भी बदल दिया गया है।

▶10 पर

कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण देने का रास्ता साफ

बेंगलुरु, 13 अप्रैल (एजेंसियां)। कर्नाटक में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण बढ़ाने की तैयारी है। इसकी सिफारिश कर्नाटक में की गई जाति जनगणना रिपोर्ट में की गई है। ओबीसी आरक्षण में बढ़ोतरी का सीधा फायदा मुस्लिमों को होने वाला है। मुसलमान कर्नाटक राज्य में सबसे बड़ा ओबीसी समूह है। जाति जनगणना की यह रिपोर्ट हाल ही में कर्नाटक कैबिनेट के सामने पेश की गई है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार इस जातिगत जनगणना के नए सर्वे पर 17 अप्रैल को बैठक करने वाली है। इस सर्वे में ओबीसी आरक्षण 32 प्रतिशत से बढ़ाकर 51 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है। इसी रिपोर्ट में मुस्लिम आरक्षण को भी 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है। 17 अप्रैल को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस आरक्षण को लेकर फैसला लिया जा सकता है। इसी बैठक में यह रिपोर्ट सार्वजनिक करने सम्बन्धित फैसला भी हो सकता है। कर्नाटक की जाति जनगणना रिपोर्ट में की गई सिफारिश अगर मानी जाती हैं,

▶10 पर

पश्चिमी सीमा पर सेना की तैयारियों का लिया जायजा

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (एजेंसियां)। थलसेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ने वज्र कोर का दौरा किया और पश्चिमी सीमाओं पर इसकी परिचालन तैयारियों का जायजा लिया। सेनाध्यक्ष ने सभी रैंकों को प्रोत्साहित किया। उन्होंने सैनिकों के उच्च मनोबल, व्यावसायिकता और अटूट समर्पण की सराहना करते हुए उनसे सेना के परिचालन उत्कृष्टता के सटीक मानकों को बनाए रखने पर जोर दिया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के साथ पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ (जीओसीइनसी) लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार भी थे।

व्यापक ब्रीफिंग के दौरान वज्र कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने सेना प्रमुख को मौजूदा सुरक्षा माहौल और कोर की तत्परता की स्थिति के बारे में जानकारी दी। जनरल द्विवेदी ने बाद में अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैन्य बलों की जमीनी स्तर की तैयारियों को प्रत्यक्ष रूप से समझने के लिए चुनिंदा अग्रिम जगहों का दौरा किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस दौरे का मुख्य आकर्षण सेना प्रमुख का भूतपूर्व सैनिकों से बातचीत करना और राष्ट्र निर्माण में

▶10 पर

आईपीएल 2025 : बेंगलूरु में कब्बन रोड पर रेलिंग से पैदल चलने वालों को असुविधा

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के लिए कब्बन रोड पर फुटपाथ पर लगाई गई रेलिंग से इस सड़क का इस्तेमाल करने वाले पैदल चलने वालों को असुविधा हो रही है। हाल ही में बृहत बेंगलूरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) से अनुमति प्राप्त करने के बाद बेंगलूरु ट्रैफिक पुलिस (बीटीपी) ने रेलिंग लगाई थी। एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल मैचों के दौरान स्टेडियम में प्रवेश करने के लिए कतार में खड़े क्रिकेट प्रेमियों की सुरक्षा के लिए पुलिस ने रेलिंग लगाई थी।

इस सीजन की शुरुआत से लेकर अब तक स्टेडियम में दो आईपीएल मैच हो चुके हैं। मैच देखने वाले लोग सड़क पर न चलें, इसके लिए सड़क के किनारे चलने वाले पूरे फुटपाथ पर रेलिंग लगाई गई है, जिससे यातायात जाम हो सकता है। हालांकि, अब यह आम पैदल चलने वालों, खासकर कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन (एचएएल निकास) से सड़क पार करने वालों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। पैदल चलने वाले अब फुटपाथ पर कदम नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि रेलिंग बाधा बन गई है।

बेंगलूरु में आईपीएल क्रिकेट मैचों के दौरान भीड़ को नियंत्रित करने के लिए चिन्नास्वामी के आसपास फुटपाथ पर रेलिंग लगाई गई। भाग्य प्रकाश जेम्स पी. नामक एक पैदल यात्री ने कहा कि उसे और उसके दोस्तों को घने ट्रैफिक के बीच सड़क के किनारे रेलिंग के साथ सावधानी से चलना पड़ता है। पैदल चलने वालों के सड़क पर आने-जाने वाले वाहनों की चपेट में आने का खतरा रहता है। मेट्रो स्टेशन के पास ऑटो चलाने वाले रमेश ने कहा कि रेलिंग लगाए जाने के बाद कई लोगों को फुटपाथ पर चलने में परेशानी हो रही है। रेलिंग के कारण सड़क पार करने के बाद पैदल चलने वालों के लिए जगह नहीं बचती। बीबीएमपी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बीटीपी ने 8 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट जमा करने के बाद रेलिंग लगाने की अनुमति प्राप्त कर ली है, लेकिन बीबीएमपी को इस बात की जानकारी नहीं है कि इससे पैदल चलने वालों को असुविधा हो रही है। अधिकारी ने कहा कि बीबीएमपी जगह का निरीक्षण करेगी और समस्या को हल करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगी।

कुमारस्वामी ने सरकार पर अत्यधिक कर लगाकर आम आदमी पर बोझ डालने का आरोप लगाया

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। केंद्रीय मंत्री और जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने शनिवार को कर्नाटक सरकार पर अत्यधिक कर लगाकर आम आदमी पर बोझ डालने का आरोप लगाया। कुमारस्वामी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा पिछले दो सालों से राज्य सरकार कई क्षेत्रों में कर लगाकर आम आदमी पर बोझ डाल रही है। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि लोगों को राहत दी जाए। ईंधन और एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा केंद्र सरकार की आलोचना का जवाब देते हुए कुमारस्वामी ने केंद्र के रुख का बचाव किया। उन्होंने कहा कांग्रेस पेट्रोल और एलपीजी गैस की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना कर रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से आम आदमी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कंपनियां इसका बोझ उठा रही हैं।

उन्होंने मौजूदा दरों की तुलना यूपीए सरकार के समय की दरों से भी की। उन्होंने कहा यूपीए सरकार में एलपीजी गैस सिलेंडर 1240 रुपये का था, लेकिन अब 50 रुपये बढ़ाने के बाद भी यह 850 रुपये का है। इस बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राज्य में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा नेताओं में गरिमा और शिष्टाचार की कमी है। सिद्धरामैया ने पूछा कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के लिए कौन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि के लिए भाजपा सीधे तौर पर जिम्मेदार है।

फिजिकल मिशन एंपॉवरमेंट के तृतीय कार्यशाला का अयोजन

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के तत्वावधान में तेरापंथ युवक परिषद राजाजीनगर द्वारा तेरापंथ टास्क फोर्स (टीटीएफ) के हर सिटी टीटीएफ के अंतर्गत फिजिकल मिशन एंपॉवरमेंट के तृतीय कार्यशाला का आयोजन तेरापंथ सभा भवन राजाजीनगर में किया गया।

कार्यक्रम की शुरुआत पंच परमेष्ठि नमस्कार महामंत्र के सामूहिक उच्चारण से हुई। भिक्षु श्रद्धा स्वर टीम द्वारा विजय गीत का संगान किया गया। संस्थापक अध्यक्ष सुनील बाफना द्वारा श्रावक निष्ठा पत्र का वाचन किया गया। तेयुप अध्यक्ष कमलेश चौरड़िया ने फिजिकल मिशन एंपॉवरमेंट कार्यशाला के ट्रेनर जयकुमार चौरड़िया और कार्यशाला में उपस्थित सभी का स्वागत किया और कहा कि ये कार्यशाला हम सभी के लिए बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। जब तक हमें स्वयं को जानकारी नहीं होगी तो हम दूसरों की सहायता भी नहीं कर सकते हैं। तेरापंथ सभा राजाजीनगर के अध्यक्ष अशोक चौधरी ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि कहीं अगर कोई दुर्घटना घट जाए और आप वहां पर उपलब्ध हो और आपको जानकारी हो तो मेडिकल इमर्जेंसी में कैसे आप किसी की जिंदगी बचाने का माध्यम बन सकते हें।

तेरापंथ युवक परिषद द्वारा तीन कार्यशाला का आयोजन किया गया। प्रथम कार्यशाला चन्नपट्टना स्थित बालू पब्लिक स्कूल, द्वितीय कार्यशाला चिकपेट स्थित भेरू गारमेंट्स और तृतीय कार्यशाला का आयोजन स्थानीय भवन में हुआ। कोलकाता से प्रधारे तेरापंथ टास्क फोर्स के ट्रेनर जयकुमार चौरड़िया ने उपस्थित सभी को मेडिकल इमरजेंसी में या दैनिक जीवन में होने वाली आपातकालीन घटनाएं जैसे की जलने के समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। शरीर में चोट लगने पर ब्लीडिंग ज्यादा होने पर हमारे शरीर के किस अंग में कहा- कहा दबाव बनाए रखने से कैसे हम रक्त के प्रवाह को रोक सकते हैं। नाक से खून बहने पर क्या करना चाहिए और फैक्चर हो जाने पर हॉस्पिटलाइज्ड करने से पहले हम कैसे उस मरीज को तुरंत राहत दे सकते हैं, आदि के बारे में विस्तार से बताया। परिषद परिवार की ओर से टीटीएफ के ट्रेनर का जैनपट द्वारा सम्मान किया गया। इस अवसर पर तेरापंथ सभा अध्यक्ष अशोक चौधरी एवं सभा परिवार, तेयुप संस्थापक अध्यक्ष सुनील बाफना, परामर्शक चंद्रेश मांडोत, तेयुप अध्यक्ष कमलेश चौरड़िया एवं तेयुप परिवार एवं श्रावक समाज की अच्छी उपस्थिति रही।

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। *श्री कुवेंपु गलियारा बलेगा वृंदावन नगर द्वारा आयोजित तीसरे वार्षिकोत्सव श्री अन्नम्मा देवी, श्री बंडी महाकाली देवी उत्सव कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि महेंद्र मुणोत ने देवी मां के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। साथ ही जरूरतमंद बच्चों में शिक्षण सामग्री वितरित की। आयोजकों ने मुणोत को सम्मानित किया।*

केंद्रीय मंत्री ने सरकार द्वारा जाति जनगणना रिपोर्ट लागू करने पर अराजकता की चेतावनी दी

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। केंद्रीय रेल और जल शक्ति राज्य मंत्री वी. सोमन्ना ने रविवार को चेतावनी दी कि विवादास्पद जाति जनगणना रिपोर्ट को लागू करने से पूरे कर्नाटक में काफी भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। यहां मीडिया को संबोधित करते हुए मंत्री सोमन्ना ने रिपोर्ट के कार्यान्वयन को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की कड़ी आलोचना की और उन पर जनहित से ज्यादा राजनीतिक अस्तित्व को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। सोमन्ना ने कहा मुझे दुख है कि सीएम सिद्धरामैया इस स्तर तक गिर सकते हैं। अगर वह जाति जनगणना रिपोर्ट को लागू करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो उन्हें इतिहास में खलनायक के रूप में याद किया जाएगा। रिपोर्ट को मनगढ़ंत नाटक बताते हुए सोमन्ना ने कहा कि भाजपा नेता जल्द ही अपनी अगली कार्रवाई तय करने के लिए बैठक करेंगे। उन्होंने कहा यह जाति जनगणना रिपोर्ट एक मनगढ़ंत नाटक लगती है।

भाजपा नेता मिलेंगे और सामूहिक रूप से इस मामले पर भविष्य की कार्रवाई तय करेंगे। उन्होंने आगे दावा किया कि कांग्रेस के 50 से 60 प्रतिशत नेताओं ने निजी तौर पर स्वीकार किया है कि रिपोर्ट में डेटा त्रुटिपूर्ण है। विश्वसनीय डेटा एकत्र करने के लिए सर्वेक्षण ठीक से नहीं किया गया था, और रिपोर्ट में ईमानदारी का अभाव है। सोमन्ना ने इस कदम के समय पर भी सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के पास पहले कार्रवाई करने का पर्याप्त अवसर था। उन्होंने दोहराया भले ही सीएम सिद्धरामैया जानते हैं कि रिपोर्ट में खामियां हैं, फिर भी वे इसे लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पूरे राज्य में भ्रम की स्थिति पैदा होगी। सोमन्ना ने आग्रह किया मैं सीएम सिद्धरामैया से एक नया सर्वेक्षण कराने का अनुरोध करता हूं। वे जिसे चाहें नियुक्त कर सकते हैं और डेढ़ साल के भीतर इसे पूरा कर सकते हैं। उनके कार्यकाल में अभी तीन साल बाकी हैं। केंद्रीय मंत्री ने राजनीतिक परिणामों की चेतावनी देते हुए आगे कहा मैं सीएम को चेतावनी देता हूं कि इस रिपोर्ट को लागू करना उनके राजनीतिक करियर के लिए मौत की सजा साबित हो सकता है। उनके अपने लोगों ने उन्हें नीचे गिराने की साजिश रची है। एकता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा समाज में उच्च या निम्न वर्ग जैसी कोई चीज नहीं है। हमें एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ नहीं खड़ा करना चाहिए। मुख्यमंत्री के साथ अपने पिछले संबंधों को याद करते हुए सोमन्ना ने कहा मैंने कई वर्षों तक उनके साथ मंत्री के रूप में काम किया है। मुझे उनकी वर्तमान स्थिति पर दया आती है। हाल ही में, उन्हें पार्टी हाईकमान ने बुलाया था और नई दिल्ली में निर्देश दिए थे। जाति जनगणना का मामला 2014 से शुरू होता है, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने कर्नाटक सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक जनगणना का आदेश दिया था। तत्कालीन पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एच कांताराजू के नेतृत्व में किए गए इस सर्वेक्षण पर लगभग 169 करोड़ रुपये खर्च हुए और यह 2016 में पूरा हुआ। हालांकि, एच.डी. कुमारस्वामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस-जेडी(एस) गठबंधन और बी.एस. येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली भाजपा सरकारों सहित लगातार सरकारों ने रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया। 2020 में, भाजपा सरकार ने जयप्रकाश हेगड़े को नया आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया, लेकिन निष्कर्षों को सार्वजनिक नहीं किया गया। हेगड़े ने 29 फरवरी, 2024 को सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार को अंतिम रिपोर्ट सौंपी।

अशोक ने सावरकर पर टिप्पणी को लेकर महादेवप्पा की आलोचना की

अंबेडकर की चुनावी हार के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की कर्नाटक इकाई ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर और वीर सावरकर के बारे में राज्य के एक मंत्री की टिप्पणी के बाद कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। पार्टी ने कहा कि अंबेडकर की चुनावी हार के लिए वास्तव में कांग्रेस ही जिम्मेदार है। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के करीबी सामाजिक कल्याण मंत्री एच.सी. महादेवप्पा ने पहले आरोप लगाया था कि वीर सावरकर ने चुनावों में अंबेडकर की हार सुनिश्चित करने के लिए साजिश रची थी। रविवार को तीखी प्रतिक्रिया देते हुए विधानसभा में विपक्ष के नेता आर. अशोक ने कहा यह कांग्रेस पार्टी ही थी जिसने बाबासाहेब अंबेडकर के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा किया था। यह कांग्रेस ही थी जिसने अंबेडकर की हार सुनिश्चित करने के लिए हर संभव रणनीति बनाई थी। यह कांग्रेस ही थी जिसने अंबेडकर को हराने के लिए नारायण सदोबा काजरोलकर को संसाधन मुहैया कराए थे। विडंबना यह है कि यह वही कांग्रेस पार्टी थी जिसने बाद में उन्हें उनकी हार के इनाम के तौर पर पद्म भूषण से सम्मानित किया। अशोक ने आरोप लगाया बाबासाहेब को हराने और उन्हें भारत रत्न देने से इनकार करने के लिए इतनी सारी साजिशें रचने के बाद, अब कांग्रेस का यह दावा करना कि अंबेडकर की चुनावी हार के पीछे वीर सावरकर का हाथ था, बेशर्मी की पराकाष्ठा है। उन्होंने कहा अंबेडकर की व्यापक जीवनी में कहीं भी - यहां तक कि महाराष्ट्र कांग्रेस द्वारा 1974 में प्रकाशित पुस्तक में भी नहीं, और न ही कर्नाटक कांग्रेस द्वारा प्रकाशित खंडों में - वीर सावरकर को इस मामले से जोड़ने का कोई उल्लेख है। अशोक ने कहा कांग्रेस का अंबेडकर के प्रति गहरा आक्रोश और उन्हें दबाने और दरकिनार करने के उनके बार-बार के प्रयास इतिहास में स्पष्ट रूप से दर्ज हैं। उन्होंने कांग्रेस के भीतर सदस्यों द्वारा दिए गए बयानों का भी हवाला देते हुए कहा यहां तक कि आपकी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, जिनमें सीएम सिद्धरामैया के करीबी सहयोगी और पूर्व स्पीकर रमेश कुमार भी शामिल हैं, ने विधानसभा में कांग्रेस द्वारा अंबेडकर के साथ किए गए अन्याय के बारे में बात की है। अंबेडकर के सच्चे अनुयायी कभी भी कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं करेंगे। मंत्री महादेवप्पा, जो एक उत्पीड़ित समुदाय से आते हैं, ने पहले विपक्ष के नेता पर निशाना साधते हुए कहा था, बाबासाहेब अंबेडकर का आजीवन संघर्ष आपके जैसी मानसिकता वाले लोगों के खिलाफ था, जो मनुवाद में निहित हैं। उस विचारधारा के मूल सिद्धांतों के खिलाफ था। ऐसे संदर्भ में, जब आप संविधान के मार्ग को अपनाने के बजाय मनुवाद के मार्ग पर चलते रहते हैं और फिर भी कांग्रेस के खिलाफ झूठा प्रचार करने की कोशिश करते हैं, तो यह मुझे केवल मुस्कुराहट देता है क्योंकि यह आपकी ओर से जागरूकता की कमी को दर्शाता है। बाबासाहेब ने खुद कहा था कि सावरकर उनकी चुनावी हार का कारण थे।

भारी बारिश के बीच एक विशाल जनसभा आयोजित

राज्य में मुसलमानों को खुश करने और हिंदुओं को अपमानित करने की राजनीति: विजयेंद्र

शिवमोग्गा/शुभ लाभ ब्यूरो। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने राज्य की कांग्रेस सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि करने के बाद वह ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां उसके पास सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए भी पैसे नहीं हैं। यहां भारी बारिश के बीच जनाक्रोश यात्रा की विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने मुसलमानों को लुभाने के लिए सरकारी कार्यों में 4 प्रतिशत आरक्षण दिया है। उन्होंने इसे हिंदुओं का अपमान करने वाला कृत्य बताया। मुस्लिम युवा यदि शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो उन्हें 20 लाख की जगह 30 लाख रुपये दिए जाएंगे। क्या आपको हिन्दू नहीं दिखते? उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि हमारे हिंदुओं ने आपके साथ क्या अन्याय किया है? उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की मुसलमानों को खुश करने और हिंदुओं को अपमानित करने की राजनीति करने के लिए आलोचना की। उन्होंने कहा कि भाजपा ने इसके लिए जन आक्रोश अभियान शुरू कर दिया है। दूध के दाम में वृद्धि हुई है, जिससे गरीब लोगों के लिए अपने बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना असंभव हो गया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर एक हाथ से देने और दूसरे हाथ से छीन लेने का आरोप लगाया। उन्होंने आपत्ति जताई कि पिछली भाजपा सरकार के दौरान जहां किसानों को ट्रांसफार्मर लगाने के लिए 25,000 रुपये खर्च करने पड़ते थे, वहीं अब सिद्धरामैया की तथाकथित किसान हितैषी सरकार के सत्ता में आने के बाद किसानों को 2.5 से 3 लाख रुपये तक चुकाने पड़ रहे हैं। उन्होंने शिकायत की कि सिद्धरामैया 38 हजार करोड़ रुपये के एसईटी और टीएसपी फंड का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल दलितों के कल्याण के लिए किया जाना चाहिए था। उन्होंने बताया कि पिछले 10 वर्षों में नरेन्द्र मोदी के प्रभावी शासन के परिणामस्वरूप भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा है। यह लड़ाई चुनाव के लिए नहीं है। राज्य में सत्ता में आई कांग्रेस सरकार जनविरोधी है। यह किसान विरोधी रवैया अपना रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि भाजपा कार्यकर्ताओं में इस हिंदू विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने की ताकत है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ निकाली जा रही जनाक्रोश यात्रा के तहत रमन्ना श्रेष्ठी सर्किल से विरोध मार्च शुरू होकर गोपी सर्किल पहुंचा। इसके बाद एक विशाल विरोध सभा आयोजित की गई। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय संसदीय बोर्ड के सदस्य बी.एस. येदियुरप्पा, सांसद बी.वाई. राघवेंद्र, पूर्व उपमुख्यमंत्री और सांसद गोविंद करजोल, पूर्व मंत्री और विधायक अरगा ज्ञानेंद्र, सांसद कोटा श्रीनिवास पुजारी, प्रदेश उपाध्यक्ष हरतालु हलप्पा, विधायक चन्नबसप्पा, राज्य सचिव और विधान परिषद सदस्य डी.एस. अरुण, विधान परिषद सदस्य भारती शेट्टी, विधान परिषद सदस्य डॉ. धनंजय सरजी, पूर्व विधायक कुमारस्वामी, अशोक नाइक, विधान परिषद के पूर्व सदस्य रुद्रेगौड़ा, जिला पदाधिकारी, मंडल अध्यक्ष एवं पार्टी नेता उपस्थित थे।

कर्नाटक में मुस्लिम आबादी 18.08 प्रतिशत सर्वे में 8 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश?

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा कर्नाटक में कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार को सौंपी गई विवादास्पद जाति जनगणना रिपोर्ट में राज्य में मुस्लिम आबादी 18.08 प्रतिशत बताई गई है और समुदाय के लिए 8 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई है। सूत्रों ने रविवार को इसकी पुष्टि की। वर्तमान में, राज्य में मुसलमानों को 4 प्रतिशत आरक्षण मिल रहा है। जाति जनगणना रिपोर्ट शुक्रवार को राज्य मंत्रिमंडल को सौंपी गई, और राज्य सरकार रिपोर्ट की सिफारिशों पर निर्णय लेने के लिए 17 अप्रैल को एक विशेष कैबिनेट बैठक बुला रही है। हालांकि, रिपोर्ट की सामग्री के बारे में मीडिया को कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। बहरहाल, कैबिनेट बैठक में प्रस्तुत विवरण सार्वजनिक डोमेन में सामने आए हैं। इसके अलावा, सूत्रों ने पुष्टि की कि जाति जनगणना रिपोर्ट में कर्नाटक में कुल आरक्षण को 75 प्रतिशत से अधिक करने की सिफारिश की गई है। सर्वेक्षण में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की आबादी 4.18 करोड़, अनुसूचित जाति (एससी) की 1.09 करोड़ और अनुसूचित जनजाति (एसटी) की 42.81 लाख होने का अनुमान है। सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य की आबादी में ओबीसी समूह की हिस्सेदारी करीब 70 फीसदी है। रिपोर्ट की एक बड़ी सिफारिश ओबीसी के लिए आरक्षण कोटा मौजूदा 31 फीसदी से बढ़ाकर 51 फीसदी करना है। सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में श्रेणी 2बी के तहत मुस्लिम आबादी को 18.08 फीसदी बताया गया है, जिनकी कुल आबादी 75.25 लाख है। रिपोर्ट में उनके आरक्षण को 4 फीसदी से बढ़ाकर 8 फीसदी करने की सिफारिश की गई है। यह वोक्कालिगा समुदाय से ज्यादा है, जिसे वर्तमान में राज्य में दूसरा सबसे बड़ा आबादी वाला समूह माना जाता है। वोक्कालिगा की आबादी 61.68 लाख दर्ज की गई है, जो कुल आबादी का 10.31 फीसदी है। सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में उनके आरक्षण को बढ़ाकर 7 फीसदी करने का सुझाव दिया गया है। जनगणना रिपोर्ट में लिंगायत समुदाय की आबादी 66.35 लाख बताई गई है, जो मुस्लिम आबादी से 11.09 फीसदी कम है। रिपोर्ट में उनके आरक्षण को बढ़ाकर 8 फीसदी करने की सिफारिश की गई है। वर्तमान में लिंगायत समुदाय को राज्य में सबसे बड़ा माना जाता है। अनुसूचित जातियों की जनसंख्या राज्य में सबसे अधिक है। रिपोर्ट में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या 1.09 करोड़ बताई गई है और आरक्षण को 24.1 प्रतिशत पर बनाए रखने की सिफारिश की गई है। अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या 42.81 लाख है और 9.95 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई है। नए बनाए गए श्रेणी 1ए समूह - जिसमें गोल्ला, उप्पारा, मोगावीरा, कोली और अन्य हाशिए के समूह जैसे समुदाय शामिल हैं, की जनसंख्या 73.92 लाख है। सूत्रों के अनुसार, रिपोर्ट में इस समूह के लिए 12 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई है। श्रेणी 2ए, जिसमें मडिवाला, एडिगा और अन्य समुदाय शामिल हैं, की जनसंख्या 77.78 लाख है और 10 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की गई है।

50 प्रतिशत की सीमा को पार कर लिया

रिपोर्ट के निष्कर्षों से राज्य में एक बड़ी बहस और विवाद शुरू होने की उम्मीद है और यह राजनीतिक परिदृश्य को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकता है। गृह मंत्री जी. परमेश्वर और मंत्री जमीर अहमद खान ने निविदाओं में मुस्लिम कोटे का बचाव करते हुए पहले कहा था कि राज्य की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 16 से 18 प्रतिशत है। इस बीच, कांग्रेस नेताओं ने संकेत दिया है कि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार राज्य में आरक्षण की सीमा बढ़ाने के लिए तैयार है। श्रम मंत्री संतोष लाड ने कहा कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करके पहले ही 50 प्रतिशत की सीमा को पार कर लिया है। कांग्रेस एमएलसी बी.के. हरिप्रसाद ने जोर देकर कहा कि जाति जनगणना सरकार को राज्य में आरक्षण की सीमा को 50 प्रतिशत से अधिक बढ़ाने का औचित्य साबित करने के लिए अनुभवजन्य डेटा प्रदान करती है।

शिवकुमार ने पत्नि के साथ घाटी सुब्रमण्य स्वामी की विशेष पूजा-अर्चना की

डोड्डबल्लापुर/शुभ लाभ ब्यूरो। उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार अपनी पत्नी के साथ रविवार सुबह तालुका स्थित ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध श्री घाटी सुब्रह्मण्य स्वामी मंदिर गए और विशेष पूजा-अर्चना की।

ऐतिहासिक करगा शक्रोत्सव और धर्मरायस्वामी करागोत्सव में भाग लेने के बाद, उन्होंने डोड्डबल्लापुर में घाटी क्षेत्र का दौरा किया।

कांतनाकुंटे के निकट युवा कांग्रेस इकाई के अध्यक्ष शरत पाटिल के नेतृत्व में पदाधिकारियों ने शिवकुमार का फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इसके बाद घाटी सुब्रह्मण्य मंदिर में डीसीएम दंपत्ति का मंदिर प्रबंधन द्वारा भव्य स्वागत किया गया तथा भगवान का रुद्राभिषेक, पंचामृताभिषेक एवं विशेष पूजा-अर्चना की गई। राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा हम पवित्र भूमि पर आए हैं। यहां राजनीति पर बात करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्होंने भगवान से इस बार अच्छी बारिश और समृद्ध फसल के लिए प्रार्थना की है।

श्री कृष्ण मठ और रथ बीड़ी पर विवाह-पूर्व और विवाह-पश्चात फोटोशूट प्रतिबंधित

उडुपी/शुभ लाभ ब्यूरो। उडुपी श्री कृष्ण मठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए रथबीड़ी (रथ मार्ग) परिसर में विवाह-पूर्व और विवाह-पश्चात फोटोशूट पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह घोषणा परया पुट्टीगे मठ प्रशासन द्वारा की गई है। इस निर्णय का उद्देश्य विशेष रूप से सुबह के समय और मंदिर परिसर के आसपास स्वामीजी की आवाजाही के दौरान होने वाली असहज स्थितियों को रोकना है। कृष्ण मठ की रथबीड़ी पारंपरिक विरासत संरचनाओं से सुसज्जित है। हालांकि, हाल के दिनों में, विवाह-पूर्व और विवाह-पश्चात फोटोशूट की आड़ में सुबह-सुबह अनुचित व्यवहार देखने को मिला है। मंदिर के अधिकारियों के अनुसार, फोटोशूट के दौरान जोड़ों के अंतरंग क्षणों में शामिल होने के मामले सामने आए हैं, विशेष रूप से केरल और बेंगलूरु से फोटोग्राफरों की आमद के साथ। रथबीड़ी एक पूजनीय मार्ग है, जहां सदियों से अष्ट मठों के पुजारी और भक्त चलते आए हैं। यह धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और यहां रोजाना जुलूस और उत्सव आयोजित किए जाते हैं।

अधिकारियों ने पाया कि फोटोशूट में लगे जोड़ों की मौजूदगी पवित्र माहौल को बाधित कर रही थी। अधिकारियों ने इस बात पर जोर दिया कि रथबीड़ी एक ऐसी जगह है जहां रोजाना धार्मिक अनुष्ठान और सांस्कृतिक प्रथाएं मनाई जाती हैं। ऐसे पवित्र माहौल में रोमांटिक फोटोशूट की अनुमति देना एक बड़ा विरोधाभास पैदा करता है और आसपास के माहौल की पवित्रता को बिगाड़ता है। इस तरह के व्यवधानों की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए, मंदिर प्रशासन ने कहा कि रथबीड़ी की पवित्रता और धार्मिक भावना को बनाए रखने के लिए सख्त कदम उठाना जरूरी हो गया है।

जाति जनगणना रिपोर्ट में अगर कोई खामियां हैं तो उन्हें दूर किया जाएगा: डीके शिवकुमार

बेलगावी/शुभ लाभ ब्यूरो। उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने खुद अभी तक जाति जनगणना रिपोर्ट नहीं देखी है और इसे पढ़ने के बाद ही कोई टिप्पणी करेंगे। हालांकि, उन्होंने कहा कि जल्दबाजी में कोई प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है और अगर कोई खामियां पाई जाती हैं तो उन्हें दूर किया जाएगा।

शिवकुमार ने शनिवार शाम को यहां हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से कहा कि उन्हें जाति जनगणना सर्वेक्षण रिपोर्ट की एक प्रति दी गई है और उन्होंने अभी तक इसे नहीं पढ़ा है। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी करने का वादा किया था, जिससे प्रत्येक समुदाय की प्रगति जानने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा हम भगवान बसवेश्वर के सिद्धांतों का पालन करते हैं। हम रिपोर्ट को देखेंगे। अगर कोई खामियां पाई जाती हैं तो उन्हें दूर किया जाएगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक और विधान परिषद में विपक्ष के नेता चलवाडी नारायणस्वामी द्वारा रिपोर्ट का विरोध करने के बारे में उन्होंने कहा कि उनसे यही उम्मीद की जाती है। उन्होंने कहा मैं उन पर प्रतिक्रिया नहीं दूंगा और भाजपा का प्रवक्ता नहीं बनूंगा, बल्कि अपनी पार्टी का प्रवक्ता बनूंगा। इससे पहले कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष एच. कांताराजू ने कहा था कि समाज कितना स्वस्थ है, इसका आकलन करने के लिए सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण या जनगणना नियमित रूप से की जानी चाहिए। शिवमोग्गा में शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि जब वे आयोग के प्रमुख थे, तब आयोजित सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण समाज के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए एक ऐसा ही अभ्यास था। उन्होंने कहा जाति भारत में एक वास्तविकता है। समानता प्राप्त करने के लिए जाति-आधारित भेदभाव को मिटाया जाना चाहिए। सर्वेक्षण और जनगणना यह समझने के लिए आवश्यक हैं कि समाज में जाति कितनी मजबूत है। उन्होंने सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के लिए राज्य मंत्रिमंडल की सराहना की, जिसे उन्होंने पूरा किया। उन्होंने कहा राज्य मंत्रिमंडल ने रिपोर्ट पर विचार किया है और 17 अप्रैल को होने वाली अगली बैठक में इस पर चर्चा करने का फैसला किया है। मैं इस घटनाक्रम का स्वागत करता हूं। मुझे उम्मीद है कि राज्य सरकार रिपोर्ट के उद्देश्य को पूरा करेगी। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध हैं। इससे पहले, 1931 तक, वार्षिक जनगणना के हिस्से के रूप में जाति विवरण एकत्र किए जाते थे। हालाँकि, हाल के दशकों में व्यापक जाति जनगणना नहीं की गई थी। पहली बार, कर्नाटक सरकार ने 2015 में सर्वेक्षण पूरा किया। सर्वेक्षण व्यापक था और इसमें राज्य के सभी घरों को शामिल किया गया था। गणना करने वालों ने घर-घर जाकर सर्वेक्षण के दौरान बेघर लोगों को भी शामिल किया। शुरुआत में, यह प्रक्रिया 30 दिनों के लिए थी। बाद में, बचे हुए घरों को शामिल करने के लिए इसे और 10 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों से परामर्श करने का अवसर दिया गया था, अगर उनकी गणना नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि सर्वेक्षण सटीक था और पूरी आबादी को कवर करने की कोशिश की गई थी।

किसी का अधिकार छीनने का कोई इरादा नहीं: डॉ. महादेवप्पा

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। समाज कल्याण मंत्री डॉ. एच.सी. महादेवप्पा ने स्पष्ट किया है कि पिछड़ा वर्ग पर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर सरकार का किसी का अधिकार छीनने का कोई इरादा नहीं है। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यदि रिपोर्ट में आरक्षण में संशोधन की सिफारिश की गई है तो इसका अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति में जनसंख्या विस्फोट की तरह बढ़ रही है। इसलिए, सभी को अवसर मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में वैज्ञानिक तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए स्थायी आयोग द्वारा 2015 में लगभग 200 करोड़ रुपये की लागत से एक सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण कराया गया है। इसमें जाति संबंधी जानकारी है। उन्होंने कहा कि यह सर्वेक्षण समाज में बदलाव लाने के लिए किया गया है और सरकार इसे लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के चुनाव घोषणापत्र में देश में जाति जनगणना कराने की बात कही गई थी। भारतीय जनगणना में जातिगत आंकड़े एकत्र करने के प्रयास किये गये। उन्होंने इसमें निहित स्वार्थ का आरोप लगाया। राज्य संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है। उन्होंने कहा कि विभिन्न वर्गों को आरक्षण देने के बारे में चर्चा होनी चाहिए। आजादी से पहले जाति जनगणना हुई थी। आजादी के बाद देश की जनसंख्या 35 करोड़ थी। अब यह 140 करोड़ है। तदनुसार असमानता को समाप्त करने तथा समान समाज बनाने के लिए इस प्रकार का अध्ययन आवश्यक है। केंद्र और राज्य सरकारों को पिछड़े समुदायों के उत्थान के लिए आवश्यक योजनाएं और कार्यक्रम तैयार करने की जरूरत है। पिछड़े वर्गों पर रिपोर्ट न तो समर्थन में है और न ही विरोध में। डेटा वैज्ञानिक तरीके से एकत्र किया गया है। यह बहुत प्रगतिशील रिपोर्ट है। आयोग की रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई हैं। उन्होंने कहा कि जनसंख्या वृद्धि और स्थितियों पर अध्ययन कराया जाएगा। 17 तारीख को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट पर व्यापक चर्चा की जाएगी और निर्णय लिया जाएगा। कुछ समुदाय विरोध व्यक्त कर रहे हैं। वे पुनः सर्वेक्षण की मांग कर रहे हैं। सरकार इन सब पर गौर करेगी।

भाजपा की आलोचना स्वाभाविक है। वह पार्टी सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध नहीं है। पहले जब मंडल रिपोर्ट लागू हुई थी, तब उन्होंने कमंडल लेकर यात्रा निकाली थी। इसलिए उन्होंने कहा कि भाजपा की रिपोर्ट की आलोचना राजनीति से प्रेरित थी। देश में हजारों प्रजातियां हैं। क्या सभी के लिए धन का समान वितरण है? उन्होंने कहा कि सार्वजनिक जीवन में रहने वालों को समान समाज के बारे में सोचना चाहिए और आलोचना को अपना करियर नहीं बनाना चाहिए। इस रिपोर्ट का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। कुछ लोग विज्ञान को जाने बिना ही इसे अवैज्ञानिक बताकर इसकी आलोचना कर रहे हैं। उन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं देखी है। फिर भी, हम आलोचना कैसे कर सकते हैं? यह रिपोर्ट किसी के अधिकार नहीं छीनती है, न ही इसका उद्देश्य किसी और को अधिकार प्रदान करना है। किसी को पीछे छोड़ने या किसी दूसरे को आगे लाने का कोई विचार नहीं है। केवल जब भीड़ उमड़ पड़ती है, तभी हम उनका लाभ उठा सकते हैं और उन लोगों को सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं जिनके पास सुविधाएं नहीं हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल यह सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में कैबिनेट उपसमिति के गठन के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

परिषद की चारों सीटों के लिए कड़ी टक्कर शुरू

बेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो। विधान परिषद की चार रिक्त सीटों पर नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार के समर्थकों के बीच होड़ मची हुई है। हाल ही में दिल्ली और गुजरात में हुई अलग-अलग बैठकों में डीके शिवकुमार और सिद्धरामैया ने आलाकमान के नेताओं को अलग-अलग सूचियां सौंपी थीं। दोनों ने 10-10 सदस्यों की सूची सौंपी है और अपने समर्थकों को मौका दिए जाने की अपील की है। इस बार ओबीसी समुदाय, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और अनुसूचित जाति को एक-एक सीट देने का निर्णय लिया गया है। बी.एल. शंकर का नाम वोक्कालिगा समुदाय से होना लगभग तय था। लेकिन कुछ अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं ने इसका विरोध जताया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी, मुख्यमंत्री सिद्धरामैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने आरोप लगाते हुए कहा कि बी.एल. शंकर की पहचान आरएसएस से है और उनकी नियुक्ति से अल्पसंख्यकों का कांग्रेस पर से भरोसा खत्म हो जाएगा। इस प्रकार, विकल्प के रूप में रघुनंदन रमन्ना का नाम चर्चा में आया है। रमेश बाबू, मालती कृष्णमूर्ति और अन्य के नामों पर चर्चा चल रही है। अल्पसंख्यक समुदाय के कई अन्य लोगों के नाम पर भी चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत सूची की समीक्षा के बाद आलाकमान जल्द ही उम्मीदवारों की अंतिम सूची राज्य को भेजेगा। कई अन्य लोग भी विधान परिषद में नियुक्ति के लिए विभिन्न तरीकों से पैरवी कर रहे हैं।

मैसूरु में सड़क चौड़ीकरण के लिए 40 पेड़ काटे जाने से कार्यकर्ताओं में आक्रोश

मैसूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

मैसूरु में रविवार सुबह उस वक्त शांति भंग हो गई, जब लोगों ने देखा कि रात के अंधेरे में 40 विशाल पेड़ काटे जा रहे हैं, जबकि भारी मिट्टी हटाने वाले उपकरण स्टंप को हटाने के लिए काम कर रहे हैं, जिसे अधिकारियों ने सड़क चौड़ीकरण के लिए जरूरी बताया है। लोग हैरान रह गए और पर्यावरणविदों ने इस घटना के बारे में तब तक कुछ नहीं बताया जब तक कि तस्वीरें सोशल मीडिया पर प्रसारित नहीं होने लगीं।

जब वन विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया गया तो उन्होंने बताया कि मैसूरु सिटी कॉरपोरेशन ने हैदर अली रोड पर कालीकामन मंदिर से एसपी ऑफिस सर्किल तक सड़क चौड़ीकरण के लिए पेड़ों की कटाई की अनुमति मांगी थी। एमसीसी ने 12 फरवरी, 2025 को पेड़ों की कटाई के लिए इस आधार पर अनुमति मांगी थी कि सड़क को 30 मीटर तक चौड़ा किया जाना था और 40 पेड़ इसमें बाधा डाल रहे थे। संपर्क किए जाने पर उप वन संरक्षक डॉ. के.एन. बसवराज ने कहा कि परियोजना की आवश्यकता के आधार पर अनुमति जारी की गई थी, लेकिन एमसीसी को प्रति पेड़ काटे जाने पर 10 पौधे लगाने होंगे, इसलिए प्रतिपूरक वनरोपण के रूप में 400 पौधे लगाए जाएंगे।

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जन सुनवाई तभी बुलाई जाती है, जब काटे जाने वाले पेड़ों की संख्या 50 से अधिक हो, इसलिए इस मामले में नागरिकों से कोई आपत्ति नहीं मांगी गई। वन विभाग के मूल्यांकन और आकलन के अनुसार, पेड़ कम से कम 40 साल पुराने थे। इससे नागरिक भड़क गए हैं और इलाके के एक लंबे समय से रहने वाले निवासी ने कहा कि सड़क पर यातायात की इतनी अधिक मात्रा नहीं है कि उसे चौड़ा किया जा सके, पेड़ों को काटना तो दूर की बात है। उन्होंने कहा कि बस एक ट्रैफिक सिग्नल लगाने या एक ट्रैफिक कांस्टेबल को तैनात करने की आवश्यकता थी क्योंकि यह जगह तीन सड़कों के जंक्शन पर है।

पर्यावरणविद् शैलजेश ने कहा कि प्रतिपूरक पौधा लगाने से यह भ्रम पैदा होता है कि पारिस्थितिकी की रक्षा की जा रही है। लेकिन पारिस्थितिकी को समझने वाला कोई भी व्यक्ति जानता है कि 40 साल पुराना पेड़ एक पौधे की तुलना में कई गुना अधिक कार्बन अवशोषण, छाया, जैव विविधता का समर्थन और सूक्ष्म जलवायु विनियमन प्रदान करता है। अन्य कार्यकर्ताओं ने बताया कि एक पौधे को बढ़ने और समान पारिस्थितिक लाभ प्रदान करने में दशकों लगेंगे, जो काटे गए पौधों के समान हैं, बशर्ते ये पौधे बच जाएँ।

राज्य सरकार ने दशहरा खेल प्रतियोगिता में कंबाला को शामिल करने की घोषणा की

मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार ने शनिवार को घोषणा की कि तटीय कर्नाटक की पारंपरिक भैंस दौड़ कंबाला को इस वर्ष से आधिकारिक तौर पर दशहरा खेल प्रतियोगिता में शामिल किया जाएगा। वे गुरुपुरा कंबालोत्सव के दूसरे संस्करण के समापन समारोह में बोल रहे थे, जो कि केपीसीसी महासचिव इनायत अली के नेतृत्व में गुरुपुरा के मणिबेट्टू गुथु मैदान में आयोजित रात्रिकालीन मुडलूर-अद्दूर जोदुकारे कंबाला कार्यक्रम है।

उन्होंने कहा तटीय क्षेत्र का पारंपरिक खेल कंबाला को संरक्षित किया जाना चाहिए। दुनिया को दक्षिण कन्नड़ के धार्मिक लोकाचार में अपार आस्था है। हार को विनम्रता से स्वीकार करना सीखे बिना कोई सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। इसी तरह कंबाला में भी खेल भावना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस खेल के माध्यम से हमारी परंपराएं और संस्कृति फल-फूल रही हैं। हमारी सरकार इसे प्रोत्साहित करना जारी रखेगी। शिवकुमार ने आगे घोषणा की अगले साल से, कंबाला नाडा हब्बा मैसूरु दशहरा समारोह के दौरान आयोजित होने वाले दशहरा खेल आयोजनों का हिस्सा होगा। यह एक परंपरा बननी चाहिए और पीढ़ियों तक जारी रहनी चाहिए। हमारा लक्ष्य कंबाला को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। आइए हम पार्टी, जाति या पंथ के सभी मतभेदों को दूर करके इस खेल को बढ़ावा दें और उसका समर्थन करें। मैं और सरकार इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। क्षेत्र की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए, शिवकुमार ने कहा दक्षिण कन्नड़ में देश का सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र है। सरकार ने इसका उपयोग करके धार्मिक पर्यटन और सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के उपायों पर पहले ही चर्चा की है। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ, हम तटीय क्षेत्र की समृद्ध संस्कृति को बढ़ावा देने पर भी जोर देंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार हमेशा जिले के लोगों के साथ खड़ी रहेगी और कंबाला के संरक्षण और संवर्धन में पूरा समर्थन देगी, जो तट की अनूठी संस्कृति को दर्शाता है।

मेंगलूरु में अगस्त से समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू होगी: मंत्री मंकल वैद्य

मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देते हुए मत्स्य पालन मंत्री मंकल वैद्य ने घोषणा की कि अगस्त तक मेंगलूरु में एक समर्पित समुद्री एम्बुलेंस सेवा चालू हो जाएगी। इस सेवा के लिए निविदाएं पहले ही जारी की जा चुकी हैं, जिसका उद्देश्य मछुआरों और नाविकों के लिए त्वरित आपातकालीन प्रतिक्रिया और चिकित्सा सहायता को सक्षम बनाना है। मेंगलूरु तटीय अल्पसंख्यक मछुआरों की प्राथमिक सहकारी समिति के तहत एक इकाई बहार-ए-नूर की नई बर्फ संयंत्र सुविधा का उद्घाटन करने के बाद बोलते हुए मंत्री ने तटीय मछली पकड़ने वाले समुदाय के कल्याण के लिए की गई कई पहलों की रूपरेखा बताई। वैद्य ने कहा कि मेंगलूरु मत्स्य पालन बंदरगाह और संबंधित बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के तीसरे चरण के विकास के लिए

80 करोड़ रुपये की निविदा जारी की गई है। उन्होंने यह भी घोषणा की कि बंदरगाह पर ड्रेजिंग का काम जल्द ही शुरू होने वाला है।

मछली पकड़ने के क्षेत्र के लिए सरकारी समर्थन पर प्रकाश डालते हुए, मंत्री ने कहा कि मछुआरों के लिए डीजल कोटा 1.5 लाख लीटर से बढ़ाकर 2 लाख लीटर कर दिया गया है, साथ ही यह सुनिश्चित करने के उपाय किए गए हैं कि पांच महीने की अवधि के भीतर पूरा कोटा इस्तेमाल हो जाए। बहार-ए-नूर के नए भवन का उद्घाटन करने वाले विधानसभा अध्यक्ष यू टी खादर ने कर्नाटक के तटीय क्षेत्र के लिए एक व्यापक मत्स्य पालन नीति की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा आज, समुद्र से अपरिचित लोग भी मछली पकड़ने वाली नौकाओं में निवेश कर रहे हैं। मछली पकड़ने की अच्छी प्रथाओं के साथ-साथ, यह महत्वपूर्ण है कि मछुआरे छोटी मछलियों को पकड़ने जैसी गतिविधियों से बचकर समुद्री संरक्षण में सक्रिय रूप से योगदान दें। खादर ने कहा कि मत्स्य पालन संगठनों को समुद्री संसाधनों की रक्षा करने और मछुआरों के बीच सामुदायिक एकता को बढ़ावा देने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करने में अग्रणी भूमिका निभानी चाहिए। व्यस्त मेंगलूरु मत्स्य बंदरगाह को भीड़भाड़ से मुक्त करने के लिए, कोटेकर में 5 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक छोटी मछली पकड़ने वाली जेटी की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, 200 करोड़ रुपये के निवेश से बोलर और कोटेपुरा को जोड़ने वाले मत्स्य पालन पुल के निर्माण की एक बड़ी परियोजना को मंजूरी मिल गई है। मत्स्य विभाग के निदेशक दिनेश कुमार के ने कहा कि नवनिर्मित बर्फ संयंत्र को मत्स्य संपदा योजना के तहत सहायता देने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि बंदरगाह विकास के तीसरे चरण और अन्य पहलों पर काम जल्द ही शुरू होगा। इस बीच, मेंगलूरु शहर दक्षिण के विधायक वेदव्यास कामथ ने बताया कि सागरमाला परियोजना के तहत ड्रेजिंग कार्यों के लिए नौ बार निविदाएं जारी की गईं, लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होंने यह भी कहा कि हालांकि बंदरगाह विकास के तीसरे चरण को दो साल पहले मंजूरी दी गई थी, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है।

व्यापक ग्रीष्मकालीन वर्षा से मेंगलूरु उडुपी में जल संकट कम हुआ

मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

दक्षिण कन्नड़ (डीके) और उडुपी जिलों के अधिकांश हिस्सों में हाल ही में हुई व्यापक गर्मी की बारिश ने जल-संबंधी चिंताओं को कम करने की उम्मीद जगाई है। पिछले दो हफ्तों से लगातार हो रही बारिश ने उम्मीद जगाई है कि इस गर्मी में पीने के पानी की कमी नहीं होगी। फरवरी में कुछ दिन बारिश हुई, मार्च में सप्ताह भर बारिश हुई और अब अप्रैल की शुरुआत के साथ ही कई इलाकों में अच्छी खासी बारिश हो रही है। पिछले तीन दिनों से क्षेत्र के कई हिस्सों में शाम को भारी बारिश की सूचना मिली है। सुल्लिया, कडाबा और बेल्टांगडी तालुकों के पश्चिमी घाट क्षेत्रों में जिले के अन्य हिस्सों की तुलना में काफी अधिक बारिश हुई है - लगभग चार गुना अधिक। मार्च के आखिरी हफ्ते

से इन इलाकों में रोजाना शाम को बारिश हो रही है। पुत्तूर तालुक में भी संतोषजनक बारिश हुई है, जबकि बंटवाल में रुक-रुक कर भारी बारिश हुई है। मार्च में, मेंगलूरु, पुत्तुर, सुल्लिया, कडाबा, बेल्टांगडी और बंटवाल में संबंधित विधायकों के नेतृत्व में जिला स्तर पर पेयजल आपूर्ति से संबंधित बैठकें आयोजित की गईं। केडीपी बैठकों में जल प्रबंधन के संबंध में एहतियाती उपायों पर चर्चा की गई।

सुल्लिया, पुत्तुर और बेल्टांगडी तालुकों में सुपारी उत्पादक वर्तमान जल उपलब्धता को लेकर राहत व्यक्त कर रहे हैं। सुल्लिया के किसानों को, विशेष रूप से, इस वर्ष बहुत कम बार पंप का उपयोग करना पड़ा है। लगातार गर्मियों की बारिश ने क्षेत्र की नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में मिट्टी की नमी बढ़ा दी है।

यदि बारिश जारी रहती है, तो न केवल नदी के किनारे सूखने से बचेंगे, बल्कि बारिश से थुम्बे बांध में जल स्तर बढ़ाने में भी मदद मिलेगी - जो मेंगलूरु सिटी कॉरपोरेशन को पेयजल आपूर्ति का एक प्रमुख स्रोत है। अधिकारियों ने कई बैठकें की हैं और पेयजल प्रबंधन के संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं। पंचायत विकास अधिकारियों (पीडीओ) को अपने-अपने क्षेत्रों में पानी के मुद्दों को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार बनाया गया है।

सोमन्ना ने मेंगलूरु से सुब्रह्मण्य रोड तक विस्तारित रेल सेवा को हरी झंडी दिखाई

मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

रेल राज्य मंत्री वी सोमन्ना ने शनिवार को मेंगलूरु सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर मेंगलूरु सेंट्रल-कबाका पुत्तुर-सुब्रह्मण्य रोड से विस्तारित यात्री ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाई।

इस अवसर पर बोलते हुए वी सोमन्ना ने कहा मंत्री बनने के बाद मैंने मेंगलूरु का दौरा किया और रेलवे के संबंध में सांसद कैप्टन बृजेश चौटा के साथ बैठक की। मैंने मेंगलूरु सेंट्रल के उन्नयन के लिए संबंधितों को निर्देश भी दिए हैं। मेंगलूरु जंक्शन रेलवे स्टेशन के विकास के लिए 19 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिसमें से 85 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है और संभावित रूप से 25 अगस्त तक काम पूरा हो जाएगा। वी सोमन्ना ने कहा सेंट्रल रेलवे स्टेशन के विकास के लिए मास्टर प्लान

तैयार कर लिया गया है। जल्द ही टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे और दो साल में काम का उद्घाटन किया जाएगा। सुब्रह्मण्य रोड रेलवे स्टेशन का काम भी सितंबर 2025 तक पूरा हो जाएगा। मेंगलूरु सेंट्रल-कबाका पुत्तूर ट्रेन को सुब्रह्मण्य रोड तक विस्तारित करने की लंबे समय से मांग थी और कैप्टन बृजेश चौटा की मांग के अनुसार हम इसे मेमू ट्रेन में बदलने पर काम करेंगे। सांसद कैप्टन बृजेश चौटा ने कहा एक बार सेवा में रही ट्रेन को फिर से शुरू करना हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि यह लंबे समय से लंबित मांग थी। महज छह महीने में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई और आज मंत्री वी सोमन्ना की बदौलत इसे हरी झंडी दिखा दी गई। उन्होंने यह भी मांग की कि विद्युतीकरण पूरा होने के बाद ट्रेन को मेमू ट्रेन में बदल दिया जाए। आने वाले दिनों में ट्रेन की आवृत्ति बढ़ाई जाएगी। उन्होंने कहा यहां तक कि डीपीआर भी एनएचएआई और रेलवे द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया जाएगा ताकि शिरडी घाट पर रेलवे और सड़क समानांतर चले, जो समग्र विकास के लिए अच्छा होगा। यहां तक कि मेंगलूरु सेंट्रल स्टेशन के विकास के लिए जल्द ही टेंडर भी आमंत्रित किया जाएगा। हर तीन या चार महीने में एक बार समन्वय बैठकें आयोजित करने के लिए कुछ अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। स्पीकर यू टी खादर ने कहा मैं मंत्री सोमन्ना और सांसद कैप्टन बृजेश चौटा को सुब्रह्मण्य रोड तक ट्रेन सेवा का विस्तार करने के उनके निरंतर प्रयास के लिए धन्यवाद देता हूं। इससे जिले के समग्र विकास में मदद मिलेगी। सुब्रह्मण्य एक पवित्र स्थान है और यह ट्रेन सेवा अधिक पर्यटकों को इस ट्रेन सेवा का उपयोग करने में मदद करेगी।

विधायक वेदव्यास कामथ ने कहा सुब्रह्मण्य रोड तक रेल सेवा का विस्तार करने की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसे आज हरी झंडी दिखा दी गई है। सांसद कैप्टन बृजेश चौटा को उनके प्रयास के लिए धन्यवाद। आने वाले दिनों में, दो रेलवे स्टेशनों- मेंगलूरु सेंट्रल और कंकनाडी- को 300 से 400 करोड़ रुपये की लागत से अपग्रेड किया जाएगा, जिसका उद्घाटन अगले दो वर्षों में किया जाएगा।

कार दुर्घटना में गांजा बरामद 3 हिरासत में लिए गए

मेंगलूरु/शुभ लाभ ब्यूरो।

दक्षिण कन्नड़ के सुलिया के देवराकोली इलाके में एक कार दुर्घटना में शनिवार शाम को पुलिस निरीक्षण के दौरान गांजा (भांग) बरामद हुआ। यह घटना तब हुई जब पेरियापट्टना से मदिकेरी होते हुए पुत्तुर जा रही एक कार देवराकोली के पास नियंत्रण खो बैठी और पलट गई। स्थानीय निवासी जो कार में सवार लोगों की मदद करने आए थे, उन्होंने वाहन के अंदर संदिग्ध पैकेट देखे और मदिकेरी ग्रामीण पुलिस को सूचित किया।

निरीक्षण करने पर, पुलिस को कार में गांजे के कई पैकेट मिले। उन्होंने पुत्तुर के तीन निवासियों - फजरुद्दीन, मुस्ताक और जाबिर को जब्त प्रतिबंधित पदार्थ के साथ हिरासत में ले लिया है। अधिकारी दुर्घटना और मादक पदार्थ रखने के मामले दोनों की जांच कर रहे हैं। प्रारंभिक रिपोर्टों से पता चलता है कि सवार लोग प्रतिबंधित पदार्थ ले जा रहे थे। जांच जारी रहने के कारण आगे के विवरण की प्रतीक्षा है। पुलिस ने कानून की संबंधित धाराओं के तहत दुर्घटना और मादक पदार्थ रखने के संबंध में अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं।

बिहार के 24 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट, पटना में धूप-छांव का खेल जारी

पटना (एजेंसियां)।

बिहार के कई जिले में रविवार को बारिश का ओरेंट अलर्ट जारी किया गया है। पूर्णिया समेत कुछ जिलों में सुबह तेज बारिश हुई। वहीं पटना समेत कई जिलों में सुबह से ही धूप छांव का खेल जा रही है। ठंडी हवाओं से तापमान में ठंडक का एहसास हुआ। बक्सर और मुजफ्फरपुर में हल्की बारिश देखने को मिली। इधर, मौसम विभाग ने 24 जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। समस्तीपुर, वैशाली, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, जमुई, भागलपुर, बांका, मुंगेर, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, दरभंगा, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार, रोहतास, औरंगाबाद, गया, कैमूर, भोजपुर, बक्सर जिलों में बारिश और वज्रपात का अलर्ट किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि इन जिलों में मध्यम दर्जे की मेघ गर्जन, वज्रपात, और बारिश के आसार है। इन जिलों में हवा की गति 40 से 50 किमी प्रति घंटे

की रफ्तार चलने के आसार हैं।

मौसम विभाग के अनुसार, बंगाल की खाड़ी और पश्चिमी विक्षोभ से अलग-अलग आ रहीं नम हवाओं की टकराहट से मौसम बदल सकता है।

इससे बादल बनते रहेंगे। ऐसे मौसम में गरजने वाले बादल अधिक बनते हैं। पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि बारिश और वज्रापत को लेकर मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिये आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये सुझावों का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में रहें और सुरक्षित रहें। वहीं मौसम विभाग ने लोगों से अपील कि है कि खराब मौसम के दौरान अपने पशुधन और खुद को बाहर निकलने से बचें। मेघगर्जन के दौरान पेड़-पौधे के नीचे शरण न लें। बारिश के समय सुरक्षित स्थान पर जाकर बैठ जाएं।

शासकों के लिए आज भी आदर्श हैं विक्रमादित्य : उपराष्ट्रपति

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (एजेंसियां)। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि महाराजा विक्रमादित्य ने अपने शासन काल में कला संस्कृति, साहित्य और विज्ञान के विकास को संरक्षण और संवर्धन के साथ जो मूल्य स्थापित किए, कालान्तर में वे ही भारत की सांस्कृतिक आदर्श एवं पहचान बने।

उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ शनिवार शाम यहां लाल किला परिसर स्थित माधौदास पार्क में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आयोजित सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य महामंचन के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर मध्यप्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री मोहन यादव, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और केन्द्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी उपस्थित थे।

उपराष्ट्रपति एवं अन्य अतिथियों ने इस तीन दिवसीय सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य महामंचन आयोजन का दीप प्रज्ज्वलन कर शुभारंभ किया। सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य महामंचन 14 अप्रैल तक लगातार जारी रहेगा।

उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ ने कहा कि हमारी संस्कृति एक मिसाल है कि भारतीय जीवन मूल्यों के साथ जीवन कितना सहज और सरल हो सकता है। उन्होंने कहा कि भारतीयता हमारी पहचान है और राष्ट्रवाद हमारा परम धर्म है। सम्राट विक्रमादित्य ने अपने शासनकाल में राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान दिया। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारा देश बदल रहा है। भारत में भूतल की गहराई से आकाश की ऊंचाइयों तक हर तरफ विकास ही विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की दूरदर्शिता से भारत की पुरानी प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित और जीवंत हो रही है। उन्होंने कहा कि भाषा हमारी सांस्कृतिक चेतना की धुरी है। हमें अपनी भाषा पर गर्व करना चाहिए। हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी भारत की सांस्कृतिक चेतना

के प्रसार और भारतीय ज्ञान परम्पराओं पर आधारित शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।

उपराष्ट्रपति ने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली में किए जा रहे इस महा आयोजन के लिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को बधाई और साधुवाद देते हुए कहा कि केंद्र एवं दिल्ली सरकार के साथ मिलकर यह सिलसिला आगे भी जारी रहना चाहिए। हमें हमारी संस्कृति के संवर्धन के लिए हमेशा प्रयास करना चाहिए और उन्हें खुशी है कि मध्यप्रदेश में यह काम बड़ी ही लगन और कुशलता से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखना है और इसे वैश्विक स्तर पर मान्यता दिलाने के भी प्रयास हमें करना चाहिए।

कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिवप्रकाश, उपराष्ट्रपति की धर्मपत्नी डॉ. श्रीमती सुदेश धनखड़, मप्र के प्रमुख सचिव पर्यटन और संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव आनंद विभाग श्री राघवेंद्र कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के संस्कृति सलाहकार डा. श्रीराम तिवारी, डॉ अतुल जैन सहित मध्यप्रदेश एवं दिल्ली सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण तथा विक्रमादित्य महानाट्य महामंचन के 250 से अधिक कलाकारों सहित बड़ी संख्या में मध्यप्रदेश एवं दिल्ली के कलाप्रेमी नागरिकगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सम्राट वीर विक्रमादित्य के शासनकाल को भारतीय इतिहास का गौरवशाली काल बताते हुए कहा कि हमारी संस्कृति को सहेजने और संवारने में विक्रमादित्य का अमिट योगदान है। उन्होंने सिर्फ़ शासन को सुशासन की व्यवस्था में बदला। वे अदम्य साहस, धीरता वीरता और संवेदनशीलता के प्रतीक थे। उन्होंने अपनी प्रजा को कर्जमुक्त किया। वे अनेकानेक गुणों से युक्त थे। गरीबों, लाचारों, वंचितों को उनका हक दिलाने की प्रेरणा हमें सम्राट वीर विक्रमादित्य से ही मिलती है।

उन्होंने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य हमारे लिए सदैव स्तुत्य रहेंगे। उन्होंने हमें जनता की सेवा की सीख दी है। वे अपनी प्रजा का सुख-दुख देखने के लिए भेष बदलकर प्रजा के बीच जाते थे। उनकी यह संवेदनशीलता बताती है कि प्रजा के सुख में ही शासक का सौख्य है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमारी संस्कृति सदैव समृद्ध रही है और आगे भी रहेगी। हमारी संस्कृति मां गंगा की अविरल धारा की तरह लगातार बहती रहेगी। हमें अपने गौरवशाली अतीत पर नाज है और यह भावना हमें नई पीढ़ी तक भी पहुंचानी है। देश की राजधानी दिल्ली में विक्रमादित्य महानाट्य के महामंचन के मूल में हमारी यही मंशा है। उन्होंने सभी से इस आयोजन का लाभ उठाकर अपने इतिहास के गौरवशाली काल को देखने, समझने और आनंद लेने की अपील की।

केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार द्वारा दिल्ली में सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य का आयोजन देश के इतिहास को जीवंत करने के साथ-साथ हमारी सांस्कृतिक चेतना को भी मजबूती प्रदान करता है।

उन्होंने कहा कि सम्राट विक्रमादित्य का शासनकाल भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का उच्चतम समय था। उनके शासन पर आधारित महानाट्य का मंचन विक्रमादित्य के उस स्वर्णिम युग का मंचन है। वे ज्ञान, विज्ञान कौशल के पोषक और वीरता की मिसाल थे। वे आदर्श शासक थे। उन्होंने अपने नवरत्नों के जरिए भारत की संस्कृति को उच्चतम स्तर पर ले जाने का प्रयास किया। वीर विक्रमादित्य के शासनकाल का मंचन एक नई धारा है, एक नया सोपान है, जिसका आगाज मध्यप्रदेश सरकार ने किया है। उन्होंने इस पहल के लिए मुख्यमंत्री डॉ यादव को बधाई और शुभकामनाएं दीं।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार जताया। उन्होंने कहा कि डॉ. यादव ने दिल्ली की जनता को विक्रमादित्य के चरित्र और शौर्य को देखने और समझने का अवसर दिया है। दिल्लीवासियों का परम सौभाग्य है कि आज ये दिन दिल्ली को देखने को मिला। सौभाग्य की बात है कि शौर्य और पराक्रम के प्रतीक सम्राट विक्रमादित्य पर महानाट्य मंचन यहां हो रहा है। दिल्लीवासी आज इतिहास से रुबरू हो रहे हैं। वे सम्राट विक्रमादित्य के चरित्र को अपनी आंखों से देख रहे हैं।

सम्राट विक्रमादित्य महानाट्य महामंचन 13 एवं 14 अप्रैल को भी होगा। इसमें 250 कलाकार सम्राट विक्रमादित्य की जीवन गाथा को जीवंत कर रहे हैं। इस महानाट्य के दृश्यों को सजीव बनाने के लिए पालकी, रथ, घोड़ों और एलईडी ग्राफिक्स के स्पेशल इफेक्ट का प्रयोग किया जा रहा है। कार्यक्रम में महाराजा विक्रमादित्य शोधपीठ द्वारा 'विक्रमादित्यकालीन मुद्रा और मुद्रांक' की प्रदर्शनी भी लगाई जा रही है। भारतीय ऋषि वैज्ञानिक परंपरा पर केंद्रित 'आर्ष भारत' प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है। इसमें 100 से अधिक ऋषियों के जीवन और योगदान को प्रदर्शित किया जा रहा है। जनसम्पर्क विभाग द्वारा 'मध्यप्रदेश का विकास एवं उपलब्धियां' विषय पर और पर्यटन एवं उद्योग विभाग द्वारा भी प्रदर्शनियां भी यहां लगाई गई हैं।

गोयल ने वाइब्रेंट बिल्डकॉन में स्वस्थ विकास के वैश्विक मानक बनाने का किया आह्वान

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (एजेंसियां)। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने रविवार को कैपेक्सिल के वाइब्रेंट बिल्डकॉन 2025 को संबोधित करते हुए उद्योग जगत के हितधारकों से स्थिरता में सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने, आयात निर्भरता को कम करने, स्वच्छ और हरित निर्माण पर ध्यान केंद्रित करने तथा भूकंपरोधी और मॉड्यूलर बुनियादी ढांचे की दिशा में काम करने का आह्वान किया।

श्री गोयल ने निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में भारत की बढ़ती ताकत का उल्लेख करते हुए कहा कि यह ताकत वैश्विक क्षमता केंद्रों (जीसीसी) से लेकर मेक इन इंडिया के तहत घरेलू विनिर्माण के काम में दिख रही है। उन्होंने आवास, बुनियादी ढांचे, वाणिज्यिक अचल संपत्ति, रेलवे, हवाई अड्डों, राजमार्गों और ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, ''सीमेंट और इलेक्ट्रिकल्स से लेकर सुरक्षा प्रणालियों और स्व-चालन तक हर तत्व इस पारिस्थितिकी तंत्र में एक भूमिका निभाता है।

श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में तेजी से बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे विश्व स्तरीय सम्मेलन केंद्रों की परिकल्पना की थी, दोनों ही महामारी के दौरान बनाए गए थे। इन अत्याधुनिक स्थलों ने जी20 शिखर सम्मेलन, भारतटेक्स, भारत मोबिलिटी और स्टार्टअप महाकुंभ जैसे वैश्विक कार्यक्रमों की मेजबानी की है।

श्री गोयल ने कई प्रमुख सरकारी पहलों को सूचीबद्ध किया, जिनमें 20 नए स्मार्ट औद्योगिक शहर, 50 गंतव्यों में बेहतर पर्यटन बुनियादी ढांचा और 100 नए औद्योगिक प्लग-एंड-प्ले हब शामिल हैं। उन्होंने कहा, अगर हमें आज की 4 ट्रिलियन(4 लाख करोड़) डॉलर की अर्थव्यवस्था से 2047 तक 30-35 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना है, तो हर नागरिक को विकसित भारत 2047 में योगदान देना होगा।

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा कि आज भारत एकता के साथ भविष्य की कल्पना कर रहा है, सहयोग को बढ़ावा दे रहा है और एकजुट होकर काम कर रहा है। श्री गोयल ने कहा, वाइब्रेंट बिल्डकॉन हमारे निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को एक साथ लाने की शुरुआत मात्र है।

बैसाखी के अवसर पर उपस्थित लोगों को बधाई देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों की भूमिका के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यवधानों के बावजूद, भारत ने महीने दर महीने निर्बाध खाद्य वितरण सुनिश्चित किया। उन्होंने कहा, ''महामारी के चरम के दौरान भी, भारत ने गरीबों को भोजन उपलब्ध कराने और लाखों लोगों को अभाव से बाहर निकालने के अपने मिशन को जारी रखा।

भारत की खाद्य सुरक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास के बीच संबंध बताते हुए, श्री गोयल ने कहा कि वाइब्रेंट बिल्डकॉन देश की तीव्र शहरीकरण, सभी के लिए आवास और लॉजिस्टिक्स परिवर्तन का समर्थन करने की क्षमता का उदाहरण है। उन्होंने कहा, यह मंच हमारी विनिर्माण और बुनियादी ढांचे की ताकत को दर्शाता है, जो वैश्विक निवेश को आकर्षित करने और लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।

अंत में, श्री गोयल ने वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरने की भारत की क्षमता पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हमें साहसिक लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे श्रम बल को उचित वेतन मिले और निरंतर नवाचार करते रहें। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए - भारत विकास, नवाचार और समावेशी विकास में दुनिया का नेतृत्व करेगा।

फिर विवादों में तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि

जय श्री राम का नारा लगवाने पर पद से हटाने की उठी मांग

चेन्नई, 13 अप्रैल (एजेंसियां)। तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। इस बार उन पर एक कॉलेज कार्यक्रम के दौरान 'जय श्री राम' का नारा लगवाने का आरोप लगा है। इस घटना के बाद शिक्षा विशेषज्ञों के संगठन स्टेट प्लेटफॉर्म फॉर कॉमन स्कूल सिस्टम-तमिलनाडु (एस-पीसीएसएस-टीएन) ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से राज्यपाल को उनके पद से हटाने की मांग की है।

राज्यपाल आरएन रवि 12 अप्रैल को मदुरै में मौजूद एक सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज में बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किए गए थे। वहां एक साहित्यिक प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार देने के लिए राज्यपाल पहुंचे थे। अपने भाषण के दौरान उन्होंने छात्रों से तीन बार 'जय श्री राम' कहने को कहा। बस इसी बात को लेकर विवाद खड़ा हुआ

है।

एसपीसीएसएस-टीएन का कहना है कि राज्यपाल ने इस प्रकार का नारा लगवाकर संविधान की धर्मनिरपेक्षता की भावना का उल्लंघन किया है। संगठन के महासचिव पी.बी. प्रिंस गजेन्द्र बाबू ने कहा कि राज्यपाल का यह कृत्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 (राज्यपाल की शपथ) का उल्लंघन है। उन्होंने कहा, 'भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और शिक्षा भी एक धर्मनिरपेक्ष गतिविधि है। ऐसे में किसी विशेष धर्म के भगवान का नाम लेकर नारा लगवाना न सिर्फ गलत है, बल्कि यह राज्यपाल की संवैधानिक जिम्मेदारियों के खिलाफ भी है।

संविधान के अनुसार, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। हर नागरिक का कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करे, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे।

साथ ही वैज्ञानिक सोच, मानवता, और सुधार की भावना को विकसित करे। राज्यपाल, जो संविधान की रक्षा, संरक्षण और समर्थन की शपथ लेते हैं, उनसे उम्मीद की जाती है कि वे धर्मनिरपेक्षता की भावना का पालन करें और सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण रखें।

संगठन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से अपील की है कि राज्यपाल को तत्काल उनके पद से हटाया जाए क्योंकि उन्होंने अपने संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन किया है। संगठन ने यह भी कहा कि ऐसा कार्य शिक्षा क्षेत्र को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास है, जो स्वीकार नहीं किया जा सकता।

साढ़े तीन साल में मोदी सरकार ने सहकारिता क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया है : अमित

भोपाल, 13 अप्रैल (एजेंसियां)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि देश में सहकारिता आंदोलन में कभी 'अनियमन' की स्थिति थी, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने साढ़े तीन सालों के दौरान सहकारिता के क्षेत्र में बड़ा बदलाव किया है।

श्री शाह ने यहां राज्य स्तरीय सहकारी सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, राज्य के सहकारिता मंत्री विश्वास सारंग और पशुपालन मंत्री लखन पटेल समेत अनेक जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इस मौके पर राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) और मध्यप्रदेश डेयरी फेडरेशन के मध्य समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए, जिसके तहत राज्य में डेयरी क्षेत्र में व्यापक बदलाव लाए जाएंगे।

श्री शाह ने अपने संबोधन में कहा कि एक समय था, जब देश में सहकारिता आंदोलन में अनियमन था। कुछ राज्यों में यह काफी आगे था। कुछ जगह इसका सरकारीकरण हुआ, तो

कुछ जगह पूरी तरह विनाश हुआ। देश में सहकारी आंदोलन बटा हुआ था, इसकी मुख्य वजह यह थी कि कानूनों में समय के साथ बदलाव नहीं किया गया। देश में जिस तेजी से परिस्थितियां बदलीं, उनके अनुरूप कानून नहीं बदले गए। उस समय कभी भी राष्ट्रीय स्तर पर समग्रता के साथ विचार नहीं हुआ।

श्री शाह ने कहा कि लेकिन मोदी सरकार ने देश में 75 साल बाद केंद्रीय सहकारिता विभाग का गठन किया। इसका मंत्री उन्हें (श्री शाह) बनाया गया। उन्होंने मंत्री बनने के बाद सबसे पहले प्राथमिक सहकारी समितियों में सुधार के लिए आदर्श बाय लॉज बनाए और उन्हें सभी राज्यों को भेज दिया। श्री शाह ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि सभी राज्यों ने इन बाय लॉज को लागू कर दिया और इसके साथ ही सहकारिता क्षेत्र में सुधार प्रारंभ हो गया। उन्होंने कहा कि वे सभी राज्यों को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहते हैं।

केंद्रीय सहकारिता मंत्री ने कहा कि इन सुधारों की वजह से अब पैक्स 20 से ज्यादा काम करने लगे हैं और उनकी आय भी बढ़ी है, जबकि एक समय पैक्स केवल अल्पकालीन किसान ऋण से संबंधित कार्य करते थे, जिससे उन्हें सिर्फ आधा प्रतिशत का मुनाफा होता था। अब पैक्स आयुष्मान भारत से जुड़ी सस्ती दवाएं बेच रहा है। जल वितरण का कार्य भी कर रहे हैं। आने वाले समय में ये और अधिक काम करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराए गए 25 हजार करोड़ रुपए के खर्चे से पूरे देश में पैक्स का कंप्यूटरा-इजेशन कर दिया गया है। इस कार्य में मध्यप्रदेश प्रथम स्थान पर रहा।

श्री शाह ने कहा कि मध्यप्रदेश में कृषि, सहकारिता और पशुपालन के क्षेत्र में ढेर सारी संभावनाएं हैं। अब इन्हीं संभावनाओं का दोहन करने का निर्णय लिया गया है। श्री शाह ने बताया कि आज वे यहां पर एनडीडीबी और एमपी फेडरेशन के बीच हुए समझौते के साक्षी बने हैं। मध्यप्रदेश में साढ़े पांच करोड़ लीटर दुग्ध उत्पादन है, जो देश का नौ प्रतिशत है। जबकि सरकारी डेयरियों में इसका एक प्रतिशत से भी कम संग्रहण होता है। उनका कहना है कि किसान जब ओपन मार्केट में दूध बेचने जाता है, तो उसका शोषण होता है। अब किसानों का शोषण रोका जा सकेगा। उन्होंने कहा कि अब प्राथमिक डेयरियों का विस्तार करना है। दुग्ध संग्रहण बढ़ाना है। पशुओं की नस्ल सुधारना है, ताकि दुग्ध उत्पादन बढ़ सके और दूध से जुड़े अन्य उत्पादों का भी उत्पादन हो सके।

केंद्रीय मंत्री ने मध्यप्रदेश से संबंधित अनेक आकड़े प्रस्तुत किए और कहा कि अब शेष 83 प्रतिशत गांवों तक दुग्ध सहकारी संघों के पहुंचने का मार्ग खुल गया है। अब अनुबंध के तहत पांच साल में 50 प्रतिशत गांवों में दुग्ध उत्पादन समितियां बनाने का लक्ष्य है। उन्होंने संबंधित विभागों से आग्रह किया कि इस दौरान दुग्ध गुणवत्ता की जांच और किसानों को हर सप्ताह भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने समझौते के तहत तए किए गए लक्ष्यों के संबंध में कहा कि इनका फिर से निर्धारण किया जाना चाहिए। अब मध्यप्रदेश में सुशासन है, इसलिए और बेहतर लक्ष्य तय करके इन्हें हासिल किया जा सकता है।

इसके पहले अपने संबोधन में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार किसानों की बेहतरी के लिए कार्य कर रही है और इस समझौते से दुग्ध उत्पादक किसानों की आय बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि सरकार दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रयास कर रही है। कार्यक्रम को प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री शर्मा और सहकारिता मंत्री श्री सारंग ने भी संबोधित किया।

केरल को एक नवंबर तक 'अत्यधिक गरीबी मुक्त' राज्य घोषित कर दिया जायेगा: विजयन

कन्नूर, 13 अप्रैल (एजेंसियां)। केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने रविवार को कहा कि प्रदेश को आगामी एक नवंबर तक 'अत्यधिक गरीबी मुक्त' राज्य घोषित कर दिया जायेगा।

श्री विजयन ने आज यहां पिनाराई कन्वेंशन सेंटर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उनके 'धर्मादम विधानसभा क्षेत्र' को केरल के 140 विधानसभा क्षेत्रों में से अत्यधिक गरीबी उन्मूलन वाला पहला क्षेत्र घोषित किया गया है।

यह पहल तीन साल पहले एक व्यापक सरकारी परियोजना के साथ शुरू हुई थी जिसका उद्देश्य पूरे राज्य में अत्यधिक गरीबी को खत्म करना था। इस प्रयास में विभिन्न विभागों, विशेष रूप से स्थानीय स्वशासन संस्थानों द्वारा समन्वित हस्तक्षेप शामिल था, जो एकजुट होकर काम कर रहे थे। उन्होंने कहा , राज्य में हालांकि अत्यधिक गरीबी की दर एक प्रतिशत से कम थी, लेकिन हमने इस चुनौती को गंभीरता से लिया और इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध किया। कुल 64002 व्यक्तियों की पहचान की गयी और उनमें से प्रत्येक के साथ-साथ उनके परिवार के सदस्यों के उत्थान के लिए सूक्ष्म योजनाएं विकसित की गयी।

करणी सेना के अध्यक्ष ने किया सपा को धूल चटाने का आह्वान

तुम्हें राम की सौगंध है, सपा का सफाया करना है

आगरा, 13 अप्रैल (एजेंसियां)। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सदस्य रामजीलाल सुमन द्वारा महावीर राणा सांगा के खिलाफ दिए गए बयान पर करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र राणा ने आने वाले विधानसभा चुनाव में सपा को ध्वस्त करने का क्षत्रियों से आह्वान किया है। उन्होंने अपनी अपील में राम के वंशज क्षत्रियों को राम की सौगंध दिलाते हुए वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को पराजित करने की अपील की। करणी सेना ने सपा सांसद के खिलाफ कल आगरा में रक्त स्वाभिमान सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें पूरे देश से लाखों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया।

रक्त स्वाभिमान सम्मेलन में वक्ताओं ने शूरवीर राणा सांगा के जीवन पर प्रकाश डाला और उन पर बेजा टिप्पणी करने वाले सपा सांसद की भर्त्सना की। डॉ. राज सिंह शेखावत ने कहा कि हम पूर्वजों का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सुमन के माफी मांगने पर भी माफ नहीं करेंगे। इसका बदला लिया जाएगा। उन्होंने क्षत्रियों से कहा कि रामजीलाल सुमन जिस गांव में जाएं, वहां एक भी क्षत्रिय हो तो बदला जरूर लें।

करणी सेना के दिवगंत राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की पत्नी शीला गोगामेड़ी ने कहा कि हमारी रगों में राणा सांगा और महाराणा प्रताप जैसे शूरवीरों का रक्त है। हमारे इतिहास के बारे में जो हाथ उठेगा वह काट दिया जाएगा, जो सिर उठेगा वह भी काटा जाएगा। शाम चार बजे के बाद ओकेंद्र राणा बुलेट से पगड़ी पहनकर फिल्मी अंदाज में सम्मेलन में पहुंचे तो युवाओं ने घेर लिया। किसी तरह मंच तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम राम के वंशज हैं। तुम्हें राम की सौगंध है, सपा का सफाया करना है। उन्होंने कहा कि सांसद पुलिस के घेरे में दुबक गया है।

प्रतापगढ़ के राजा भैया तो सम्मेलन में नहीं पहुंचे मगर उनके जनसत्ता दल के एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह ने कहा कि महापुरुष किसी जाति के नहीं होते हैं। उन्हें जाति बंधन में नहीं बांधना चाहिए। राजा भैया आपके साथ हैं। भाजपा विधायक धर्मपाल ने कुछ बोलने से परहेज किया मगर आयोजक उनके एक इशारे पर सम्मेलन समाप्त करने पर सहमत हो गए। इससे साफ है कि आयोजन के पीछे केवल जयंती मनाना ही नहीं बल्कि राजनीतिक उद्देश्य भी रहा।

वाराणसी गैंग-रेप का मामला

बड़े सेक्स रैकेट का पर्दाफाश

वाराणसी, 13 अप्रैल (एजेंसियां)। वाराणसी में छात्रा से गैंगरेप के मामले ने अब एक बड़े सेक्स रैकेट का रूप ले लिया है। पुलिस ने इस केस में अब तक 12 आरोपितों को गिरफ्तार किया है, जिनके 14 मोबाइल फोन से 546 लड़कियों के न्यूड और आपत्तिजनक वीडियो बरामद हुए हैं। ये वीडियो व्हाट्सएप के जरिए उत्तर प्रदेश समेत महाराष्ट्र, दिल्ली, बिहार, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में शेयर किए गए थे। वहीं, पीड़िता की हालत खराब बताई जा रही है। लगातार नशे की वजह से वो पीलिया की शिकार हो गई है।

रैकेट के सरगना अनमोल गुप्ता (कांटिनेंटल कैफे का मालिक) के कब्जे से दो आईफोन बरामद हुए हैं, जिनमें कैफे के अंदर तैयार किए गए अश्लील वीडियो, आपत्तिजनक तस्वीरें और ग्राहकों का पूरा डेटा मौजूद है। अनमोल गुप्ता इन वीडियो का इस्तेमाल नए ग्राहकों को जोड़ने और पुराने ग्राहकों को बनाए रखने के लिए करता था। पुलिस ने बताया कि अब तक गिरफ्तार 12 में से अधिकांश आरोपी ड्रग एडिक्ट हैं। पूछताछ में पता चला कि इन युवकों को नशे की लत अनमोल गुप्ता ने ही लगवाई। छात्रा ने जिन लड़कों की पहचान की, पुलिस उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। मोबाइल से मिले कंटेंट की फोरेंसिक जांच आगरा की विधि विज्ञान प्रयोगशाला में की जा रही है। छात्रा की हालत अभी भी मानसिक रूप से अस्थिर है। उसे बार-बार ड्रग्स दिया गया था, जिससे उसका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। डॉक्टर की देखरेख में उसका इलाज चल रहा है और पुलिस सुरक्षा में उसे घर भेजा गया है। इस बीच, उसे हेपेटाइटिस-बी की शिकायत हो चुकी है, जिसकी वजह से उसकी हालत बेहद खराब हो गई है।

इस मामले में तीन और आरोपित रेहान, जाहिर और मोहम्मद रजा भी पकड़े गए हैं, जो सीधे अनमोल के कैफे से जुड़े थे। पूछताछ में उन्होंने कबूल किया कि नशे में धुत होकर उन्होंने भी छात्रा के साथ ज्यादती की। जांच में यह भी सामने आया है कि अनमोल का पिता शरद गुप्ता भी पुराना सेक्स रैकेट संचालक है और दोनों पहले भी गिरफ्तार हो चुके हैं। तीन थानों की पुलिस ने बीते 72 घंटों में 41 से अधिक ठिकानों पर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की है। चेतगंज एसीपी गौरव कुमार के नेतृत्व में स्पा सेंटर, कैफे होटल, ड्रिंक हाउस, और हुक्का बार पर छापे मार रही हैं। पुलिस अब तक 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाल चुकी है और जांच लगातार जारी है।

कांग्रेस ने अंबेडकर का अपमान किया: सीएम योगी

कुछ लोग वक्फ के नाम पर भड़का रहे हिंसा

लखनऊ, 13 अप्रैल (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहेब अंबेडकर का अपमान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। सीएम योगी ने कहा कि 1976 में कांग्रेस ने संविधान में संशोधन किया। एक ऐसा शब्द जोड़ा, जिसके खिलाफ बाबा साहब ने खुद तर्क दिए थे। डॉ. अंबेडकर का अंतिम संस्कार बौद्ध रीति-रिवाजों के अनुसार किया गया था। उनका अंतिम संस्कार महाराष्ट्र के मुंबई शहर में चैतन्य भूमि पर हुआ था। लखनऊ में रविवार को बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर सम्मान अभियान के तहत आयोजित कार्यशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस द्वारा बाबा साहेब का अपमान किए जाने की बात कही।

सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस ने अंबेडकर का अंतिम संस्कार दिल्ली में नहीं होने दिया था। इस पुरानी पार्टी ने भारतीय संविधान के निर्माता का स्मारक बनाने से मना कर दिया था। इन्हीं लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हारने दिया। उनके महा परिनिर्वाण के बाद स्मारक भी नहीं बनने दिया। मुख्यमंत्री ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर भी विपक्ष को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वक्फ के नाम पर हजारों एकड़ जमीन कब्जा की गई है। वक्फ के पास उसका कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं है। अब जब कार्रवाई हो रही है तो कुछ लोग हिंसा भड़का रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में घर से घसीटकर तीन हिंदुओं की हत्या कर दी गई। यूपी में आज जो लोग दलित हितैषी होने की बात कहते हैं। इन्हीं के पार्टियों से जुड़े लोगों ने गरीब, वंचितों और दलितों की सबसे ज्यादा जमीनें कब्जा की हैं।

दलित, शोषित और वंचितों के लिए नई उम्मीदों का दौर बना योगी का कार्यकाल

सामाजिक न्याय का बाबा साहब का सपना पूरा कर रही योगी सरकार

लखनऊ, 13 अप्रैल (एजेंसियां)। भारत रत्न बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय के सिद्धांत को प्रेरणापुंज मानकर कार्य कर रही योगी सरकार ने पिछले 8 वर्षों में उत्तर प्रदेश में न केवल 6 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में सफलता प्राप्त की है, वरन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के उत्थान के लिए कई उल्लेखनीय कदम भी उठाए हैं। शिक्षा, रोजगार, आवास और सामाजिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में किए गए प्रयासों ने इन समुदायों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं। दलितों, पिछड़ों और वंचितों के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारकर न केवल इन वर्गों को मुख्यधारा से जोड़ा है, बल्कि उनके आत्मसम्मान और आर्थिक स्वावलंबन को भी बढ़ावा दिया है। सरकार की योजना है कि दलित, शोषित और वंचित परिवारों को ऐसी आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ा जाए, जिससे प्रतिवर्ष कम से कम 1.25 लाख की आमदनी सतत तरीके से हो सके।

बाबा साहब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा को शेरनी का दूध बताया था। उनके कथन की महत्ता को समझते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। शिक्षा से वंचित ऐसे छात्र-छात्राओं की स्कॉलरशिप राशि में वृद्धि को सरकार की बड़ी पहल के रूप में देखा जा रहा है। प्रदेश के गरीब और प्रतिभावान बच्चों को मुफ्त शिक्षा, किताबें, यूनिफॉर्म से लेकर थारू, कोल और मुसहर जैसी जनजातियों के बच्चों के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया, जिससे उनकी पढ़ाई बिना रुकावट जारी रह सके। इसके साथ ही श्रमिकों के बच्चों के व्यवस्थित पठन पाठन के लिए प्रत्येक मंडल में सर्व सुविधायुक्त अटल आवासीय विद्यालय की चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। वहीं इसके अलावा पहले चरण में 57 जनपदों में मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय, उसके बाद सभी 350 तहसीलों में और फिर समस्त 825 विकास खंड में इस तरह के विद्यालयों की स्थापना भी अनुसूचित जाति और जनजाति के बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के द्वार खोलेंगे। यह प्रयास शिक्षा के जरिए सामाजिक समानता की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहा है।

रोजगार के क्षेत्र में योगी सरकार ने एससी एसटी समुदायों के लिए कई योजनाएं शुरू कीं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के तहत युवाओं को उद्योग और सेवा क्षेत्र में 25 लाख तक का ऋण और 25% सब्सिडी दी जा रही है। अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम के माध्यम से छोटे व्यवसाय जैसे दुकान, टेलरिंग, और लॉन्ड्री के लिए ब्याज-मुक्त ऋण और अनुदान दिए गए। बाबा साहब अंबेडकर रोजगार प्रोत्साहन योजना ने गरीब परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की। इन कदमों से हजारों युवाओं को नई राह मिली है। वहीं योगी सरकार ने एससी-एसटी समुदायों के लिए आवास और बुनियादी सुविधाओं पर विशेष जोर दिया। भूमिहीन परिवारों को जमीन का पट्टा और प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान दिए गए।

इसके अलावा 1.86 करोड़ उज्ज्वला गैस कनेक्शन और 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड में इन समुदायों को विशेष प्राथमिकता दी गई। राशन और पेंशन कार्ड से वंचित लोगों योजना का लाभ दिलाने के लिए सरकार के प्रयास को सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के खिलाफ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए योगी सरकार ने कड़े कदम उठाए हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों को 22,500 से 8,25,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता तुरंत दी जाती है। वहीं छुआछूत के खिलाफ नागरिक अधिकार संरक्षण कानून को भी यूपी में प्रभावी ढंग से लागू किया गया। इन कदमों से समाज में डर का माहौल खत्म हुआ और कमजोर वर्गों को सुरक्षा मिली है। इसके साथ ही योगी सरकार ने एससी-एसटी समुदायों की संस्कृति और पहचान को संरक्षित करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। लखनऊ में जनजातीय संग्रहालय के लिए बजट आवंटित किया गया, जो इन समुदायों की विरासत को सहेजेगा। थारू, मुसहर और सहरिया जैसी जनजातियों के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गईं, जिनसे उनका सामाजिक और आर्थिक पुनरुद्धार हुआ। वृद्धाश्रमों में भी एससी-एसटी बुजुर्गों को मुफ्त भोजन और चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही हैं, जिससे उनकी जिंदगी में सम्मान बढ़ा है।

खालसा पंथ के स्थापना दिवस बैसाखी पर सीएम योगी ने दी बधाई

सिखों ने अपने पराक्रम से हमेशा देश और धर्म की रक्षा की: योगी

लखनऊ, 13 अप्रैल (एजेंसियां)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खालसा पंथ के स्थापना दिवस और बैसाखी पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। याहियागंज स्थित गुरुद्वारे में रविवार को आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना कर देश और धर्म की रक्षा का संदेश दिया था। सीएम योगी ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना करने का उद्देश्य था कि सकल जगत में खालसा पंथ जागे, जगे धर्म हिंदू, सकल भंड भाजे। गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब के क्रूर शासन के खिलाफ पंज प्यारों के साथ खालसा पंथ की नींव रखी। मुख्यमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज द्वारा स्थापित खालसा पंथ के 325 वर्षों की गौरवशाली यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि सिख समुदाय ने हर विपरीत परिस्थिति में अपने शौर्य और पराक्रम से देश-धर्म की रक्षा की। उन्होंने गुरु नानक देव जी से शुरू हुई सिख परंपरा को विश्व में अनुपम बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जब एक तरफ क्रूर औरंगजेब का शासन था, अत्याचार की पराकाष्ठा थी, जजियाकर के जरिए हिन्दुओं को पूरी तरह से इस्लाम में बदलने की क्रूर चाल थी, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था और बहन बेटियों की इज्जत पर सरेआम हाथ डाला जा रहा था, उस समय अपने एक लाख शिष्यों के साथ देश और धर्म पर मंडरा रही इस ज्वलंत समस्या के खिलाफ प्रभावी शंखनाथ करने का कार्य दशमेश गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने किया। उन्होंने इसका नाम खालसा रखा। खालसा का मतलब, परमात्मा के विशेष जन, जो पूर्ण निर्मल मन से कार्य कर सकें। उनके उपदेश आज भी हमारे लिए प्रेरणा हैं। केवल सिखों के लिए नहीं बल्कि हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। सीएम योगी ने कहा कि सिख कहीं भी होगा वह बिना झुके बिना डिगे अपने पथ पर आगे बढ़ता है इसीलिए सरदार कहलाता है।

सीएम योगी ने तराई और पंजाब में हो रहे धर्मांतरण की घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने बिना भेदभाव के पंज प्यारे चुने थे। गुरुद्वारों में आज भी हर व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के लंगर मिलता है, फिर भी धर्मांतरण की घटनाएं हो रही हैं। इसे रोकने और इसके कारणों का निवारण करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने पंज प्यारों का जिक्र करते हुए बताया कि लाहौर के दयाराम, दिल्ली के धर्मदास, द्वारका के मोहकम चंद, जगन्नाथ पुरी के हिम्मत राय और बीदर के साहेब चंद के रूप में बिना किसी भेद-भाव के खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। उन्होंने गुरु गोविंद सिंह को शहीद पिता का पुत्र और शहीद पुत्रों का पिता बताते हुए उनके बलिदान को नमन किया। उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बंदे जहां कहीं भी गए हैं, उन्होंने अपने जज्बे, संघर्ष, शौर्य और पराक्रम से अपना लोहा मनवाया है।

मुख्यमंत्री ने तराई क्षेत्र के सिख युवाओं के विदेश पलायन पर भी चिंता जताई और कहा कि सिख समुदाय ने मलेरिया प्रभावित इस क्षेत्र को उपजाऊ बनाया, लेकिन अब इसे और मजबूती देने की जरूरत है। उन्होंने युवाओं से गुरु परंपरा के उपदेशों का पालन कर पुरुषार्थ के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिस पराक्रम और पुरुषार्थ के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी हमें उससे भागना नहीं है। जो भी कौम अपने पुरुषार्थ से डिगेगी उसके सामने संकट आएगा। हमें गुरु परंपरा के साथ उनके उपदेशों का अक्षरश: पालन करना चाहिए।

सीएम ने बताया कि गुरु गोविंद सिंह के चार साहिबजादों की स्मृति में 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस पूरे देश में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से हुई थी, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं जयंती पर उत्तर प्रदेश में भव्य आयोजन की योजना है। राज्य सरकार के स्तर पर क्या क्या कार्यक्रम होने हैं, इसे लेकर प्रदेश की गुरुद्वारा कमेटी को व्यापक रूपरेखा तैयार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, चारों साहिबजादों और सिख योद्धाओं का बलिदान उनके स्वयं के लिए नहीं था, देश और धर्म के लिए था।

बिजली निजीकरण के खिलाफ 16 अप्रैल से चलेगा अभियान

लखनऊ, 13 अप्रैल (एजेंसियां)। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने निजीकरण पर मुख्य सचिव के बयान पर आपत्ति जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि दिल्ली, ओड़ीशा, चंडीगढ़ में निजीकरण सफलता की कहानी नहीं है बल्कि सार्वजनिक संपत्ति की लूट की कहानी है। समिति के संयोजक शैलेंद्र दुबे ने कहा कि निजीकरण के विरोध में 16 अप्रैल से व्यापक जनसंपर्क किया जाएगा। समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि बिजली कर्मचारी किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार हैं लेकिन निजीकरण के नाम पर उत्तर प्रदेश में किसी भी कीमत पर सार्वजनिक संपत्ति की लूट नहीं होने देंगे। ओडिशा के विद्युत नियामक आयोग के पूर्व अध्यक्ष उपेंद्रनाथ बेहरा को बैठक में बताना चाहिए था कि निजीकरण होने के 17 साल बाद ओड़ीशा के विद्युत नियामक आयोग ने वर्ष 2015 में तीनों निजी कंपनियों के लाइसेंस अक्षमता और भारी भ्रष्टाचार के चलते रद्द कर दिए थे। क्या यही सफलता की कहानी है? उन्होंने कहा कि असली सुधार सरकारी क्षेत्र में ही हुआ है। चंडीगढ़ का विद्युत विभाग लगातार मुनाफा कमा रहा था। सालाना मुनाफा लगभग 200 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष का था। करीब 22 हजार करोड़ रुपए की चंडीगढ़ विद्युत विभाग की परिसंपत्तियों को मात्र 871 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। क्या यह सफलता की कहानी है? कुछ ऐसा ही दिल्ली में हुआ। दिल्ली में निजीकरण होने के समय कंपनी में 5431 कर्मचारी थे। एक वर्ष के अंदर ही 1970 कर्मचारियों को जबरन सेवानिवृत्ति दे दी गई। कर्मचारियों का क्लेम भुगतान नहीं किया गया।

संपादकीय

बड़ी कूटनीतिक जीत

लगभग डेढ़ दशक के प्रयासों के बाद, देश को दहला देने वाले मुंबई आतंकी हमले के सूत्रधार रहे पाकिस्तानी मूल के तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण हमारी बड़ी कानूनी व कूटनीतिक जीत है। यह सफलता तब ही पूर्ण मानी जाएगी जब इस साजिश में बड़ी भूमिका निभाने वाले डेविड कोलमैन हेडली का भारत प्रत्यर्पण हो सकेगा। जिसने मुंबई हमले से पूर्व आतंकियों द्वारा निशाने पर लिए गए जगहों की कई बार रेकी करके आतंकी सरगनाओं की मदद की थी। निश्चय की तहव्वुर राणा का भारत लाया जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जांच के बाद मुंबई आतंकी हमले में पाकिस्तान सरकार तथा आईएसआई की भूमिका व पाक स्थित आतंकी संगठनों के खतरनाक मंसूबों का खुलासा हो सकेगा। सही मायनों में यह हमारी खुफिया एजेंसियों की भी कठिन परीक्षा होगी कि इस साजिश की तह तक कैसे पहुंचा जाए। भारतीय खुफिया एजेंसियां से यदि इस बड़ी साजिश की कड़ियां सही तरह से जोड़ पायी तो आतंकवाद की उर्वरा भूमि बने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब किया जा सकेगा। यही वजह है कि 26/11 के दहला देने वाले मुंबई हमले के सूत्रधार तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण करने के रास्ते अवरोध खड़े करने में प्रत्यक्ष-परोक्ष तौर पर पाक समर्थकों द्वारा कोशिशें की गई। वे सारे कानूनी उपाय अपनाए गए जो राणा का प्रत्यर्पण रोक सकते थे। बहरहाल, इस प्रत्यर्पण से उन शहीदों के परिजनों को न्याय मिलने की उम्मीद जगी है, जिनकी इस आतंकी हमले में मृत्यु हुई थी। अब तक उनके परिजनों को इस बात का मलाल था कि सोलह साल बाद भी सभी अपराधियों को सजा नहीं मिली सकी है। साथ ही राणा की पूछताछ से होने वाले खुलासों से आतंकवाद की पाठशाला बने पाकिस्तान को अलग-थलग करने के प्रयासों को भी बल मिलेगा। निश्चित रूप से तहव्वुर राणा के खिलाफ भारतीय कानून व न्याय व्यवस्था के मानकों के अनुरूप ही कार्रवाई होगी। साथ ही अजमल कसाब की तरह उसकी अपनी बात कहने को कानूनी मदद भी दी जाएगी। हालांकि, अब तक पाकिस्तान मुंबई आतंकी हमले में अपना हाथ होने से लगातार इनकार करता रहा है, लेकिन सभी प्राथमिक सूचनाएं और ठोस सबूत पाक की तरफ इशारा करते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वह अपनी धरती पर कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के बड़े गुर्गों को संरक्षण देकर उनका बचाव करता रहा है। ऐसे में हमारी जांच एजेंसियों के अधिकारी तहव्वुर राणा से सख्त पूछताछ से सच्चाई सामने लाने में सक्षम हो सकते हैं। साथ ही ठोस निष्कर्षों के आधार पर पाकिस्तान पर दबाव बना सकता है कि वह अपनी जमीन आतंकवादियों को पालने-पोसने में इस्तेमाल न होने दे। इसके अलावा आतंकी संगठनों पर पर्याप्त दबाव बनाए, ताकि फिर मानवता के खिलाफ मुबई हमले जैसे घटनाक्रम न दोहराए जा सकें। बहरहाल, तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण पाकिस्तान तथा दूसरे देशों में भारत विरोधी गतिविधियां चला रहे लोगों व संगठनों के लिये साफ संदेश गया है कि इंसानियत के दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में कानून की ओट में बच नहीं सकते। साथ ही पाकिस्तान को आईना दिखा दिया गया है जो तहव्वुर राणा को कनाडा का नागरिक बताकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रहा था। निश्चित रूप से इस सफलता में भारत के राजनीतिक व कूटनीतिक प्रयासों की भी बड़ी भूमिका रही है। भारतीय अधिकारियों ने इस दिन के लिये कड़ी मेहनत की। हालांकि, अभी इस रहस्य से पर्दा उठना बाकी है कि अमेरिका ने क्यों अपने नागरिक डेविड कोलमैन हेडली को भारत को सौंपने से परहेज किया। जबकि उसने इस बड़े अपराध में बड़ी भूमिका निभाई थी। हेडली व राणा आतंकी हमले को अंजाम देने वाले आतंकी संगठनों व पाक खुफिया एजेंसियों के संपर्क में लगातार बने रहे थे।

आतंकी हमले के सूत्रधार रहे पाकिस्तानी मूल के तहव्वुर राणा का भारत प्रत्यर्पण हमारी बड़ी कानूनी व कूटनीतिक जीत है। यह सफलता तब ही पूर्ण मानी जाएगी जब इस साजिश में बड़ी भूमिका निभाने वाले डेविड कोलमैन हेडली का भारत प्रत्यर्पण हो सकेगा। जिसने मुंबई हमले से पूर्व आतंकियों द्वारा निशाने पर लिए गए जगहों की कई बार रेकी करके आतंकी सरगनाओं की मदद की थी। निश्चय की तहव्वुर राणा का भारत लाया जाना इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जांच के बाद मुंबई आतंकी हमले में पाकिस्तान सरकार तथा आईएसआई की भूमिका व पाक स्थित आतंकी संगठनों के खतरनाक मंसूबों का खुलासा हो सकेगा। सही मायनों में यह हमारी खुफिया एजेंसियों की भी कठिन परीक्षा होगी कि इस साजिश की तह तक कैसे पहुंचा जाए। भारतीय खुफिया एजेंसियां से यदि इस बड़ी साजिश की कड़ियां सही तरह से जोड़ पायी तो आतंकवाद की उर्वरा भूमि बने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब किया जा सकेगा। यही वजह है कि 26/11 के दहला देने वाले मुंबई हमले के सूत्रधार तहव्वुर राणा को भारत प्रत्यर्पण करने के रास्ते अवरोध खड़े करने में प्रत्यक्ष-परोक्ष तौर पर पाक समर्थकों द्वारा कोशिशें की गई।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कूटनीतिक जीत एवं भारत की कानून की बड़ी सफलता है

राणा के बहाने पाकिस्तान का पूरा आतंकी सच उजागर हो

ललित गर्ग

मुंबई में भीषण, खौफनाक एवं दर्दनाक आतंकी हमले की साजिश रचने और उसे अंजाम देने में सक्रिय रूप से शामिल रहने वाले पाकिस्तान मूल के कनाडाई नागरिक तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाया जाना किसी उपलब्धि से कम नहीं है, यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की कूटनीतिक जीत एवं भारत की कानून की बड़ी सफलता है। लगभग 170 लोगों की दर्दनाक मौत, क्रूरता एवं अमानवीयता का डरावना मंजर एवं देशवासियों की आंखों को गमगीन करने वाले इस आतंकी हमले के मास्टरमाइंड राणा का अमेरिका से प्रत्यर्पण भारत के लिये एक उजली किरण बनकर प्रस्तुत हुई है। 26-11-2008 एक ऐसी डरावनी तारीख है जिसे याद करके देशवासी सिहर जाते हैं। दहशत की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। यह तारीख मुम्बई के पुराने घाव को न केवल कुरेदती है बल्कि टीस भी पैदा करती है कि 150 करोड़ का यह देश अब तक क्यों नहीं राणा का प्रत्यर्पण कराकर उसे दर्दनाक सजा दे पाया। अब राणा के भारत के शिकंजे में आ जाने से 26-11 के घावों पर कुछ मरहम लगेगा क्योंकि मुम्बई एवं देश आज भी जख्मों का हिसाब मांगती है। देर आये दुरस्त आये की कहावत को चरितार्थ करते हुए अब देश का खतरनाक दुश्मन हाथ आ गया है तो उसे ऐसी सजा दी जाये कि न केवल पाकिस्तान, पाकिस्तानी आतंकवादी संगठन एवं दुनिया में आतंक फैलाने वाले सहम जाये कि भविष्य में ऐसी घटना करने का दुस्साहस न कर सके। यह तो तय है कि राणा से पूछताछ में कई राज खुलेंगे, लेकिन यक्ष प्रश्न यह है कि क्या उसे फांसी की सजा देना संभव होगा? भारत सरकार को ऐसे कूटनीतिक एवं साहसिक प्रयत्न करने होंगे, जिससे उसे फांसी की सजा देना संभव हो सके और वह भी कम से कम समय में। मुंबई हमले के दौरान पकड़े गए आतंकी अजमल कसाब को सजा देने में चार साल लग गए थे। इतनी देरी राणा के मामले में नहीं होनी चाहिए। यह ऐसा मामला है, जिस पर देश के साथ दुनिया की भी निगाह होगी। राणा की सजा से ही भारत के न्यायतंत्र की त्वरता एवं तत्परता सामने आयेगी। क्योंकि खूंखार आतंकियों को सजा देने में देरी से आतंक से लड़ने की प्रतिबद्धता पर प्रश्नचिह्न टंकते है। 17 साल बाद आज भी महानगर मुम्बई की वह काली रात एवं गोलियों की गूंज से सब दहल उठते है, सहम जाते हैं। उस दिन

क्रूरता एवं अमानवीयता का डरावना मंजर एवं देशवासियों की आंखों को गमगीन करने वाले इस आतंकी हमले के मास्टरमाइंड राणा का अमेरिका से प्रत्यर्पण भारत के लिये एक उजली किरण बनकर प्रस्तुत हुई है। 26-11-2008 एक ऐसी डरावनी तारीख है जिसे याद करके देशवासी सिहर जाते हैं। दहशत की तस्वीरें आंखों के सामने आ जाती हैं। यह तारीख मुम्बई के पुराने घाव को न केवल कुरेदती है बल्कि टीस भी पैदा करती है कि 150 करोड़ का यह देश अब तक क्यों नहीं राणा का प्रत्यर्पण कराकर उसे दर्दनाक सजा दे पाया।

पाक प्रशिक्षित लश्कर-ए-तैयबा के 10 आतंकवादियों ने एक साथ कई जगहों पर हमला किया। लियो पोल्र्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल से शुरू हुआ मौत का दर्दनाक तांडव ताजमहल होटल में जाकर खत्म हुआ। जिसमें आतंकवाद निरोधक दस्ते यानि एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे, मुम्बई पुलिस के अतिरिक्त आयुक्त अशोक कामटे और पुलिस इंस्पैक्टर विजय सालस्कर शहीद हुए। आतंकवादी कसाब को जिन्दा पकड़ने वाले साहसी सब इंस्पैक्टर तुकाराम को कौन भुला सकता है, जो एक दूसरे आतंकवादी की गोलियों का शिकार होकर भी, जान की बाजी लगाकर कसाब को पकड़ने में सफलता पायी, भले ही इस एकमात्र पाकिस्तानी आतंकवादी कसाब को सजा-ए-मौत दी गई लेकिन इस हमले ने क्रूरता के जो निशान छोड़े वे आज भी मुम्बई में मौजूद हैं, भारत के जन-जन के हृदय पटल पर अंकित है। कौन नहीं जानता कि तहव्वुर राणा ने दाऊद सईद गिलानी यानि डेविड कोलमैन हेडली के साथ मिलकर हमले की साजिश रची थी। डेविड हेडली ने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुम्बई में फर्स्ट वर्ल्ड इमीग्रेशन सर्विसिज के नाम से एक कम्पनी का कार्यालय खोला और खुद को बिजनेसमैन के रूप में पेश किया। धीरे-धीरे उसने फिल्म जगत में नामी-गिरामी हस्तियों से जान-पहचान बढ़ाई। भारत यात्रा के दौरान उसने मुम्बई एवं देश के अन्य हिस्सों की रेकी की जहां पर हमला किया जाना था। पाकिस्तानी पिता और अमरीकी माँ की औलाद हेडली अमरीका में एक समय रंगीन ज़िन्दगी गुज़ार चुका था जिसके दौरान ड्रग्स की तस्करी के लिए उसे जेल भी हुई थी। भारत ने हेडली के प्रत्यर्पण के लिए भी अनुरोध किया था, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने उसे छोड़ने से इनकार कर दिया, क्योंकि कई मामलों और डेनमार्क में एक हमले की नाकाम साजिश सहित 12 आतंकवाद से संबंधित आरोपों में दोषी होने की बात स्वीकार की थी। उसने लश्कर, आईएसआई और अलकायदा के राज अमेरिका को बताए तब से ही हेडली अमेरिका की सम्पत्ति बन गया है। फिलहाल हेडली का अमेरिका में सुरक्षित रहना बड़े सवाल खड़े करता है। इस बीच भारत ने राणा को मोस्ट वॉन्टेड घोषित कर दिया और 28 अगस्त 2018 भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचने, युद्ध छेड़ने, हत्या, जालसाजी और आतंकवादी हमले के आरोपों पर गिरफ्तारी वारंट जारी किया। अब सवाल यह है कि अमेरिका ने राणा को तो भारत के हवाले कर दिया लेकिन वह डेविड हेडली के मामले में क्यों खामोश है? राणा को भारत लाया जाना, भारत के शिकंजे में आना भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत है। राणा पाकिस्तानी सेना का पूर्व अधिकारी है। चूंकि उसने आतंकी संगठन लश्कर एवं पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आइएसआइ से मिलकर मुंबई हमले की साजिश रची थी, इसलिए उससे गहन पूछताछ करके पाकिस्तान को नए सिरे से न केवल बेनकाब करना होगा, बल्कि उस पर इसके लिए दबाव भी बनाना होगा कि वह मुंबई हमले के अन्य गुनहगारों को भी दंडित करे। इस हमले के गुनहगार पाकिस्तान में खुले घूम रहे हैं। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण संधि के तहत राणा को भारत भेजने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। हालांकि राणा ने कई हथकंडे अपनाए लेकिन अमेरिकी अदालतों में उसकी सारी याचिकाएं ठुकरा दी गईं। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत की यह आज तक की सबसे बड़ी जीत है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, विदेश मंत्री एस. जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल इसके लिए कूटनीतिक प्रयास करते रहे हैं। सर्वविदित है कि भारत विश्व के सर्वाधिक पाकिस्तान पोषित आतंकवाद प्रभावित देशों में से एक है। 26-11 के मुंबई हमलों के अलावा 2008 में ही जयपुर विस्फोट, काबुल में भारतीय दूतावास के अलावा अहमदाबाद, दिल्ली और असम के विस्फोट भी शामिल थे। यह संतोषजनक तो है कि अमेरिका ने देर से सही, राणा को भारत को सौंप दिया। यदि ट्रंप फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं बनते तो शायद राणा को भारत लाना और मुश्किल होता।

दृष्टि कोण

अब ओबीसी पर ध्यान केंद्रित करने की रणनीति

कांग्रेस के सामने लक्ष्य स्पष्ट हैं कि उसे अपने खोये जनाधार को पाने के लिए खासी मशक्कत करनी है। उसे जहां बीजेपी के सामने सबसे बड़ा विकल्प बना रहना है। वहीं उसे अपने जनाधार के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संघर्ष उन दलों से भी करना है जो उसके साथ अभी इंडिया गठबंधन में खड़े दिखते हैं। ये सारा खेल उस सियासी समीकरण का है जिसमें कांग्रेस अपनी दमदार उपस्थिति दिखाने की जद्दोजहद में जुटी है। इसी दायरे में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस से ओबीसी के छिटकने की बात कही। आजादी के बाद से कांग्रेस की सियासी रणनीति में उच्च जातियों, मुस्लिम और दलितों का ऐसा समीकरण रहा जिसका तोड़ विपक्ष के पास लंबे समय तक नहीं रहा। जनसंघ या तमाम समाजवादी दलों की सियासत मंचों पर तो मुखर रही लेकिन राजनीति के जोड़-घटाने में लगभग डेढ़ दशक तक ये पार्टियां लोकसभा या राज्यों के चुनाव में अंकों की तालिका में बस अपनी उपस्थिति ही जताती रहीं। साठ के दशक के अंत और सत्तर के दशक के शुरुआत में राजनीति के उथल पुथल के दौर में कई बदलाव देखने को मिले। कांग्रेस में खुलकर गुटबाजी और राजनीतिक पैंतरेबाजी देखने को मिली। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कुशल नेतृत्व ने उस समय की स्थितियों को संभाल लिया। उनके नेतृत्व वाले धड़े को ही असली कांग्रेस के रूप में स्वीकार कर लिया गया। लेकिन कांग्रेस का जनाधार पहली बार यहीं से खिसकना शुरू हुआ था। इसी के चलते यूपी, बिहार जैसे राज्यों में विपक्ष की सरकारें बनीं। हालांकि, 71 के युद्ध के बाद इंदिरा गांधी के करिश्माई नेतृत्व से फिर से कांग्रेस को एक बड़ा आधार मिला। अगर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव परिणामों को छोड़ दें, तो उसके बाद कांग्रेस अपने जनाधार को वापस पाने के लिए लगातार जूझती रही है। 90 के दशक में कांग्रेस के लिए यह लड़ाई और कठिन हो गई। मंडल-कमंडल के बीच कांग्रेस का गलियारा छोटा हो गया। पूर्व पीएम वीपी सिंह ने ठंडे बस्ते में पड़ी मंडल आयोग की सिफारिश लागू की और ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू हुआ। तब भविष्य की राजनीति की थाह न ले कांग्रेस ने इसका विरोध किया। कांग्रेस ने अपनी सियासी रणनीतियों में जिन जातियों को फोकस किया उसमें पिछड़ी जातियां नहीं थीं। लेकिन फिर भी कांग्रेस के प्रभामंडल में पिछड़ी जातियों के वोट कांग्रेस को पड़ते रहे।

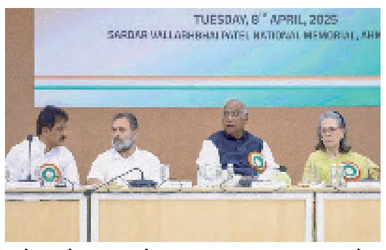

उसके लिए इन जातियों को अपने साथ जोड़ने की पहल बहुत ज्यादा नहीं हुई। दूसरी तरफ इसी दौर में यूपी में सपा, बिहार में आरजेडी, ओडिशा में बीजू जनता दल, कर्नाटक में जनता दल यू जैसे दल उभरे और अपनी पृष्ठभूमि में सशक्त हुए। राजनीति की बयार को समझने वाले कांशीराम ने 1984 में बसपा को स्थापित किया तो उनके अपने लक्ष्य स्पष्ट थे। ज्यादा वक्त नहीं लगा। एक दशक से भी कम समय में यूपी में सपा-बसपा का एक मजबूत चक्रव्यूह तैयार हुआ। इसी बारीक सियासी पेंच को समझना होगा कि जहां पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां सपा आरजेडी जैसे दलों के साथ जुड़ गईं, वहीं बाबरी मस्जिद ढहने के बाद मुस्लिमों ने कांग्रेस से किनारा कर दिया। कांग्रेस आज तक अपने जनाधार की कोशिश में है। दूसरी तरफ राममंदिर आंदोलन ने बीजेपी के लिए सत्ता का रास्ता बनाया। इसके साथ ही सामाजिक समीकरणों में बीजेपी ने पिछड़ी जातियों और दलितों के बीच उन समूहों को साधने की कोशिश की जो अपने को कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे थे। खासकर 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीजेपी ने ओबीसी को प्रभाव में लाने के लिए जतन किए। यही नहीं बीजेपी ने अपनी बिसात बिछाते हुए हरियाणा मध्यप्रदेश जैसे राज्यों में ओबीसी मुख्यमंत्री दिए वहीं ओडिशा में आदिवासी समाज के नेता को नेतृत्व सौंपा। इसी ओबीसी की पिच पर कांग्रेस अब बीजेपी और दूसरे दलों से जूझना चाहती है। कांग्रेस के अधिवेशन से ठीक पहले राहुल गांधी के इस बयान के अपने मायने हैं कि हम ब्राह्मण, दलित मुस्लिम में ही उलझ गए ओबीसी हमसे दूर हो गया। कांग्रेस अब महसूस कर रही है कि तमाम कोशिशों के बाद भी वह सपा व आरजेडी जैसे तमाम दलों से अल्पसंख्यकों के आधार को छीन नहीं पा रही है।

कुछ अलग

सस्ते लोन की आस

अमेरिका के टैरिफ युद्ध से उपजी वैश्विक आर्थिक अस्थिरता के बीच केंद्रीय बैंक ने सावधानी के फैसले लेने शुरू कर दिए हैं। शेयर बाजारों के ध्वस्त होने के बाद आर्थिक मंदी की आहट अमेरिका समेत पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। वैश्विक प्रतिकूलताओं के बीच केंद्रीय बैंक द्वारा हाल ही में दूसरी बार रेपो दर में 25 आधार अंक की कटौती अनिश्चितता के बीच सावधानी का ही संकेत है। केंद्रीय बैंक ने अब रेपो दर 6.25 से घटाकर 6 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है। इस साल यह दूसरी बार कटौती है। जबकि पहली कटौती पांच साल बाद की गई थी। यह कदम वैश्विक अस्थिरता के प्रति रिजर्व बैंक की चिंता को ही दर्शाता है। निश्चित रूप से आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा के नेतृत्व में मौद्रिक नीति समिति द्वारा समायोजन के साथ बदलती प्राथमिकताओं का संकेत दिया है। अब बैंक की प्राथमिकता मुद्रास्फीति के बजाय विकास को गति देना है। निर्विवाद रूप से केंद्रीय बैंक ने यह कदम ऐसे समय पर उठाया है जब संयुक्त राज्य अमेरिका से उपजे व्यापार तनाव और टैरिफ संकट के बीच आर्थिक अनिश्चितता बढ़ रही है। ये हालात घरेलू स्तर पर खपत में कमी करके मंदी की आशंका बढ़ा सकते हैं। साथ ही विकास में निजी निवेश की संभावनाओं पर भी भारी पड़ सकते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक ने देश के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के पूर्वानुमान को संशोधित करके 6.5 फीसदी कर दिया है। जो आने वाली आर्थिक चुनौतियों के मद्देनजर पैदा होने वाली चिंताओं को ही रेखांकित करता है। निश्चित रूप से यह फैसला आवास और ऑटो ऋण ले चुके लोगों के लिये राहत भरी खबर है क्योंकि रेपो रेट घटने पर ऋण लेने वालों की ईएमआई घट सकती है। साथ ही यह कदम नये ऋण लेने वाले लोगों को भी प्रोत्साहित करेगा। इससे रियल एस्टेट सेक्टर को गति मिलने की संभावना भी बढ़ गई है। हालांकि, उन लोगों को कुछ निराशा हो सकती है जो बैंकों में सावधि जमा राशि के जरिये जीवनयापन करते हैं। ऐसे में ब्याज दरों में गिरावट से उनका वास्तविक रिटर्न कम हो सकता है। फलतः निवेश को प्रोत्साहन देने के लिये नई रणनीति बनाने की जरूरत है। निस्संदेह, रेपो दरों में कटौती मौद्रिक अनुशासन का एक जरूरी उपकरण है, लेकिन ये अंतिम रामबाण उपचार भी नहीं है। इसके साथ ही केंद्रीय बैंक को मुद्रास्फीति के दबाव व मुद्रा अस्थिरता के प्रति भी सतर्क रहना चाहिए। जिससे महंगाई बने रहने की चिंता भी पैदा हो सकती है। जरूरी है कि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दरों में की गई कटौती का लाभ बैंक यथाशीघ्र अपने ऋण लेने वाले ग्राहकों को प्रदान करें। बहरहाल, दरों की यह कटौती केंद्रीय बैंक की विकास को गति देने की मंशा को ही जाहिर करती है। लेकिन यह कदम तभी प्रभावकारी हो सकता है जब राजकोषीय उपायों और संरचनात्मक सुधारों को गति प्रदान की जाए। बहरहाल, आम आदमी के लिये यह सुखद है कि उसकी ईएमआई कम हो जाएगी। साथ ही नये लोन भी सस्ते होंगे। जिससे हाउसिंग क्षेत्र में डिमांड बढ़ेगी। साथ ही लोग रियल एस्टेट में अधिक निवेश कर सकेंगे। निश्चित रूप से इस कदम से रियल एस्टेट सेक्टर को नई ताकत मिलेगी। वहीं उद्योग जगत ने भी केंद्रीय बैंक के फैसले का स्वागत किया है। उद्योग जगत लंबे समय से ब्याज दरों में कटौती की मांग करता रहा है, जबकि केंद्रीय बैंक की प्राथमिकता मुद्रास्फीति पर नियंत्रण की बनी रही थी।

देश दुनिया से

संघीय कशमकश और तमिल राजनीति

विधानमंडल से पास हुए विधेयकों को रोकने की शक्ति को लेकर 2023 में, पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि राज्यपाल निर्वाचित विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर समयबद्ध तरीके से कार्य करने के लिए बाध्य हैं। अदालत के इस बार के फैसले ने उस समयबद्धता को परिभाषित भी कर दिया है। इससे विधानमंडल से पास हुए विधेयकों के बारे में राज्यपालों का विशेषाधिकार सीमित हो गया है। इस निर्णय का महत्व तमिलनाडु के राज्यपाल की निंदा से कहीं अधिक है। राज्यपाल अब जांच के बहाने कानून को अनिश्चितकाल तक विलंबित नहीं कर सकते। न्यायालय ने एक संवैधानिक सिद्धांत की पुष्टि की है कि राजभवनों को पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम करना चाहिए। अब सिद्धांत यह बना है कि किसी विधेयक को जब विधानमंडल दुबारा राज्यपाल के पास भेजें, तब उसे स्वीकृति दे दी जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को 'शीघ्रता से काम करना चाहिए' और किसी विधेयक को अनिश्चितकाल तक रोककर वे 'पॉकेट वीटो' का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अनुच्छेद 200 को अनुच्छेद 163 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो राज्यपाल को कैबिनेट की सलाह पर काम करने के लिए बाध्य करता है। यदि कैबिनेट की सलाह के विपरीत राज्यपाल किसी विधेयक को मंजूरी नहीं देते हैं या उसे सुरक्षित रखते हैं, तो उन्हें ऐसा तीन महीने के भीतर करना होगा। दोबारा पारित विधेयकों के लिए समय-सीमा घटाकर एक महीना कर दी गई है। राज्यपालों के मामले में भारत का अनुभव निराशाजनक रहा है। इस पद का दुरुपयोग लगभग सभी ताकतों ने अलग-अलग वक्त पर किया है। दिल्ली में जिसकी सरकार रही उसने राज्य सरकारों को बर्खास्त करने में राज्यपालों का सहारा लिया। दशकों से देश राज्यपालों की भूमिका को लेकर विमर्श कर रहा है, पर रास्ता अभी तक नहीं निकला है। हां, इतना जरूर हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के बोम्मई मामले में फैसले के बाद राज्यों में सरकारों की बर्खास्तगी का चलन खत्म हो गया और सरकारों के बनने-बिगड़ने का स्वीकृत सिद्धांत बन गया। इस बार के फैसले से राज्यों की प्रशासनिक स्वायत्तता बढ़ेगी और संवैधानिक पदों का कामकाज नियंत्रित होगा, जिसका प्रभाव पूरे देश पर पड़ेगा। यह न्यायिक-हस्तक्षेप ऐसे समय में हुआ है, जब गैर-भाजपा दलों द्वारा शासित राज्यों में राज्यपालों और सरकारों के बीच तनाव चरम पर है। इस संवैधानिक सफलता का राजनीतिक श्रेय एमके स्टालिन की डीएमके सरकार को जाता है, पर वहीं मेडिकल प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा 'नीट' से छूट हासिल करने में तमिलनाडु सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। इस मामले को लेकर भी वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, पर यह मामला उतना सरल नहीं है, जितना राज्यपालों के विशेषाधिकार का है। इस दौरान 'नीट' को लेकर कई तरह की शिकायतें सामने आई हैं, पर उच्चतम न्यायालय ने उसे लगातार बरकरार रखा है। राज्य सरकार ने इसे प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लिया है, पर संवैधानिक-व्यवस्थाएं उसके पक्ष में नहीं हैं। पिछले कुछ महीनों में तमिलनाडु सरकार ने तीन भाषा सूत्र, चुनाव-क्षेत्र परिसीमन और नीट परीक्षा जैसे मसलों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तीनों मामलों के कारण राजनीतिक-कोलाहल तो हुआ है, पर बुनियादी तौर पर कुछ हुआ नहीं है। यह सब अगले साल होने वाले राज्य विधानसभा के चुनाव की पूर्व-पीठिका तैयार कर रहे हैं। बुधवार को एमके स्टालिन की अध्यक्षता में विधायक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया कि तमिलनाडु सरकार चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 'नीट' से राज्य को छूट दिलाने के लिए अपना कानूनी संघर्ष जारी रखेगी। 'नीट' के खिलाफ राज्य सरकार द्वारा 2023 में सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका के माध्यम से अपने प्रयासों को तेज करने के अलावा, आवश्यक हो तो एक नया मामला दायर करने के बारे में भी विधि-विशेषज्ञों से परामर्श किया जाएगा। पिछले हफ्ते ही खबर आई थी कि राष्ट्रपति ने 'तमिलनाडु अंडरग्रेजुएट मेडिकल डिग्री कोर्सेस बिल, 2021' को मंजूरी नहीं दी, जिसके बाद, मुख्यमंत्री ने विधायक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक बुलाई थी। तमिलनाडु का यह विधेयक सितंबर, 2021 में विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित किया गया था। राज्यपाल द्वारा विधेयक लौटाए जाने के बाद फरवरी,

2022 में एक सर्वदलीय बैठक आयोजित की गई थी। इसके बाद विधेयक को विधानसभा में फिर से पारित किया गया और राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया। केंद्र सरकार की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति ने इस विधेयक पर मंजूरी रोक दी। शुक्रवार 4 अप्रैल को विधानसभा में इसकी घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री स्टालिन ने केंद्र सरकार पर राज्य द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, 'नीट'की शुरुआत के बाद, ग्रामीण और वंचित छात्रों के लिए मेडिकल कोर्स करना मुश्किल हो गया है, जो कोचिंग क्लास का खर्च नहीं उठा सकते। यह प्रणाली भविष्य में राज्य के ग्रामीण और अविकसित क्षेत्रों में प्रदान की जाने वाली चिकित्सा सेवाओं को भी प्रभावित करेगी। 'नीट' को शहरी छात्रों के पक्ष में बनाया गया है, जो कोचिंग क्लास का खर्च उठा सकते हैं। यह सामाजिक न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है। डीएमके की दीर्घकालीन राजनीति में केंद्र से प्रतिस्पर्धा एक महत्वपूर्ण कारक है। 'नीट' से छूट हासिल करना राज्य के दशकों पुराने नीतिगत विमर्श का फिलहाल अनिर्णीत अध्याय है। केंद्रीय नीति के खिलाफ राज्य का कानून बनाने का इतना लंबा कोई अन्य प्रयास नहीं रहा है। सितंबर, 2017 में, 'नीट' विरोधी दो विधेयकों का राष्ट्र पति भवन में यही हश्र हुआ। चार साल बाद, सत्तारूढ़ डीएमके ने, जिसने 'नीट' से छूट को अपना चुनावी वादा बनाया था, जस्टिस एके रंजन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर विधानसभा में विधेयक पारित किया। राष्ट्र पति की स्वीकृति के लिए इसे आगे बढ़ाने के बजाय राज्यपाल आरएन रवि ने पहले इसे पांच महीने बाद सदन को लौटा दिया।

आप का नजरिया

झूठा आश्वासन

वक्फ कानून बनाने के बाद से ही पामि बंगाल में बवाल मचा हुआ है। लेकिन शनिवार को पामि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनजा ने एक सही सवाल पूछा कि जब यह कानून राज्य में लागू ही नहीं होगा फिर हिसा क्यों हो रही है? उन्होंने राज्य वासियों से शांति बनाए रखने की अपील की। दरअसल राज्य में शांति कायम करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनजा ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स के एक पोस्ट में लिखा, ''जिस कानून की बात हो रही है, वह वेंद्र सरकार ने बनाया है, राज्य सरकार से इसका कोईं लेना देना नहीं है। हमने कानून का समर्थन नहीं किया और यह राज्य में यह लागू नहीं होगा।'' मजे की बात तो यह है कि मुख्यमंत्री, राज्य के पुलिस महानिदेशक राजीव वुमार और कानून व्यवस्था के एडीजी जावेद शमीम ने स्पष्ट रूप से कहा कि वुछ पार्टियां मुसलमानों को भड़का रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाईं हो रही है। सच तो यह है कि मुख्यमंत्री और उनके शीर्ष पुलिस अधिकारियों का यह आरोप बिल्वुल सही है कि वुछ लोग मुस्लिम समाज को वक्फ विधेयक के खिलाफ भड़का तो रहे हैं। किन्तु उनका यह कहना कि वक्फ विधेयक वेंद्र ने बनाया है इसलिए वह राज्य में लागू नहीं होगा, शत प्रातिशत असत्य है। आश्वासन देने का तरीका सही हो सकता है किन्तु शासन द्वारा झूठ बोलकर एक पूरी कौम को भ्रमित करना भी राज धर्म के विरुद्ध है। असल में पामि बंगाल सरकार कांग्रोस और वामपंथी पार्टियों पर इस बात का आरोप लगा रही हैं कि वे मुसलमानों को वक्फ विधेयक के खिलाफ भड़का रही हैं। मुख्यमंत्री और उनके शासकीय तंत्र की आशंका सही हो सकती है किन्तु मुस्लिम समाज ममता के इस आश्वासन पर भी भरोसा नहीं करता कि संसद में पारित हुआ वक्फ विधेयक संसद में पारित होने के बाद किसी राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं रहता। असल में हमारे राजनेताओं की मुश्किल ही यही है कि वह झूठा आश्वासन देने के लिए भी वुतर्व का सहारा लेते हैं। उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि मुस्लिम समाज में भी लोगों को यह जानकारी है कि कानून बनते वैसे हैं और लागू वैसे होते हैं? हैरानी होती है कि मुस्लिम समाज से मात्र यह कहना कि जब वक्फ विधेयक में विभिन्न आपत्तिजनक प्रावधानों पर आपत्ति की समीक्षा सुप्रीम कोर्ट करने को तैयार है तो हिसक आंदोलन करने की जरूरत क्यों पड़ी। जिस तरह वक्फ कानून के खिलाफ लोगों को सड़कों पर उतारने वाले झूठ बोलकर भड़का रहे हैं, ठीक उसी प्राकार राज्य सरकार और उसका तंत्र भी झूठे आश्वासन देकर मुस्लिम समाज को हिसक झड़प से बचने की सलाह दे रहा है। हमारे राजनेताओं की प्रावृत्ति का स्थाईं भाव ही बन गया है कि वे जनता को महामूर्ख समझते हैं, इसलिए मूर्ख बनाना अपना अधिकार समझते हैं। जिस विधेयक पर संसद से पारित होने पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो गया और वह राष्ट्रीय कानून बन गया इसके बावजूद किसी राज्य की मुख्यमंत्री आश्वासन दे कि उस कानून को वह अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगी तो इस पर मात्र यही पूछा जा सकता है।

खबरें जो सोच बदल दे शुभ लाभ हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

एक हजार सैनिकों की बर्खास्तगी नेतन्याहू को पड़ सकती है भारी

तेल अवीव, 13 अप्रैल (एजेंसियां)। इज़राइली डिफेंस फोर्सेज (आईडीएफ) ने गाज़ा युद्ध की आलोचना करने के आरोप में करीब 1000 रिज़र्व सैनिकों की बर्खास्तगी का ऐलान कर दिया है। ऐसे में देश के हालात को देखते हुए कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इसका परिणाम नेतन्याहू सरकार को भुगतना पड़ सकता है। युद्ध को लेकर देश में नेतन्याहू का विरोध पहले से हो रहा है, ऐसे में सैनिकों की बर्खास्तगी का मामला आग में घी डालने जैसा प्रतीत हो रहा है। वैसे भी इसे इज़राइली सेना में अब तक की सबसे बड़ी बर्खास्तगी मानी जा रही है, जो युद्ध के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बोलने को कारण की गई है। यहां बताते चलें कि जिन सैनिकों को बड़ी संख्या में बर्खास्त किया गया उन सैनिकों ने नेतन्याहू सरकार के नाम एक सार्वजनिक पत्र लिख कर युद्ध से वापस लौटने को कहा था। इस पत्र में कहा गया था कि गाज़ा में जारी जंग अब सैन्य नहीं, बल्कि राजनीतिक मकसदों की पूर्ति कर रही है। उन्होंने युद्धविराम की मांग करते हुए कहा कि, यह लड़ाई न तो बंधकों को छुड़ा पा रही है और न ही हमास को खत्म कर रही है। इसके चलते सैनिक, बंधक और आम नागरिक मारे जा रहे हैं। इस सार्वजनिक पत्र पर सैकड़ों रिटायर्ड अफसरों और वायुसेना के रिज़र्व कर्मियों ने दस्तखत किए थे, जिसमें प्रसिद्ध रिज़र्व नेविगेटर अलोन गुर का नाम भी शामिल है। इससे नाराज नेतन्याहू सरकार ने एक हजार रिजर्व सैनिकों को बर्खास्त कर दिया। आईडीएफ के प्रवक्ता ने कहा कि यह बयानबाज़ी सैन्य अनुशासन और एकता के खिलाफ है। हमारी प्राथमिकता देश की सुरक्षा है। जब हम कई मोर्चों पर जूझ रहे हैं, तब ऐसे सार्वजनिक बयानों से हमारी एकता और सैन्य नीति कमजोर होती है। सेना प्रमुख ईयार जमीर और वायुसेना नेतृत्व ने यह निर्णय लिया।

न्यूज ब्रीफ

न्यूयार्क में प्लेन क्रेश, एक की मौत

न्यूयार्क। अमेरिका के न्यूयार्क में एक प्लेन क्रैश होने खबर आ रही है। इस प्लेन में दो लोग सवार थे, इनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई। हादसा कोलंबिया काउंटी के कोपेक इलाके के पास हुआ। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) के प्रवक्ता के मुताबिक विमान कोलंबिया काउंटी एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था। लेकिन जैसे ही वह एयरपोर्ट से करीब कुछ ही दूर रहा होगा, तभी हादसा हो गया। विमान कीचड़ भरे खेत में जा गिरा। बताया जाता है कि विमान का हादसा शनिवार की शाम को हुआ, लेकिन जानकारी काफी देर बाद लगी। नेशनल टांसपोर्टेशन सुरक्षा बोर्ड हादसे की जांच के लिए टीम मौके पर भेजी है। लेकिन खराब मौसम और बर्फ के कारण बचाव टीम को मौके पर पहुंचने में काफी दिक्कत आ रही हैं।

यूक्रेनी दूतावास का दावा, भारतीय दवा गोदाम पर रुस ने दागी मिसाइल

कीव। भारत में यूक्रेनी दूतावास ने कहा कि रूस ने शनिवार को यूक्रेन में एक भारतीय दवा कंपनी के गोदाम पर मिसाइल दागी। सोशल मीडिया पर पोस्ट में यूक्रेनी दूतावास ने आरोप लगाया कि यद्यपि रूस, भारत के साथ दोस्ती का दावा करता है, लेकिन वह जानबूझकर यूक्रेन में भारतीय व्यवसाय को निशाना बना रहा है। यूक्रेनी दूतावास ने कहा कि यूक्रेन में भारतीय दवा कंपनी कुसुम के गोदाम पर रूसी मिसाइल दागी गई। रुस बच्चों और बुजुर्गों के लिए बनी दवाइयों को नष्ट कर रहा है ।

एक तरफ बातचीत का ऑफर दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ तैनात एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स और जवान

तेहरान। मध्य पूर्व की उथल-पुथल भरी धरती फिर हथियारों की गर्जना से गूंज रही है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो सैन्य तैनाती शुरू की है, वह सिर्फ एक सामान्य डिफेंस स्ट्रैटजी नहीं, बल्कि ये एक चेतावनी है। अमेरिका ने जिस तरह से ईरान को घेरा है। बी-2 स्टील्थ बॉम्बर्स से लेकर फुल कैपेबिलिटी एयरक्राफ्ट कैरियर्स और साइप्रस से लेकर इजराइल तक...जिस तरह का मिलिट्री कॉर्डिनेशन अमेरिका ने तैयार किया है, उससे पता चलता है कि अमेरिका अब सिर्फ धमकी देने के मूड में नहीं है। अमेरिका ने ईरान से बातचीत से पहले जिस तरह से इस क्षेत्र में फोर्स तैनात की है, उससे आशंका है कि अगर ये बातचीत फेल होती है तो फिर क्या होगा परमाणु डील फेल होने पर अमेरिका करेगा क्या बड़ी कार्रवाई अमेरिका ने हिंद महासागर के डिएगो गार्सिया द्वीप में बी-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स के 6 यूनिट तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिकी थाड एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात किया है और इतना सब करने के बाद अब अमेरिका ने अपने दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को भी मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट के करीब पहुंच चुका है। इसमें 90 फाइटर जेट्स और 6000 से ज्यादा चालक दल के सदस्य हैं। परमाणु समझौते को लेकर अमेरिका और ईरान के अधिकारियों के बीच यानी शनिवार को ओमान में बैठक होने वाली है। वहीं ईरानी के सरकारी टीवी चैनल ने घोषणा की थी कि ईरानी उप विदेश मंत्री अब्बास अराघची और अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के बीच ओमान में शनिवार की बैठक की कोई भी तस्वीर जारी नहीं की जाएगी। जिससे ये संकेत मिलते हैं कि ये बैठक आमने-सामने की बातचीत वास्तव में हो सकती है। जिससे पहले ईरान ने इनकार कर दिया था। एक डिप्लोमेटिक सूत्र ने बताया कि हूती विद्रोहियों के खिलाफ चल रहे अमेरिकी अभियान के बीच, जिन्हें ईरान का समर्थन हासिल है, ईरान इस क्षेत्र में अपने मिलिशिया के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सूत्र के मुताबिक ईरान का मानना है कि उसके मिलिशिया अपने उद्देश्यों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं और अब वह कम से कम अपने मिसाइल कार्यक्रम की सुरक्षा करना चाहता है।

बीबीआईएन मोटर वाहन समझौता प्रोटोकॉल तैयार, वर्ष 2015 में भूटान में मोटर वाहन समझौते पर हुए थे हस्ताक्षर

काठमांडू, 13 अप्रैल (एजेंसियां)। बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल (बीबीआईएन) के बीच यात्री, व्यक्तिगत और कार्गो वाहनों के यातायात के आवागमन के लिए मोटर वाहन समझौते (एमवीए) पर हस्ताक्षर करने के एक दशक बाद, चार दक्षिण एशियाई देशों ने सुचारू परिवहन सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल को अंतिम रूप दे दिया है। यह प्रोटोकॉल दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला प्रोटोकॉल है। मोटर वाहन समझौते के अलावा बीबीआईएन देश क्षेत्रीय ऊर्जा सुरक्षा के लिए इंटरकनेक्टेड ग्रिड के बारे में भी सहमत हो सकते हैं।

बीबीआईएन-एमवीए का उद्देश्य यात्रियों, व्यक्तिगत और कार्गो वाहनों के यातायात के माध्यम से अंतर-क्षेत्रीय व्यापार और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए बाधाओं और नियमों को दूर करना है। हालांकि हाल ही में भारत के द्वारा बांग्लादेश को दी गई महत्वपूर्ण ट्रांसशिपमेंट सुविधाओं को रद्द करने के भारत के हालिया फैसले से चार देशों के बीच एमवीए के निष्पादन में बाधा डाल सकती है। गौरतलब है कि बांग्लादेश के सड़क परिवहन और पुल मंत्री, भूटान के सूचना और संचार मंत्री, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग और शिपिंग मंत्री और नेपाल के भौतिक बुनियादी ढांचे और परिवहन मंत्री ने 15 जून 2015 को थिम्पू, भूटान में बीबीआईएन मोटर वाहन समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। नेपाल के यातायात मन्त्रालय के सचिव केशव शर्मा के मुताबिक प्रोटोकॉल के अनुसार भूटान को छोड़कर तीन अन्य हस्ताक्षरकर्ता सभी प्रकार के वाहनों को उनके बीच चलने की अनुमति देंगे। इनमें कार्गो वाहन परमिट के तहत तीन श्रेणियों - हल्के वाणिज्यिक वाहन (7,500 किलोग्राम तक), मध्यम वाणिज्यिक वाहन (7,500-12,000 किलोग्राम) और भारी वाणिज्यिक वाहन (12,000 किलोग्राम से ऊपर) शामिल हैं। उन्होंने बताया कि प्रोटोकॉल को अंतिम रूप देने से पहले 2015 से लेकर 2018 तक कई चरण का परीक्षण किया गया। इसने दिखाया कि यात्रियों, व्यक्तिगत और कार्गो वाहनों के यातायात की निर्बाध आवाजाही संभव है। कार्गो ट्रायल रन नवंबर, 2015 में कोलकाता-ढाका-अगरतला मार्ग (600 किमी) के बीच आयोजित किया गया था। 29 अगस्त से 5 सितंबर 2016 तक ढाका और दिल्ली (1,780 किमी) के बीच, जबकि 23 अप्रैल, 2018 को भारत के माध्यम से ढाका से काठमांडू तक एक यात्री बस को परीक्षण के रूप में चलाया गया था। बीबीआईएन-एमवीए के निष्पादन का समर्थन करने वाले एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के अनुसार अब प्रस्तावित ट्रायल रन मार्ग काठमांडू-भैरहवा-सुनौली-लखनऊ-कानपुर-नई दिल्ली और नेपाल और भारत के बीच काठमांडू-बीरगंज-रक्सौल-कोलकाता हैं। इसी तरह काठमांडू-काँकडभिट्टा-पानीटंकी-सिलीगुड़ी-फुलबारी-बंगलाबांधा-मोंगला व चटोग्राम मार्ग नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच एक परीक्षण मार्ग के रूप में प्रस्तावित है। संबंधित देशों के अधिकारियों ने मार्च 2022 में नई दिल्ली में मुलाकात की थी और मोटर वाहन समझौते को निष्पादित करने के लिए एक समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने पर सहमति व्यक्त की है। इनमें अधिक परीक्षण करने का सुझाव दिया और एडीबी से परीक्षण का समर्थन करने का अनुरोध किया।

एमवीए के कॉन्सेप्ट पेपर के अनुसार बैंक ने बाद में एक तौर-तरीका प्रस्तावित किया था। ट्रायल रन बांग्लादेश, भारत और नेपाल के बीच या केवल दो देशों के बीच आयोजित किए गए थे। भूटान ने बीबीआईएन-एमवीए पर हस्ताक्षर किए हैं और प्रोटोकॉल को अपनी सहमति दी है लेकिन उसने ट्रायल रन में भाग नहीं लिया। एडीबी के कंट्री डायरेक्टर मखूतर खामुंदखनोव के मुताबिक एडीबी द्वारा बनाई जा रही एशियाई राजमार्ग एक गलियारा होगा जो बीबीआईएन-एमवीए के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एडीबी ने मार्ग सामंजस्य (मार्ग-आधारित मूल-गंतव्य विश्लेषण), मार्ग पहचान, शुल्क निर्धारण, सीमा पार वाहन बीमा और नेपाल के लिए बीबीआईएन निहितार्थ अध्ययन पर निष्कर्ष निकाला है। उन्होंने कहा कि नेपाल के पास चार भारतीय बंदरगाहों-कोलकाता, हल्दिया, विशाखापत्तनम और मुंद्रा तक सीधी पहुंच होगी। प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षरकर्ता दो साल के भीतर, समझौते के तहत चलने वाले वाहनों की कुशल ट्रैकिंग के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म स्थापित करेंगे। राष्ट्र वाहन और कार्गो आवाजाही की निगरानी और सुरक्षा उपायों के कार्यान्वयन के लिए एक साझा इलेक्ट्रॉनिक मंच स्थापित करेंगे। शर्त यह भी है कि वाहनों के चालक दल को हस्ताक्षरकर्ता देशों के नागरिक होना चाहिए। वे वैध पासपोर्ट या अन्य दस्तावेजों के आधार पर यात्रा करेंगे। जब सीमा पार यात्रा के लिए वीजा की आवश्यकता होती है, तो ड्राइवरों और चालक दल द्वारा वीजा के लिए आवेदन को समझौते के अनुसार जारी किए गए उसके क्रू पहचान पत्र को सत्यापित किया जाएगा।

नेतन्याहू के भड़कते हुए कनाडाई पीएम ने दे दी सफाई

तेल अवीव,13 अप्रैल (एजेंसियां)।

गाज़ा संकट को लेकर कनाडा और इज़राइल के बीच राजनयिक तनाव देखने को मिल रहा है। वैसे कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने इजराइल के भड़कने के बाद अपने बयान पर सफाई दे दी है, लेकिन मामला शांत होता दिख नहीं रहा है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा गाज़ा पर दिए गए एक बयान पर इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी आपत्ति जताई और बयान वापस लेने को कहते हुए कड़ी चेतावनी दे दी।

यहां बताते चलें कि कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी एक सार्वजनिक समारोह में बोल रहे थे, तभी एक फिलिस्तीन समर्थक व्यक्ति ने उन्हें बीच में टोका और कहा - गाज़ा में नरसंहार हो रहा है। इस पर जवाब देते हुए कार्नी ने कहा- मुझे पता है, इसीलिए हमारे यहां हथियारों पर प्रतिबंध है। पीएम कार्नी के इस बयान पर नेतन्याहू ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रतिक्रिया देते हुए उन्हें बयान वापस लेने की नसीहत दे दी। उन्होंने लिखा, कि कनाडा ने हमेशा सभ्यता का पक्ष लिया है, इसलिए प्रधानमंत्री कार्नी को भी वही करना चाहिए। उन्हें अपना बयान तुरंत वापस लेना चाहिए। इज़राइल, जो कि एकमात्र यहूदी देश है, हमास के खिलाफ न्यायपूर्ण तरीके से लड़ रहा है। बढ़ते विवाद के बीच कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने सफाई दी है। पीएम कार्नी ने कहा कि भीड़ के शोर में सुनाई ही नहीं दिया कि गाजा शब्द के साथ नरसंहार भी कहा गया है। शोर अधिक था और उन्हें सिर्फ 'गाज़ा' शब्द ही सुनाई दिया, 'नरसंहार' शब्द सुनाई ही नहीं दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उनका बयान किसी विशेष स्थिति का समर्थन या विरोध से जुड़ा हुआ नहीं था।

यूक्रेन-रूस युद्ध समाप्ति को बातचीत सही दिशा की ओर: ट्रम्प

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा है कि यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध समाप्ति के लिए बातचीत शायद सही दिशा की ओर जा रही है। मीडिया रिपोर्टस के मुताबिक एयर फोर्स वन में ट्रम्प ने पत्रकारों से कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो कि ठीक दिशा की ओर जा रहा है। लेकिन ऐसा समय भी आता है जब आपको कुछ कर दिखाना होता है। या फिर चुप हो जाना होता है। डोनाल्ट ट्रम्प का बयान ऐसे समय आया है, जब बीते दिनों अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकाफ ने सलाह दी थी कि यदि अमेरिका यूक्रेन बंटवारे वाली रूस की शर्त मान लेता है तो युद्ध विराम संभव है। इस बयान को लेकर खलबली देखी गई थी।लेकिन अब डोनाल्ड ट्रम्प के हाल के बयान के बाद इसे अमेरिका की ओर से एक तरह के यूक्रेन-रूस युद्ध के मुद्दे पर उनका पक्ष माना जा रहा है।

म्यांमार में फिर लगे भूकंप के तेज झटके 5.1 रही तीव्रता.....लोग घरों से भागे

नेपीडॉ,13 अप्रैल (एजेंसियां)। म्यांमार में रविवार सुबह एक बार फिर भूकंप के तेज झटकों ने लोगों को हिला कर रख दिया। सुबह 7 बजकर 54 मिनट पर आए इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.1 मापी गई है। भूकंप का केंद्र जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था।

म्यांमार में एक बार फिर आए भूकंप के झटकों के बीच राहत की खबर यह रही कि इस बार किसी जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है, लेकिन अचानक आए झटकों के कारण लोग भयभीत होकर अपने घरों से बाहर निकल आए। इस भूकंप के तीब्र झटके ऐसे समय में महसूस हुए हैं जबकि 28 मार्च को म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप की त्रासदी अभी भी लोगों के जेहन में ताज़ा है। उस समय 7.7 तीव्रता वाले भूकंप ने मांडला क्षेत्र को बुरी तरह झकझोर दिया था। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस त्रासदी में करीब 3600 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 5000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे।

संचार तंत्र पर भी पड़ा असर

भूकंप से म्यांमार के मोबाइल संचार तंत्र को भी भारी नुकसान पहुंचा। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कुल 6730 संचार स्टेशन प्रभावित हुए, जिनमें से अब तक करीब 6000 की मरम्मत की जा चुकी है।

दुनियाभर से मिल रही है मदद

म्यांमार में आई इस आपदा के बाद भारत, अमेरिका, चीन जैसे देशों ने अपने राहत एवं बचाव दल भेजे हैं। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी चिकित्सा सहायता और आवश्यक संसाधन मुहैया कराए हैं।

रविवार सुबह आए भूकंप से लोगों की चिंता बढ़ गई। मेइकतिला शहर में रविवार सुबह आए 5.5 तीव्रता के भूकंप का केंद्र मांडले और नैपीदा के बीच जमीन से 10 किमी नीचे था। फिलहाल इस भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि क्षेत्र में बार-बार आ रहे भूकंपों को देखते हुए सतर्कता बनाए रखना बेहद जरूरी है।

इजराइल ने सेंट्रल गाजा स्थित अस्पताल में किए हवाई हमले, इमरजेंसी वार्ड तबाह, राफा से कटा गाजा का संपर्क

गाजा पट्टी,13 अप्रैल (एजेंसियां)।

इजराइल ने गाजा पर हमले और तेज कर दिए हैं, जिससे स्थिति और भी भयावह हो गई है। शनिवार देर रात इजराइली सेना ने सेंट्रल गाजा स्थित अल-अहली अरब बैपटिस्ट अस्पताल को निशाने पर लेते हुए हमले किए हैं। अस्पताल स्टाफ के अनुसार, परिसर की एक बिल्डिंग पर दो मिसाइलें दागी गईं, जिससे इमरजेंसी और रिसेप्शन विभाग पूरी तरह नष्ट हो गया।

स्थानीय सूत्रों ने बताया कि हमले से ठीक पहले अस्पताल प्रशासन को एक फोन कॉल आया, जिसमें इमारत खाली करने को कहा गया। कॉल के कुछ ही मिनट बाद विस्फोट हुआ, जिससे आसपास की इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। इजराइली सेना की ओर से अभी तक इस हमले पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है। हालांकि पहले इजराइल की ओर से दावा किया गया था कि उसी इलाके से उस पर रॉकेट दागे गए थे।

राफा का संपर्क गाजा पट्टी से टूटा

इस बीच इजराइली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज़ ने पुष्टि की है कि इजराइली डिफेंस फोर्स ने मोराग कॉरिडोर पर कब्जा कर लिया है। यह कॉरिडोर गाजा के दक्षिण में स्थित एक रणनीतिक रास्ता है जो राफा को गाजा पट्टी के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इससे अब राफा पूरी तरह अलग-थलग पड़ गया है। इसके साथ ही काट्ज़ ने गाजा के निवासियों को चेतावनी देते हुए कहा है, कि यह हमास को खत्म करने और बंधकों की रिहाई के लिए अंतिम मौका है। अगर ऐसा नहीं हुआ, तो यही हाल गाजा के अन्य हिस्सों का भी होगा।

इस प्रकार से इलराइल द्वारा लगातार हो रहे हमलों से गाजा में मानवीय संकट गहरा गया है। अस्पतालों पर हमले और नागरिक इलाकों में हो रही तबाही ने राहत और बचाव कार्यों को और मुश्किल बना दिया है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय की नजरें अब इस भयावह युद्ध के रुकने पर टिकी हुई हैं।

शख्स ने किया तीन बार मरकर लौटने का दावा

लंदन । सदियों से इंसान यह जानने की कोशिश कर रहा है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, लेकिन अब तक इस सवाल का कोई ठोस और सार्वभौमिक जवाब नहीं मिला है। आमतौर पर वही कहानियां सामने आती हैं जो उन लोगों ने बताई हैं जो कुछ पल के लिए मौत के करीब जाकर लौट आए हैं। इन्हीं अनुभवों को आधार बनाकर लोग जीवन के उस रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं जो मौत के बाद शुरू होता है। कुछ लोगों को यह अनुभव सुखद लगता है, तो कुछ ने डरावनी कहानियां भी सुनाई हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं डैनियन ब्रिंक्ले, जिन्होंने दावा किया है कि वे तीन बार मरकर फिर जिंदा हुए हैं। 74 वर्षीय डैनियन ने अपनी जिंदगी और मृत्यु के अनुभवों को किताब के रूप में दुनिया के सामने रखा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, पहली बार 1975 में उन पर टेलीफोन का खंभा गिर गया था, जिसके चलते वे 28 मिनट तक मृत रहे और फिर लौट आए। दूसरी बार 1989 में उनकी ओपन हार्ट सर्जरी के दौरान मौत हुई, लेकिन वे फिर जीवित हो गए। तीसरी बार ब्रेन सर्जरी के वक्त उनकी मृत्यु हुई, परंतु फिर से उन्हें जीवन मिल गया। अपने पहले अनुभव के बारे में डैनियन ने बताया कि उन्हें एक अंधेरी सुरंग से होकर गुजरना पड़ा, जिसके बाद वे एक चमकदार जगह पर पहुंचे। वहां उन्हें अपने पूरे जीवन की घटनाएं एक-एक कर फ्लैशबैक में दिखाई दीं। इसके बाद एक चमकदार रौशनी के साथ वे वापस लौट आए। दूसरी बार की मौत के बाद वे एक कांच जैसे शहर पहुंचे, जिसे उन्होंने स्वर्ग बताया। वहां फरिश्तों ने उन्हें अध्यात्मिक और मानसिक शक्ति के उपयोग के तरीके सिखाए। इन अनुभवों के बाद डैनियन अब लोगों को सलाह देते हैं कि मौत उतनी डरावनी नहीं है जितना हम उसे समझते हैं।

बेंगलूरू ने राजस्थान को नौ विकेट से पीटा, सॉल्ट और कोहली ने जड़े अर्धशतक

जयपुर, 13 अप्रैल (एजेंसियां)।

आईपीएल 2025 के 28वें मैच में आरसीबी ने राजस्थान रॉयल्स को उसी के घर में 9 विकेट से हरा दिया। इस मैच में पहले बल्लेबाजी करने राजस्थान रॉयल्स की टीम उतरी और उसने बोर्ड पर 173 रन लगाए। जवाब में आरसीबी ने इस टारगेट को चेज करने में सिर्फ 17.1 ओवर लिए। आरसीबी के लिए इस मैच में

फिल साल्ट ने 65 रन की पारी खेली, वहीं विराट कोहली ने नाबाद 62 रन बनाए।

हालांकि राजस्थान की टीम को विराट का विकेट पहले ही मिल जाता लेकिन रियान पराग की एक गलती ने ये मौका छीन लिया।रियान पराग ने विराट कोहली का एक आसान कैच छोड़ दिया।

यह कैच संदीप शर्मा के ओवर में छूटा। इस वजह से कोहली को आउट करने का एक सुनहरा मौका हाथ से निकल गया। बाद में यशस्वी जायसवाल की शानदार बल्लेबाजी और रियान पराग के साथ उनकी साझेदारी की बदौलत ठठ ने 173 रन बनाए।

संदीप शर्मा की गेंद पर विराट कोहली ने एक शॉट खेला।

गेंद हवा में ऊंची गई। रियान पराग मिड-ऑन से दौड़कर आए और कैच लेने की कोशिश की। लेकिन, वे कैच नहीं पकड़ पाए। यह एक आसान कैच था, पर पराग ने इसे छोड़ दिया। इससे वे निराश दिखे।

उन्होंने तुषार देशपांडे से कुछ बातें भी कीं। तुषार भी गेंद की तरफ आ रहे थे, लेकिन फिर पीछे हट गए।संदीप शर्मा ने खझङ में कोहली को 7 बार आउट किया है। वे लगभग आठवीं बार उन्हें आउट करने वाले थे। लेकिन, कैच छूटने की वजह से कोहली बच गए और उन्होंने दो रन बना लिए। पराग, जो कोहली को अपना आदर्श मानते हैं, कैच छोड़ने के बाद हैरान दिखे। सोशल मीडिया पर फैंस ने इस घटना पर खूब प्रतिक्रिया दी। अगर इस कैच को पराग पकड़ लेते तो आरसीबी की टीम के ऊपर दवाब आ सकता था और कहीं ना कहीं इस मैच में राजस्थान की टीम वापसी कर सकती थी।

न्यूज ब्रीफ

धवन के घर पहुंची सोफी

नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व सलामी बल्लेबाज शिखर धवन पिछले कुछ समय से एक विदेशी युवती के साथ नजर आते रहे हैं जिससे उनके अफेयर की चर्चाओं को भी बल मिला है। इसके बाद सामने आया कि ये युवती आयरलैंड की सोफी शाइन है। अब धवन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर आया है। इसमें सोफी उनसे कह रही है कि मुझे आपके पास रहना है। धवन सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहते हैं और आमतौर पर अपने वीडियो साझा करते है। अब उन्होंने सोफी के साथ एक रील साझा की है। इस दौरान सोफी वीडियो बनाती दिखी। इस दौरान वह धवन से कहा रही हैं, मेरा यहां से जाने की मन नहीं, मुझे आपके पास रहना है। धवन ने कुछ दिन पहले ही बताया था, हाँ, मैंने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया है। मैं यह नहीं कहूंगा कि मैं प्यार में बदकिस्मत था बल्कि, मेरे चुनाव अनुभवहीनता से आए थे पर अब मेरे पास अनुभव है और यह काम आएगा। यह मेरे लिए एक सीखने का दौर था. गौरतलब है कि सोफी एक आयरिश प्रोडक्ट कंसल्टेंट हैं। वहीं धवन ने क्रिकेट के सारे फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है और अब वह विज्ञापनों के अलावा क्रिकेट कमेंट्री के साथ ही कई अन्य काम करते हैं।

शमी आईपीएल में सबसे अधिक रन देने वाले दूसरे गेंदबाज बने

हैदराबाद। अनुभवी तेज गेंदबाज मो शमी के नाम आईपीएल में एक ऐसा रिकार्ड बना है जिससे वह भूलना चाहेंगे। पंजाब किंग्स की ओर से खेलते हुए शमी आईपीएल में सबसे अधिक रन देने वाले दूसरे तेज गेंदबाज बने हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में शमी की गेंदों की जमकर पिटाई हुई और 4 ओवर में ही 75 रन निकल गये जबकि उन्हें एक भी विकेट नहीं मिला। मार्कस स्टॉयनिस ने उनके अंतिम ओवर में लगातार 4 छक्के लगाए। शमी ने अपने अंतिम ओवर में 27 रन दिये। यह आईपीएल के अब तक के इतिहास में दूसरी सबसे महंगी गेंदबाजी है। अब तक आईपीएल में 4 ओवर के स्पेल में सबसे अधिक रन देने के मामले में जोफ्रा आर्चर पहले नंबर पर हैं। राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले आर्चर ने इसी साल हैदराबाद के खिलाफ 76 रन दिये थे। शमी से पहले आईपीएल में सबसे अधिक रन लुटाने वाले भारतीय गेंदबाज मोहित शर्मा थे। मोहित ने पिछले साल गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए 4 ओवर में ही 70 रन दे दिये थे। तब शमी उनकी ही टीम में शामिल थे। वहीं इस बार शमी शमी गुजरात टाइटंस की जगह पर सनराइजर्स हैदराबाद से खेल रहे हैं।

काव्या ने अभिषेक की मां को गले लगाया

हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा की पंजाब किंग्स के खिलाफ खेली पारी से बेहद उत्साहित हैं। अभिषेक ने 141 रनों की आक्रामक पारी खेलकर सनराइजर्स को पंजाब किंग्स के खिलाफ बड़ी जीत दिलायी है। इस मैच में सनराइजर्स को जीत के लिए 246 रनों का बड़ लक्ष्य मिला था जो उसने आसानी से हासिल कर लिया। इसी को देखकर काव्या अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पायीं और उन्होंने अभिषेक की मां को गले से लगा लिया। इसपर उन्होंने भी काव्या को खुशी में हाथ चूम कर बधाई दी। अभिषेक ने इस मैच में 55 गेंदों पर ही 141 रन बना दिये थे। इस प्रकार 245 रन बनाने के बाद भी पंजाब की टीम ये मैच हार गयी। वहीं 4 लगातार हार के बाद हैदराबाद को पहली जीत मिली। काव्या ने अभिषेक के माता-पिता मंजू शर्मा और राज कुमार शर्मा को जाकर गले से लगा लिया। जब काव्या ने अभिषेक की मां को गले से लगाया तो उन्होंने भी प्यार से उनके हाथ को चूमा।

मुंबई ने दिल्ली को 12 रन से हराया

19वें ओवर में तीन बल्लेबाज रनआउट, करुण की मेहनत बेकार

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (एजेंसियां)।

इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 29वें मैच में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 12 रन से हरा दिया। मुकाबले में मुंबई की टीम ने टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर के खेल में 205 रन का स्कोर खड़ा किया। इसके जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम 19 ओवर में 193 रन ही बनाकर सिमट गई। इस तरह लगातार पांच मैच में जीत के बाद अब दिल्ली कैपिटल्स का अभियान रुक गया। वहीं मुंबई की टीम ने इस सीजन में अपनी दूसरी जीत हासिल की।

मुंबई के खिलाफ अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। दिल्ली ने बिना किसी के स्कोर के अपना पहला विकेट गंवा दिया था। हालांकिस इसके बाद करुण नायर ने धमाकेदार अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए मैच को लगभग एक तरफा बना दिया था, लेकिन इसके बाद मुंबई ने स्पिन गेंदबाजों के दमदार खेल और जबरदस्त फील्डिंग से मैच को एक रहते अपने नाम कर लिया। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली के अंतिम तीन विकेट लगातार रनआउट से हासिल किए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत बहुत ही खराब रही थी। दिल्ली ने पारी के पहले ओवर में ही ओपनर बल्लेबाज जैक फ्रेजर मैकगर्क का विकेट गंवा दिया। मैकगर्क को मुंबई के दीपक चाहर ने अपना शिकार बनाया था। हालांकि, इसके बाद दिल्ली के लिए करुण नायर और अभिषेक पोरेल ने मिलकर मोर्चा संभाला। दोनों के बीच दूसरे विकेट के लिए 119 रनों की जबरदस्त साझेदारी हुई। इस दौरान अभिषेक पोरेल 25 गेंद में 33 रन बनाकर आउट हो गए। अपनी इस पारी में उन्होंने 3 चौके और 1 छक्का भी लगाया।

पोरेल के आउट होने के बाद एक छोर से करुण नायर का तूफान जारी था, लेकिन मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों को एक वापसी का मौका जरूर मिला गया। आरसीबी के खिलाफ मिडिल ऑर्डर में दमदार बल्लेबाजी करने वाले केएल राहुल का इस मैच में बल्ला नहीं चल पाया। राहुल 13 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। इसके अलावा कप्तान अक्षर पटेल ने 9 और ट्रिस्टन स्टब्स ने सिर्फ 1 रन बनाए।

दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस को टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी का न्योता मिला था। मुंबई की टीम ने दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में तिलक वर्मा (59), रयान रिकेल्टन (41), सूर्यकुमार यादव (40) और नमन धीर (नाबाद 38) की शानदार पारियों से निर्धारित 20 ओवर खेल में पांच विकेट पर 205 रन का मजबूत स्कोर बनाया।

मुंबई के लिए इस मैच में रोहित शर्मा और रिकलटन ने ओपनिंग साझेदारी में पांच ओवर में 47 रन जोड़े। रोहित अच्छी शुरुआत के बाद एक बार फिर बड़ी पारी खेलने से चूक गए। रोहित ने 12 गेंदों पर 18 रन में दो चौके और एक छक्का लगाया। विप्रज निगम ने रोहित को एलबीडबल्यू किया। रिकेल्टन ने 25 गेंदों पर 41 रन में पांच चौके और दो छक्के लगाए। सूर्यकुमार यादव ने 28 गेंदों पर पांच चौकों और दो छक्कों के सहारे 40 रन बनाए।

मुंबई की तरफ से तिलक वर्मा ने 33 गेंदों पर छह चौके और तीन छक्के उड़ाते हुए 59 रन की तूफानी अर्धशतकीय पारी खेली। यह उनका लगातार दूसरा अर्धशतक है। इसके अलावा नमन धीर ने मात्र 17 गेंदों पर तीन चौके और दो छक्के उड़ाते हुए नाबाद 38 रन की जबरदस्त पारी खेली।दिल्ली के लिए दोनों कलाई के स्पिनर कुलदीप यादव और विप्रज निगम बेमिसाल साबित हुए और मध्य ओवरों में टीम को विकेट दिलाए। कुलदीप ने चार ओवर में मात्र 23 रन देकर दो विकेट जबकि विप्रज ने चार ओवर में 41 रन देकर दो विकेट लिए।

हैदराबाद से हार पर पंजाब किंग्स के बॉलिंग कोच सुनील बोले-हमें डॉट बॉल प्रतिशत बढ़ाने की जरूरत

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (एजेंसियां)।

पंजाब किंग्स के स्पिन-गेंदबाज कोच सुनील जोशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार पर कहा है कि हमारे बल्लेबाज अच्छी फार्म हैं, लेकिन गेंदबाजी में थोड़ी सुधार के साथ डॉट-बॉल प्रतिशत बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हम आधे मौकों का फायदा नहीं उठा सके।

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2025 में शनिवार को पंजाब किंग्स को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। पंजाब किंग्स ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाज प्रभसिमरन सिंह (23 गेंदों पर 42 रन), प्रियांश आर्य (13 गेंदों पर 36 रन), कप्तान श्रेयस अय्यर (36 गेंदों पर 82 रन) और मार्कस स्टोइनिस (11 गेंदों पर नाबाद 34 रन) की धमाकेदार पारियों की बदौलत 6 विकेट पर 245 बनाए थे। सनराइजर्स हैदराबाद ने इसके जवाब में अभिषेक शर्मा (55 गेंदों पर 141 रन) ट्रैविड हेड (37 गेंदों पर 66 रन) की बदौलत जीत सुनिश्चित की। सनराइजर्स हैदराबाद ने 18.3 ओवर में मात्र 2 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। पंजाब किंग्स 5 मैचों में तीन जीत और दो हार के बाद प्वाइंट टेबल में छठे नंबर पर आ गई है। मैच पर विचार रखते हुए पंजाब किंग्स के स्पिन बॉलिंग कोच सुनील जोशी ने कहा कि मुझे लगता है कि इस मैच से सकारात्मक बात यह रही कि हमारे बल्लेबाज निश्चित रूप से शानदार फॉर्म में हैं। हालांकि, गेंदबाजी में सुधार की जरूरत है और हमें अपना डॉट-बॉल प्रतिशत बढ़ाने की जरूरत है। इस विकेट पर गेंदबाजी करते समय हम यही चूक गए। अच्छे विकेट पर, बीच के ओवरों में डॉट-बॉल प्रतिशत ही एकमात्र अंतर हो सकता है। इसलिए यही महत्वपूर्ण है और हम आधे मौकों का फायदा नहीं उठा सके। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि गेंदबाजों ने कोई कसर नहीं छोड़ी, मेरा मतलब है कि यह एक अच्छा विकेट है। यह हमारे लिए अच्छा प्रदर्शन करने का एक मौक़ा था, लेकिन सच तो यह है कि हमने अपने मौके गंवा दिए। पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर का भी मानना है कि गेंदबाजी इकाई उस रात बेहतर प्रदर्शन कर सकती थी, लेकिन उन्होंने यह भी सुनिश्चित किया कि टीम अपनी रणनीतियों में सुधार करने के बाद मजबूत वापसी करेगी।

ला लीगा फुटबॉल

स्पेन में ला लीगा फुटबॉल में खेलते हुए खेलते हुए बार्सिलोना के पैड्री।

डेरेन गंगा की पत्नी का बनारस से है गहरा नाता

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (एजेंसियां)।

वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर डेरेन गंगा भारतीय मूल से ताल्लुक रखते हैं। उनके पूर्वज वर्षों पहले भारत से त्रिनिडाड एंड टोबैगो जाकर बस गए थे। गंगा का जन्म त्रिनिडाड में हुआ और उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 48 टेस्ट और 35 वनडे मैच खेले। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद वह कमेंट्री से जुड़े हुए हैं और वर्तमान में आईपीएल के वर्ल्ड फीड अंग्रेजी पैनल का हिस्सा हैं। डेरेन की पत्नी प्रणीता तिवारी भी भारत से जुड़ी हुई हैं। उनका पारिवारिक घर बनारस के अस्सी घाट पर है।

प्रणीता का जन्म ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और वह अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में एड व सेल्स फर्म में काम कर चुकी हैं। उन्होंने लगभग पांच साल न्यूयॉर्क में बिताए। कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने त्रिनिडाड में गंगा जूस बार नाम से एक दुकान शुरू की, जो पिछले पांच वर्षों से सफलतापूर्वक चल रही है। खास बात यह है कि फुर्सत के समय में डेरेन गंगा खुद भी दुकान पर हाथ बंटाते हैं।

डेरेन और प्रणीता की पहली मुलाकात 2017 में अमेरिका में हुई थी। लंबे समय तक डेटिंग के बाद दोनों ने 2020 में शादी कर ली। प्रणीता भारत से गहरे जुड़ाव को हमेशा महसूस करती हैं और अक्सर अपने पति के साथ बनारस आती रहती हैं। डेरेन गंगा जब भी बनारस आते हैं, गंगा में डुबकी लगाना नहीं भूलते।

उन्होंने लगभग दो साल पहले अस्सी घाट पर स्नान किया था। गौरतलब है कि डेरेन की जूस दुकान पर अब तक कई दिग्गज क्रिकेटर आ चुके हैं, जिनमें ब्रायन लारा भी शामिल हैं। इस जोड़ी की कहानी खेल, संस्कृति और व्यवसाय का सुंदर संगम है।

चेन्नई सुपर किंग्स के पास अभी प्लेऑफ में पहुंचने का मौका, सभी को उम्मीद थाला से

चेन्नई, 13 अप्रैल (एजेंसियां)।

चेन्नई सुपर किंग्स के लिए आईपीएल 2025 का अब तक का सीजन बेहद खराब साबित हो रहा है।5 बार की चैंपियन टीम ने अभी तक 6 मैच में से 5 में हार का सामना करना पड़ा है। चेन्नई सुपर किंग्स के क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब टीम लगातार मैच हारी है। ऐसा पहली बार हुआ हैं कि एमए चिदंबरम स्टेडियम में सीएसके ने हार की हैट्रिक लगाई हो। ऋतुराज गायकवाड़ के टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद लगा था कि नए कप्तान एमएस धोनी के साथ सीएसके की किस्मत पलटेगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। शुक्रवार को केकेआर के खिलाफ उन्हें 8 विकेट से शर्मनाक हार मिली। हालांकि हार के बावजूद उनके पास प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई करने का मौका है।

सीएसके का प्लेऑफ समीकरण कुछ इसपर हैं, सीएसके ने आईपीएल 2025 में अभी तक 6 मैच खेले हैं जिसमें उन्हें 1 में जीत मिली है। टीम को अभी इस सीजन में 8 और मैच खेलने हैं। अगर सीएसके इन 8 में से 7 मुकाबले जीत जाती हैं, तब उनके खाते में 16 अंक आएंगे और आईपीएल के इतिहास में देखा गया है कि 16 अंक के साथ अक्सर टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर जाती है। वहीं अगर चेन्नई 8 के 8 मैच जीतने में कामयाब रहती है, तब उनके खाते में 18 पॉइंट्स हो जाएंगे, फिर निश्चित उन्हें नॉकआउट राउंड में जगह मिल जाएगी।

खराब फार्म के दौरान युवराज और सूर्यकुमार से सलाह ले रहा था : अभिषेक

हैदराबाद। सनराइजर्स हैदराबाद के युवा बल्लेबाज अभिषेक शर्मा ने आईपीएल में पंजाब किंग्स के खिलाफ 55 गेंदों में ही 141 रनों की तूफानी पारी खेलकर अपना फार्म हासिल किया है। इस मैच में अभिषेक की पारी से सनराइजर्स को शानदार जीत मिली है। आईपीएल के इस सत्र में ये पहली बार है जब अभिषेक ने अच्छी पारी खेली है। इस सत्र के शुरुआती मैचों में वह असफल रहे थे। अभिषेक ने कहा है कि जब वह रन नहीं बना पा रहे थे तो इस दौरान उन्होंने अपने मेंटर युवराज सिंह के अलावा सूर्यकुमार यादव से भी बात की थी। अभिषेक की आक्रामक पारी से ही हैदराबाद की टीम पंजाब किंग्स से मिले 246 रनों के लक्ष्य को हासिल करने में सफल रही। मैच में धमाकेदार पारी खेलने के बाद अभिषेक ने कहा, यह जीत बहुत विषेष है क्योंकि मैं हार के सिलसिले को तोड़ना चाहता था। टीम इस जीत से पहले लगातार चार मैच हारी है। उन्होंने कहा, खराब फार्म के दौरान उन्होंने युवराज से भी बात की थी। इसके अलावा सूर्या से भी मुझे लगातार सहयोग मिलता रहा है।

खबरें जो सोच बदल दे शुभ लाभ हिन्दी दैनिक समाचार पत्र

एफपीआई ने अप्रैल में भारतीय शेयर बाजारों से निकाले 31,575 करोड़

नई दिल्ली, 13 अप्रैल (एजेंसियां)। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) ने अप्रैल में अब तक भारतीय शेयर बाजारों से 31,575 करोड़ रुपये निकाले हैं। इससे पहले 21 मार्च से 28 मार्च तक छह कारोबारी सत्रों में एफपीआई ने शेयरों में 30,927 करोड़ रुपये डाले थे। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार इस निवेश से मार्च में एफपीआई की कुल निकासी घटकर 3,973 करोड़ रुपये रही है। पिछले महीनों की तुलना में यह स्थिति में उल्लेखनीय सुधार है। फरवरी में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने शेयरों से 34,574 करोड़ रुपये निकाले थे, जबकि जनवरी में यह निकासी और भी अधिक यानी 78,027 करोड़ रुपये थी। आंकड़ों के अनुसार, एक अप्रैल से 11 अप्रैल के बीच एफपीआई ने भारतीय शेयरों से 31,575 करोड़ रुपये निकाले हैं। इसके साथ ही, 2025 में अब तक एफपीआई की कुल निकासी 1.48 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई है। बाजार के जानकारों ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी शुल्क के बाद वैश्विक शेयर बाजारों में उथल-पुथल भारत में एफपीआई निवेश को भी प्रभावित कर रही है। उनका मानना है कि मौजूदा उथल-पुथल थमने के बाद ही एफपीआई की रणनीति अधिक स्पष्ट हो पाएगी। उन्होंने कहा कि मध्यम अवधि में एफपीआई भारत में खरीदार बन सकते हैं, क्योंकि अमेरिका और चीन दोनों ही मौजूदा व्यापार युद्ध के चलते अपरिहार्य सुस्ती की ओर बढ़ रहे हैं। प्रतिकूल वैश्विक परिदृश्य में भी भारत वित्त वर्ष 2025-26 में छह प्रतिशत की वृद्धि दर्ज कर सकता है।

21 मार्च से 28 मार्च तक एफपीआई ने शेयरों में 30,927 करोड़ रुपये डाले थे

न्यूज ब्रीफ

बाबा रामदेव की शरबत जिहाद को लेकर आलोचना, वीडियो में योग गुरु ने सॉफ्ट ड्रिंक्स को टॉयलेट क्लीनर के जैसा बताया

नई दिल्ली। पतंजलि योग गुरु बाबा रामदेव की आयुर्वेद कंपनी ने हाल ही में अपने नए विज्ञापन के माध्यम से धर्म के मामले पर चर्चा खड़ी की है। इस विज्ञापन में पतंजलि ने पुराने ढर्रे वाले शरबत ब्रांडों पर धन और धर्म की बर्बादी का तर्क दिया है। उन्होंने ग्राहकों से उनकी शरबत को सबसे आगे रखने की अपील की है, इसके साथ ही बाबा रामदेव द्वारा एक वीडियो में किए गए शरबत जिहाद के दावे को लेकर आलोचना भी दी गई है। बाबा रामदेव के वीडियो में उन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक्स को टॉयलेट क्लीनर के जैसा बताया है, और उन्होंने इसे गर्मियों में प्यास बुझाने के बहाने से जहर के समान बताया है। इसी कंटेंट में रामदेव ने कहा है कि एक शरबत बेचने वाली कंपनी अपने कमाई का हिस्सा मस्जिद और मदरसे बनाने में खर्च करती है, जिसे उन्होंने शरबत जिहाद कहा है। यह कंट्रोवर्शल बयान ने लोगों में मीडिया और सामाजिक मंचों पर बहुत ही चर्चा का विषय बन दिया है। बाबा रामदेव की शरबत जिहाद पर आलोचना और पतंजलि की धर्म पर आधारित विज्ञापन ने भारतीय समाज में खुद विचार करने पर मजबूर कर दिया है। विज्ञापनों और सोशल मीडिया के इस युद्ध ने भारतीय जनता को इस सच्चाई का सामना करने पर मजबूर किया है कि किस तरह कंपनियां अपने उत्पादों को बेचने के लिए अलग-अलग रास्ते चुन रही हैं ।

अमेरिका ने स्मार्टफोन और लैपटॉप पर टैरिफ हटाया

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्मार्टफोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ को हटा दिया है, जिससे वैश्विक टेक जगत में एक उत्साहपूर्ण तेजी की लहर दौड़ गई है। यह नया फैसला 5 अप्रैल से लागू हो गया है और एप्पल, सैमसंग, जैसे बड़ी कंपनियों के लिए एक प्रकार से राहत की किरण बन सकता है। इस निर्णय से कुछ देश अवसरों से भरपूर महसूस कर रहे हैं, हालांकि चीन को तुरंत लाभ मिलेगा। चीन ने अमेरिका के टैरिफ बढ़ाने का जवाब देकर अपने द्वारा भी ऐसे उत्पादों पर कर बढ़ा दिया है जिससे अमेरिका को चीनी उत्पादों में सस्ताई की संभावना है। भारत के लिए भी इस निर्णय से अवसर है, लेकिन भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह इस अवसर का सही तरीके से फायदा उठा सके और इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में अपनी पकड़ मजबूत कर सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस निर्णय से भारत को नया धारा मिल सकता है और वह इसे अच्छे से उपयोग कर सकता है ।

पेट्रोल-डीजल रिफाइन करने पर होने वाली कमाई ऐतिहासिक स्तर पर, पेट्रोल-डीजल से केंद्र और राज्य सरकारों ने 5 साल में 35 लाख करोड़ जुटाए

नई दिल्ली। कच्चे तेल की कीमतें चार साल के सबसे निचले स्तर (65.41 डॉलर प्रति बैरल) आ गई हैं। इससे पहले अप्रैल 2021 में दाम 63.40 डॉलर प्रति बैरल थे। इस गिरावट से पेट्रोल-डीजल रिफाइन करने पर होने वाली कमाई ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया है। रेटिंग एजेंसियों के अनुसार मौजूदा समय में तेल कंपनियों को पेट्रोल पर प्रति लीटर 12-15 रुपए और डीजल पर रुपए 6.12 का मुनाफा हो रहा है। इसके बावजूद, तेल कंपनियों ने पिछले एक साल से पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई कटौती नहीं की है। हाल ही में संभावना थी कि तेल कंपनियां दाम घटाएंगी। लेकिन सरकार ने 2 रुपए लीटर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। इसकी आड़ में कंपनियां दाम घटाने से बच गईं। लंबे समय से तेल कंपनियां घाटे का हवाला देकर दामों में कटौती से बच रही हैं। जबकि, हकीकत ये है कि पिछले 5 सालों में 7 बड़ी तेल-गैस कंपनियों में केवल एक आईओसी को एक बार 2019-20 में मामूली घाटा हुआ था। इसे छोड़ दिया जाए तो ये कंपनियां साल दर साल भारी मुनाफा कमा रही हैं।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

सुप्रीम कोर्ट...

संविधान का अनुच्छेद 143 (1) कहता है कि यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की आशंका है, जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन होगा तो वह उस प्रश्न पर विचार करने के लिए न्यायालय को निर्देशित करेगा और वह न्यायालय, ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है, राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित करेगा। संविधान के अनुच्छेद 124 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। इसमें तब सुप्रीम कोर्ट के लिए एक मुख्य न्यायाधीश और इसके साथ ही 7 अन्य न्यायाधीश की बात कही गई थी। अनुच्छेद 145(3) में साफ कहा गया है कि ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए न्यूनतम पांच जज होंगे। यानी कुल 8 जजों में से कम-से-कम 5 जज यानी कम-से-कम 62 प्रतिशत जज शामिल रहेंगे। ताजा फरमान जारी करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पीठ में सिर्फ दो जज थे। अब अगर अनुच्छेद 143 को ध्यान में रखें तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जजों की कुल 33 में से कम-से-कम 21 न्यायाधीश शामिल होने चाहिए थे, जो इस तरह के संवैधानिक मामले पर सुनवाई करें। इतना ही नहीं, वर्तमान निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 200 और 201 में समय-सीमा का प्रावधान जोड़ा है, जो यह उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। यह एक तरह से व्याख्या के रूप में संविधान का संशोधन है। जबकि संविधान संशोधन का अधिकार सिर्फ और सिर्फ विधायिका को है। भारत के संविधान में उसके अनुच्छेद 368 के तहत ही संशोधन किया जा सकता है। इसके अलावा किसी अन्य तरीके से संविधान में संशोधन का प्रा-वधान नहीं है। न्यायालय सिर्फ कानून का संरक्षक है, उसका निर्माता नहीं है।

संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार, राज्य का राज्यपाल विधानमंडल का हिस्सा होता है। राज्यपाल जब किसी बिल पर सहमति देता है तो वह कानून बन जाता है। इस तरह, कानून बनाने, उसे पारित करने और उस पर सहमति देने का कार्य पूरी तरह से विधायी प्रक्रिया का हिस्सा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया निर्णय विधायी प्रक्रिया में न्यायपालिका का सीधा हस्तक्षेप है। संविधान का अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों के खिलाफ अदालती कार्यवाही से सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उन्हें नोटिस जारी करके या अन्य तरीके से जवाब नहीं मांग सकता है। जब सुप्रीम कोर्ट उनसे जवाब नहीं मांग सकता है तो उनकी बात सुने बिना उन पर टिप्पणी करना, उन्हें आदेश और निर्देश देना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सीधा उल्लंघन है। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति को दिया गया निर्देश लोकतंत्र के लिए अत्यंत आश्चर्यजनक, दुखद और शर्मनाक है। भारत संघ का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। संविधान का अनुच्छेद 79 कहता है कि संघ (भारत) के लिए एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम लोकसभा और राज्यसभा होंगे। देश का शासन भी राष्ट्रपति के नाम से प्रधानमंत्री द्वारा संचालित होता है, जिसका एक हिस्सा न्यायपालिका है। सुप्रीम कोर्ट के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। अनुच्छेद 124 (2) के अनुसार, राष्ट्रपति अपनी मुद्रा और हस्ताक्षर सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा।

नियुक्ति ही नहीं, बल्कि महाभियोग के बाद जजों का निष्कासन या फिर पद से त्याग-पत्र भी राष्ट्रपति के नाम से होता है। संविधान के अनुच्छेद 124(2)(क) के अनुसार, कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। ऐसे में भारत संघ के प्रमुख के मांगने पर सुप्रीम कोर्ट सलाह दे सकता है, लेकिन निर्देश नहीं दे सकता है। जिस सुप्रीम कोर्ट में किसी व्यक्ति को मृत्युदंड जैसी सजा दी जाती है, उस सजा को क्षमा करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। संविधान का अनुच्छेद 72(2) इसका प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद के अनुसार, राष्ट्रपति को किसी अपराध में दोषसिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रविलंबन, विराम या परिहार करने की अथवा दंडादेश के निलंबन कर सकता है। इतना ही नहीं, संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राष्ट्रपति तो दूर की बात है, राज्यपाल तक पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। राष्ट्रपति इस देश के शासन का प्रमुख ही नहीं होता, जिसका एक हिस्सा न्यायपालिका भी है, बल्कि वह सेना का सर्वोच्च कमांडर भी होता है। सैन्य निर्णयों के मामलों को संविधान के अनुसार चुनौती नहीं दी जा सकती है।

संविधान के अनुच्छेद 136(2) के अनुसार, सशस्त्र बलों से संबंधित किसी विधि द्वारा या उसके अधीन गठित किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, अवध-ारणा, निर्णय, दंडादेश या आदेश लागू नहीं होगी। जब संसद के किसी सदस्य पर सदन में कही गई बातों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। अनुच्छेद 105 (2) के अनुसार, संसद में या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध संसद के किसी सदन के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन, पत्र, मत या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। संविधान के अनुच्छेद 143(1) में साफ कहा गया है कि राष्ट्रपति किसी विषय पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करने के लिए उसे न्यायालय को निर्देशित कर सकते हैं। ऐसे में राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित करना स्पष्ट तौर पर न्यायपालिका का हस्तक्षेप या घुसपैठ है।

राज्यपाल की...

तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और तमिल यूनिवर्सिटी समेत विश्वविद्यालयों में संशोधनों के तहत गवर्नर और चांसलर शब्दों की जगह सरकार शब्द का इस्तेमाल किया गया है। राज्य के पास अब कुलपतियों को उनके पदों से हटाने का अधिकार भी होगा।केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। आर्लेकर ने कहा, अगर संविधान संशोधन सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाता है, तो फिर विधायिका और संसद की क्या जरूरत है। अगर सब कुछ अदालतों द्वारा तय किया जाता है, तो संसद की जरूरत खत्म हो जाती है। यह न्यायपालिका का अतिक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को बड़ी बेंच को सौंपना चाहिए था न कि खंडपीठ इस पर फैसला लेती।

केरल के राज्यपाल के इस बयान पर राजनीति गरमा गई है। कांग्रेस और केरल की सत्ताधारी पार्टी सीपीआईएम ने राज्यपाल की आलोचना की है। सीपीआईएम के महासचिव एमए बेबी ने राज्यपाल के बयान को अवांछित बताया और कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने आर्लेकर के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कोझिकोड में एक कार्यक्रम के दौरान केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डर है कि अब भाजपा का एजेंडा खुलकर सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण कि केरल के राज्यपाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ हैं।सीपीआईएम नेता एमए बेबी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी पर लागू होगा, जिसमें राष्ट्रपति भी शामिल हैं। जब राष्ट्रपति संसद के विधेयक में देरी नहीं कर सकते तो फिर राज्यपाल के पास वो अधिकार कैसे हो सकता है, जो राष्ट्रपति के पास नहीं है? बेबी ने कहा कि सभी राज्यपालों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले को स्वीकार करना चाहिए, लेकिन केरल राज्यपाल के बयान से साफ है कि उन्हें यह स्वीकार नहीं है। उनका सुप्रीम कोर्ट की आलोचना करना गलत है।

वक्फ कानून...

जिसमें शमशेरगंज में पिता-पुत्र की हत्या भी शामिल है। पुलिस ने अब तक 138 लोगों को गिरफ्तार किया है।उल्लेखनीय है कि मुर्शिदाबाद में हिंसा की दिल दहलाने वाली घटना घटी। इस्लामिक उन्मादियों ने मूर्तियां गढ़ने वाले माटी कलाकार हरगोविंद दास (पिता) और चंदन दास (बेटे) को धारदार हथियार से काट कर मार डाला। वे मूर्तिकार थे और देवी-देवताओं की मूर्तियां बनाते थे। उनके घर में इस्लामी कट्टरपंथियों ने लूटपाट की और उसके बाद धारदात हथियारों से उनकी हत्या कर दी। तस्वीरों में दिख रहा है कि उनकी आंख पर भी हमला किया है, यानि जिन आंखों से देखकर वो देवी-देवताओं की मूर्तियां गढ़ा करते थे, नफरत की आग में इस्लामी कट्टरपंथियों ने उनकी आंखें भी फोड़ दीं। इस उन्मादी हिंसा ने मुर्शिदाबाद के हिंदुओं को गहरे जख्म दिए हैं। उनके घर, दुकानें और आजीविका सब तबाह हो गए।मुर्शिदाबाद में बेकाबू हिंसा के कारण सैकड़ों हिंदू परिवार नदी पार कर मालदा में शरण ले रहे हैं। केंद्रीय बलों की मदद से नदी पार कर हिंदू परिवारों ने मालदा जिले में शरण ली है। वहां पीड़ित लोगों के लिए स्कूलों में अस्थायी ठहरने और खाने-पीने की व्यवस्था की है। मुर्शिदाबाद जिले के कई इलाकों जैसे सूती, धूलियन, जंगीपुर और समसेरगंज में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी है। यह क्षेत्र मुस्लिम-बहुल है और प्रदर्शन धीरे-धीरे सांप्रदायिक दंगे में बदल गया है। धूलियन के मंदिरपाड़ा इलाके से भागी एक महिला ने बताया, हमारे घर जला दिए गए। कुछ बाहरी और स्थानीय लोगों ने मिलकर महिलाओं और लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार किया, पुरुषों को पीटा गया। हमें कहा गया कि हम इलाके को छोड़ दें। हमारी जान को खतरा था, इसलिए हमने केंद्रीय बलों की मदद से घर छोड़ा। धूलियन से करीब 400 हिंदू नागरिक डर के मारे भागकर भागीरथी नदी पार कर मालदा जिले के बैष्णवनगर इलाके में पहुंचे हैं। उन्हें पर लालपुर हाई स्कूल में ठहराया गया है। कई स्वयंसेवी संगठन इनकी मदद कर रहे हैं। मालदा में एक स्वयंसेवी संगठन के सदस्य ने बताया कि अब तक 40 से 50 नावों में लोग धूलियन, सुईटी और जंगीपुर जैसे इलाकों से आए हैं। इन सभी को कालीचक तीन ब्लॉक के पल्लरपुर गांव में सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। उन्होंने कहा, यहां वे पूरी तरह सुरक्षित हैं।

वक्फ कानून लागू होने से कट्टरपंथी जमातों का गुस्सा पूरे देश में फैलता जा रहा है। मध्य प्रदेश के गुना जिले में शनिवार को हनुमान जयंती के जुलूस पर जबरदस्त पथराव किया गया। जुलूस कर्नलगंज में मस्जिद के पास से गुजर रहा था, तभी जुलूस पर भारी पथराव किया गया। पथराव की पहले से तैयारी थी। दूसरी तरफ केरल के कोझिकोड में वक्फ बिल के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान इस्लामी कट्टरपंथियों ने हमास और मुस्लिम ब्रदरहुड जैसे संगठनों के आतंकियों की तस्वीरें लहराईं। यह मार्च करीमपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक गया, जिसे सॉलिडैरिटी यूथ मूवमेंट और स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गनाइजेशन (एसआईओ) ने आयोजित किया था। ये दोनों संगठन जमात-ए-इस्लामी से जुड़े हैं। पुलिस ने अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की है। इस घटना ने केरल की सियासत में तनाव बढ़ा दिया है।नेपाल के भारत से जुड़े हिस्सों में भी उन्मादी मुसलमान बवाल मचा रहे हैं। बिहार सीमा पर स्थित नेपाली जिला बीरगंज में मुसलमानों ने हनुमान जयंती पर निकाली गई शोभा यात्रा पर हमला बोल दिया। जबरदस्त पथराव किया और कई वाहनों में आग लगा दी। यहां भी मस्जिद से पथराव किया गया। असामाजिक तत्वों ने पुलिस बल पर भी पथराव किया। हालात को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों ने वहां पर कई राउंड आंसू गैस के गोले दागे और लाठीचार्ज किया। घटना में एक दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए।

सियाचिन के वीर ...

इस वर्ष ऑपरेशन मेघदूत की 41वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। यह दिन उन वीर सियाचिन योद्धाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की और दुश्मनों की हर कोशिश को नाकाम किया। आज भी भारतीय जवान जमे हुए सीमांत की रक्षा में तैनात हैं और अपने अटूट हौसले और निष्ठा के साथ देश की सीमाओं को सुरक्षित रख रहे हैं। ध्यान रहे कि सियाचिन में तैनात भारतीय सेना के वीर भारत माता की सुरक्षा के लिए माइनस 50 डिग्री तापमान, तेज बर्फीली हवाएं और बेहद कठिन इलाके का सामना करते हुए हर पल देश की सुरक्षा में जुटे रहते हैं।

ऑपरेशन मेघदूत में भारतीय वायुसेना की एक अतुलनीय भूमिका रही। वायुसेना ने एएन-12, एएन-32 और आईएल-76 जैसे एयरक्राफ्ट के जरिए सैनिकों और सामान को ऊंचाई वाले हवाई क्षेत्रों तक पहुंचाया। इसके बाद एमआई-17, एमआई-8, चेतक और चीता हेलिकॉप्टरों की मदद से सैनिकों को ग्लेशियर की ऊंची चोटियों तक पहुंचाया गया। इतना ही नहीं वायुसेना के हेलीकॉप्टर 1978 से ही सियाचिन में उड़ान भर रहे हैं, और चेतक हेलिकॉप्टर पहला ऐसा भारतीय हेलिकॉप्टर था जो अक्टूबर 1978 में वहां उतरा था।सियाचिन ग्लेशियर का क्षेत्र पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके), अक्सई चिन और शक्सगाम घाटी से सटा हुआ है, जिसे पाकिस्तान ने 1963 में चीन को सौंप दिया था। यह भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण इलाका है क्योंकि इससे दुश्मन की हरकतों पर नजर रखी जा सकती है। इसके साथ ही यह स्थान लेह से गिलगित आने-जाने वाले रास्तों को भी नियंत्रित करता है, जिससे इसकी सैन्य और रणनीतिक अहमियत और बढ़ जाती है।

बांग्लादेश में हिंदू ...

अब से इसे वरशावरन आनंद शोभायात्रा कहा जाएगा। इसी प्रकार कट्टरपंथियों को मंगल शब्द से भी नफरत हो गई है। मुहम्मद यूनुस की कट्टरपंथी सरकार हिंदू प्रतीकों, हिंदू शब्दों, उसकी पहचान का क्रूरता के साथ सिस्टमैटिक तरीके से दमन कर रही है। अपने इस कदम को वह नए बांग्लादेश की समावेशी नीति करार देती है। जिस मंगल शोभायात्रा को यूनेस्को ने 2016 में अमूर्त विरासत घोषित किया था। उसे ही सरकार ने कुचल दिया। बंगाली नववर्ष पोहिला बोइशाख को भी कुचलने की कोशिश हो रही है। अपने इस कदम को जस्टिफाई करते हुए देश की अंतरिम सरकार के सांस्कृतिक सलाहकार मुस्तफा सरवर फारुकी का कहना है कि ये हिंदू जन्माष्टमी के तौर पर हम पर थोपा गया है। गौरतलब है कि 5 अगस्त 2024 को बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्तापलट हो गया था। इसके बाद उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा था। इसके बाद कट्टरपंथी बीएनपी की अगुवाई में देश में अंतरिम सरकार बनी और फिर शुरू हुआ व्यवस्थागत गत तरीके से हिंदुओं समेत दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार। अगस्त से लेकर अब तक हजारों की संख्या में हिंदुओं पर हमले, हिंदू महिलाओं का बलात्कार और उनका इस्लामिक कन्वर्जन हुआ। जब इस्कॉन संत चिन्मय कृष्ण दास ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो देशद्रोह के आरोप में उन्हें जेल में डाल दिया गया।

कर्नाटक में मुसलमानों...

तो राज्य में कुल आरक्षण 85 प्रतिशत हो जाएगा। इस 85 प्रतिशत में 51 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण होगा जबकि 24 प्रतिशत आरक्षण अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए रहेगा। इसके अलावा 10 प्रतिशत आरक्षण आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानि ईडब्लूएस को पहले की तरह मिलता रहेगा। इस रिपोर्ट को लेकर राज्य में बहस चालू हो गई है।यह जातिगत जनगणना कर्नाटक पिछड़ा वर्ग आयोग ने करवाई थी। यह 2015 में एच. कांथराज के नेतृत्व में शुरू हुई थी। इसके बाद 2020 में के. जयप्रकाश हेगड़े के नेतृत्व में कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने इसे पूरा किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछड़ी जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पिछड़ा वर्ग आयोग ने ओबीसी और मुस्लिम आरक्षण को बढ़ाने की सिफारिश तो की है लेकिन एससी-एसटी तथा ईडब्लूएस आरक्षण को पहले की तरह ही रखने की बात कही है। अभी इस पर अंतिम फैसला बाकी है।कर्नाटक में मुस्लिम ओबीसी में सबसे बड़ा समूह है। राज्य में उनकी आबादी 75.25 लाख है। मुस्लिम ओबीसी कर्नाटक के ओबीसी वर्गीकरण की श्रेणी 2इ के अंतर्गत आते हैं। इसी के आधार पर रिपोर्ट में उनका आरक्षण 4 प्रतिशत से दोगुना करके 8 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई है। राज्य की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 18.08 प्रतिशत है, जो 2011 की जनगणना में 12.92 प्रतिशत बताई गई थी। सर्वे का यह आंकड़ा 2015 का है। ऐसे में 4 साल में मुस्लिम आबादी कर्नाटक में 5.16 प्रतिशत बढ़ गई। रिपोर्ट में इस आरक्षण बढ़ाने के पीछे राज्य में ओबीसी की हिस्सेदारी सबसे अधिक होना कारण बताया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि राज्य में कुल आबादी में ओबीसी की हिस्सेद-ारी 69.60 प्रतिशत है, ऐसे में उन्हें जनसंख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिएइस रिपोर्ट में आरक्षण को 50 प्रतिशत से ऊपर ले जाने के क्रम में बाधा को भी पार करने की बात की गई है। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के इंद्रा साहनी मामले में दिए गए फैसले के अनुसार, कोई भी राज्य 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दे सकता है। ईडब्लूएस आरक्षण इससे अलग है। यदि कर्नाटक के पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश मानी गई तो यह आरक्षण 50 प्रतिशत से कहीं अधिक 85 प्रतिशत हो जाएगा। रिपोर्ट में इसके लिए झारखंड और तमिलनाडु का उदाहरण दिया गया है, जहां पहले ही 77 प्रतिशत और 69 प्रतिशत आरक्षण दिया जा चुका है। रिपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के इन्द्रा साहनी फैसले को आज के समय में प्रांसगिक ना होना बताया गया है।कर्नाटक में आरक्षण पर से सीमा हटाने की बात ऐसे समय हो रही है जब राहुल गांधी हाल ही में इसकी वकालत कर चुके हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि उनकी पार्टी भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित 50 प्रतिशत आरक्षण की दीवार तोड़ने के पक्ष में है। कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण बढ़ाने की सिफारिश और मुस्लिमों को अपने पाले में करने की कोशिश कांग्रेस की चुनावी तैयारी के तौर पर देखी जा रही है। कर्नाटक में ओबीसी आरक्षण पर हो रही यह पूरी कवायद अहिन्दा-वोट साधने की तरकीब मानी जा रही है। राज्य में ओबीसी, मुस्लिम और एससी-एसटी वोट को मिला कर अहिन्दा-वोट बैंक का नाम दिया जाता है। अहिन्दा शब्द कांग्रेस के बड़े नेता देवराज उर्स ने दिया था। वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्दारमैया इस फ़ॉर्मूला पर काम करते आए हैं। कांग्रेस चाहती है कि वह ओबीसी, मुस्लिम और दलित वोटरों में इन सब कदम से वह और मजबूत हो जाए, जिससे आगामी चुनावों में उसे आसानी हो। जातिगत जनगणना में आरक्षण की सिफारिश के अलावा हाल ही में मुस्लिमों को राज्य में ठेकों में आरक्षण दिया गया था। यह भी इसी दिशा में एक कदम माना गया था।राज्य यह अहिन्दा-वोट लिंगायत और वोक्कालिगा समुदाय से इतर है। लिंगायत परंपरागत रूप से भाजपा जबकि वोक्कालिगा जेडी (एस) के वोटर रहे हैं। वर्तमान में यह दोनों पार्टियां साथ में हैं, ऐसे में कांग्रेस की चिंताएं और भी बढ़ गई हैं। ऐसे में वह इन दोनों समुदाय से इतर अपना अहिन्दा-वोट बैंक को बचाए रखना चाहती है।

पश्चिमी सीमा पर...

उनकी निस्वार्थ सेवा तथा निरंतर योगदान के लिए उन्हें सम्मानित करना था।

उन्होंने बताया कि सेना प्रमुख ने सीमा और भीतरी इलाकों की सुरक्षा में भारतीय वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल, पंजाब पुलिस और अन्य हितधारकों के बीच निर्बाध तालमेल पर संतोष व्यक्त किया। उनके साथ मौजूद सेना महिला कल्याण संघ की अध्यक्ष सुनीता द्विवेदी ने परिवारों और भूतपूर्व सैनिकों की भलाई के लिए वज्र कोर की तरफ से की जा रही कई कल्याणकारी पहलों की समीक्षा की, जो कल्याण और सामुदायिक समर्थन के प्रति सेना के समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है।

सूर्य आज करेंगे अपनी उच्च राशि मेष में गोचर

सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करना संक्रांति कहलाता है। वर्तमान समय में सूर्य मीन राशि में हैं। सूर्य के धनु और मीन राशि में रहने पर खरमास लगता है। इस दौरान कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है। अतः शादी-विवाह समेत सभी मांगलिक कार्य नहीं किए जा रहे हैं। 14 अप्रैल को सूर्य मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। उस दिन से शुभ कार्य किए जा सकते हैं। श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन अजमेर की निदेशिका ज्योतिषाचार्या एवं टैरो कार्ड रीडर नीतिका शर्मा ने बताया कि 14 अप्रैल को ग्रहों के राजा सूर्य मेष राशि में गोचर करेंगे। सूर्य आत्मा का कारक माना जाता है। सूर्य के मजबूत रहने से करियर और कारोबार में मन मुताबिक सफलता मिलती है। व्यक्ति ऊंचा मुकाम हासिल करने में कामयाब होता है। इसके लिए ज्योतिष लोगों को सूर्य मजबूत करने की सलाह देते हैं। सूर्य को मजबूत करने के लिए रोजाना सूर्य देव को जल का अर्घ्य दें। साथ ही सूर्य चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा, पिताजी के साथ संबंध मधुर रखना चाहिए। पिता के आशीर्वाद से जातक अपने जीवन में खूब तरक्की और उन्नति करता है।

ग्रहों के राजा कहे जाने वाले सूर्य देव 14 अप्रैल को मीन राशि से निकलकर मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में सूर्य उच्च का फल देते हैं। ज्योतिष में सूर्य को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। सूर्य को आत्मा और पिता का कारक भी कहा गया है। सूर्य शुभ होने पर व्यक्ति को उच्च पद की प्राप्ति होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को सिंह राशि का स्वामी माना गया है। मेष इसमें उच्च माना जाता है। वहीं सूर्य तुला राशि में नीच का हो जाता है।

मीन से निकलेंगे सूर्य

सूर्य 14 अप्रैल को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। जहां पर ये इस राशि में 14 मई तक रहेंगे। मेष राशि सूर्यदेव की उच्च की राशि होते हैं और इस राशि के स्वामी ग्रह मंगल होते हैं। वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कोई भी ग्रह जब अपनी उच्च राशि में रहता है तब इसका शुभ फल जातकों के जीवन पर पड़ता है। सूर्य के उच्च की राशि में गोचर करने से कई राशि के लोगों को फायदा मिलने के संकेत हैं।

शुरू होंगे मांगलिक कार्य

सूर्य देव के मीन राशि में गोचर से मीन मलमास प्रारंभ हो जाता है । जिसकी वजह एक माह तक यानी सूर्य के मीन राशि में रहते विवाह आदि मंगल कार्यों पर रोक लग जाती है। सूर्य के मीन से निकलकर मेष राशि में गोचर के साथ मीन मलमास समाप्त हो जायेगा और इसकी वजह से रुके हुए मांगलिक कार्यक्रम, विवाह आदि फिर से शुरू हो जाएंगे।

देश-दुनिया पर असर

शेयर बाजार में गिरावट के साथ बिजनेस की गति कुछ थमेगी। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि के साथ शेयर बाजार फिर से बढ़ने की भी संभावना रहेगी। इससे अर्थव्यवस्था मजबूत होने के योग बनेंगे। राजनीतिक उथल-पुथल एवं प्राकृतिक आपदाओं की आशंका बढ़ेगी। लोगों को विशेष लाभ मिलेगा। शिक्षा प्रणाली में सुधार के भी योग बनेंगे। धरना जुलूस प्रदर्शन आंदोलन गिरफ्तारियां होगी। रेल दुर्घटना होने की संभावना। महिलाओं के लिए समय शुभ नहीं है। कोई बड़ी फिल्म अभिनेत्री से दुखद समाचार। देश और दुनिया में राजनीतिक बदलाव होंगे। सत्ता संगठन में परिवर्तन होगा। आरोप-प्रत्यारोप का दौर चलेगा। मनोरंजन फिल्म नाटक फैशन डांसर कॉमेडी चर्चा में रहेंगे।

उपाय

श्री विष्णु की उपासना करें। बंदर, पहाड़ी गाय या कपिला गाय को भोजन कराएं। रोज उगते सूर्य को अर्घ्य देना शुरू करें। रविवार के दिन उपवास रखे। रोज गुढ़ या मिश्री खाकर पानी पीकर ही घर से निकलें। जन्मदाता पिता का सम्मान करें, प्रतिदिन उनके चरण छुकर आशीर्वाद लें । भगवान सूर्य की स्तुति आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें ।

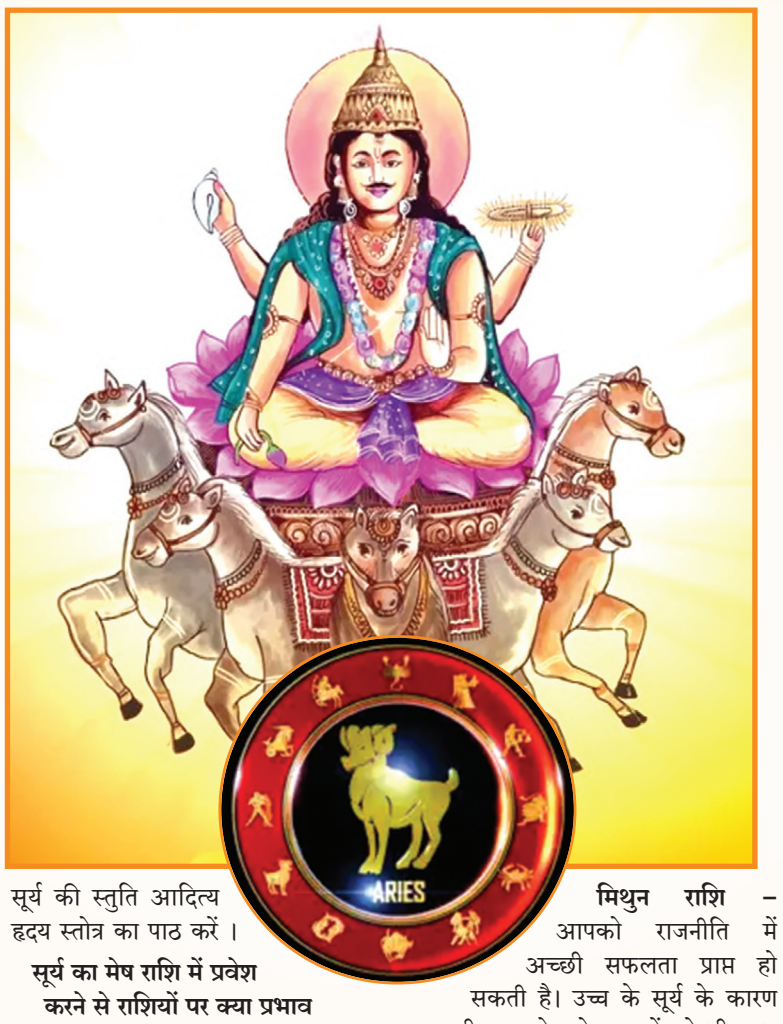

सूर्य का मेष राशि में प्रवेश करने से राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

मेष राशि – सरकार और राजनीति से जुड़े लोगों को अच्छा फायदा होने की उम्मीद है। वैवाहिक जीवन में थोड़ा तनाव दिखाई पड़ रहा है इसलिए पत्नी के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद को जन्म नहीं दे।

वृष राशि – मानसिक तनाव और परिवार की ओर से कष्ट संभव है। इस गोचर के दौरान आपके खर्च में वृद्धि होगी और विदेश यात्राओं से कोई ख़ास लाभ नहीं होगा। इस समय आपके अपनी मां के साथ रिश्तें बिगड़ सकते हैं।

मिथुन राशि – आपको राजनीति में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। उच्च के सूर्य के कारण सरकारी काम से जुड़े जातकों को भी लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार के साथ यात्रा का योग दिखाई दे रहा है।

कर्क राशि – कार्यस्थल पर उच्च पद देने का काम करने वाली है। किसी काम के सिलसिले में यात्रा भी करेंगे। इस समय आपके घर में किसी मांगलिक आयोजन का मौका भी बन सकता है।

सिंह राशि – धार्मिक यात्रा पर जाने का मौका मिलने वाला है। पिता के साथ आपके मतभेद सामने आ सकते हैं वहीं उनकी सेहत का भी ध्यान रखना होगा। कई समय से अटका हुआ निवेश इस समय पूरा हो सकता है।

कन्या राशि – इस समय आपको चोट लगने की आशंका है वही किसी बीमारी का भी आगाज़ जीवन में हो सकता है। इस समय किसी को धन उधार नहीं दे वरना आपका पैसा अटक सकता है।

तुला राशि – आप अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और आलस्य को त्याग दें। सरकार से जुड़कर आप कोई अच्छा काम शुरू कर सकते हैं। इस समय किसी मित्र के साथ कोई काम शुरू करना चाह रहे है तो उसे टाल दें।

वृश्चिक राशि – आपके सभी शत्रुओं का नाश होगा। इस समय आप अपने कार्यस्थल पर लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। आपके जीवन में इस समय विदेश यात्रा और धन लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं।

धनु राशि – प्रेम और शिक्षा का विचार होता है। इस समय छात्र वर्ग को पढ़ाई में समस्या आ सकती है। प्रेम प्रसंग असफल हो सकते हैं। इस समय आपको सलाह दी जाती है कि अपने प्रेमी को धोखा न दें।

मकर राशि – आपके लिए समय बेहद कठिन होने वाला है। आपके खिलाफ शत्रु साजिश करेंगे। इस समय आप किसी भी प्रकार की कोई आर्थिक डील न करें तो अच्छा होगा। इस दौरान आपके खर्चों में वृद्धि होगी।

कुंभ राशि – आपके साहस में वृद्धि होगी और आपकी यात्राओं से आपको फायदा होगा। इस समय धार्मिक यात्राओं के योग भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो जातक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय शुभ है।

मीन राशि – आपकी वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है। इस समय आपको वाहन चलाते समय भी सावधानी रखनी है। ससुराल पक्ष से कोई भी आर्थिक लेनदेन नहीं करने की सलाह आपको दी जाती है।

इन राशियों पर पड़ेगा बुरा असर

तुला राशि – सूर्य का गोचर वृषभ राशि में हो रहा है। ऐसे में तुला राशि के जातकों को सबसे अधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इन्हें स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही कार्यक्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके बुरे प्रभाव से बचने के लिए सूर्य देव के वैदिक मंत्रों का जाप करें।

मकर राशि – मकर राशि के जातकों को भी सूर्य के गोचर के दौरान सावधानी रखने की जरूरत है। इस दौरान इस राशि के लोगों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। साथ ही पारिवारिक जीवन में भी तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में भगवान सूर्य को रोजाना अर्घ्य दें।

वृश्चिक राशि – वृश्चिक राशि के जातकों को भी सूर्य के गोचर के दौरान सतर्क रहना चाहिए। इस दौरान इन्हें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही क्रोध पर नियंत्रण रखने की सलाह दी जाती है। साथ ही सूर्य देव के कवच का पाठ करें।

सूर्य गोचर के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

- अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
- क्रोध पर नियंत्रण रखें।
- किसी भी प्रकार के वाद-विवाद से बचें।
- वाहन चलाते समय सावधानी बरतें।
- रोजाना सूर्य देव की पूजा विधि अनुसार करें।
- सूर्य को अर्घ्य दें।

नीतिका शर्मा
ज्योतिषाचार्या एवं फेमस टैरो कार्ड रीडर
श्री लक्ष्मीनारायण एस्ट्रो सॉल्यूशन अजमेर, अजमेर

आज मेष संक्रांति और 16 को संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी

वैशाख माह की शुरुआत आज यानी 13 अप्रैल से हो गई है और अब इस माह का नया सप्ताह भी कुछ ही समय में शुरू होने वाला है। धार्मिक दृष्टि से वैशाख माह के पहले सप्ताह को अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इस सप्ताह में कई व्रत और पर्व मनाए जाएंगे, जिनका विशेष महत्व है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि इस सप्ताह में पड़ने व्रत-त्योहारों की डेट और शुभ मुहूर्त के बारे में।

मेष संक्रांति २०२५ शुभ मुहूर्त

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन की तिथि पर संक्रांति मनाई जाती है। इस बार 14 अप्रैल को मेष संक्रांति मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे।

विकट संकष्टी चतुर्थी २०२५ शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 16 अप्रैल को दोपहर 01 बजकर 16 मिनट से शुरू होगी और 17 अप्रैल को दोपहर 03 बजकर 23 मिनट पर खत्म होगी। इस प्रकार 16 अप्रैल को विकट संकष्टी चतुर्थी मनाई जाएगी।

मासिक जन्माष्टमी २०२५ शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 20 अप्रैल को शाम 07 बजे शुरू होगी और 21 अप्रैल को शाम 06 बजकर 58 पर खत्म होगी। अष्टमी तिथि पर जगत के पालनहार भगवान श्रीकृष्ण की पूजा निशा काल में करने का विधान है। ऐसे में मासिक कृष्ण जन्माष्टमी 20 अप्रैल को मनाई जाएगी। इसी दिन कालाष्टमी का पर्व भी भी मनाया जाएगा। कालाष्टमी के दिन काल भैरव की पूजा-अर्चना करने का विधान है।

वैशाख माह में करें इन मंत्रों का जप

ॐ बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद् द्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु ।
यद्दीदयच्दवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्।।
वृंदा,वृन्दावनी,विश्वपुजिता,विश्वपावनी ।
पुष्पसारा,नंदिनी च तुलसी,कृष्णजीवनी ।।
एत नाम अष्टकं चैव स्त्रोत्र नामार्थ संयुतम ।
य:पठेत तां सम्पूज्य सोभवमेघ फलं लभेत।।
ॐ वासुदेवाय विघ्माहे वैधयाराजाया धीमहि तन्नो धन्वन्तरी प्रचोदयात् ।।
ॐ तत्पुरुषाय विद्महे अमृता कलसा हस्थाया धीमहि तन्नो धन्वन्तरी प्रचोदयात् ।।

पत्नी क्रोधित होती है तो पति क्यों डर जाते हैं!

जानें कैसे शुरू हुआ यह सिलसिला

पत्नियां अक्सर घर लेट आने पर, कोई खास दिन या समान भूलने पर अपने जीवनसाथी से क्रोधित हो जाती हैं। उनका गुस्सा दूर से ही देखकर पति डर जाते हैं। ऐसी छोटी-मोटी नोक-झोक अक्सर पति-पत्नी के बीच होती रहती है। यह रुठने-मनाना आज से ही नहीं बल्कि बहुत पुराने समय से चला आ रहा है। इस सिलसिले की कहानी की जड़ को ढूंढेंगे तो आप भगवान शिव और देवी सती की कहानी तक पहुंच जाएंगे।

देवी सती और शिव जी की कथा में पति और पत्नी की तनातनी

यह कथा देवी सती से संबंधित है। देवी सती ने पिता दक्ष की इच्छुक के विरुद्ध जाकर शिवजी से विवाह किया था, लेकिन उनके पिता दक्ष प्रजापति शिवजी को पसंद नहीं करते थे। ऐसे में वह हर समय भगवान शिव को अपमानित करने की तरकीब लगाते रहते थे। एक बार देवी सती के पिता दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया। जिसमें देवी सती और शिवजी को छोड़कर सभी देवी देवता और ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया था। यह बात जैसे ही सती तक पहुंची वह तुरंत अपने पिता के यहां यज्ञ में जाने के लिए तैयार हो गईं। शिवजी ने देवी सती को समझाया, हमें वहां बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। इस पर देवी सती ने कहा कि पिता के पास जाने के लिए आमंत्रण की जरूरत नहीं होती है। और वह पिता के यज्ञ में जाने के लिए हठ कर बैठीं।

शिवजी के बार-बार मना करने और समझाने पर पर देवी सती को क्रोध आ गया। इसके बाद देवी सती अपने आदिशक्ति रूप में प्रकट हो गईं और और इन्हें ने दसों दिशाओं से दस देवियों को प्रकट किया और जो दश महाविद्याएं कहलायीं। इन महाशक्तियों ने दसों दिशाओं से शिवजी को घेर लिया जिससे शिवजी भी घबरा गए तब देवी का क्रोध शांत हुआ। और शिवजी को न चाहते हुए भी देवी सती को पिता दक्ष के यज्ञ में जाने दिया। और यहीं से सभवतः पत्नी से पतियों के डर का सिलसिला शुरू हुआ। तो बताइए कैसी लगी आपको यह रोचक कथा।

अक्षय तृतीया पर करें इन वस्तुओं का दान, दूर होगी आर्थिक तंगी

अक्षय तृतीया का पर्व हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन लोग मां लक्ष्मी की विशेष पूजा-अर्चना करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया कोई भी काम शुभ फल देता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल को मनाया जाएगा। कहते हैं कि इस दिन दान जरूर करना चाहिए। इससे अन्न और धन में बरकत होती है, तो चलिए यहां जानते हैं कि इस मौके पर क्या दान करना शुभ माना जाता है।

अक्षय तृतीया पर दान का महत्व

अक्षय तृतीया पर दान करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन दान करने से भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और सभी दुखों का नाश होता है। हिंदू धर्म में दान का विशेष महत्व है। ऐसे में इस दिन ज्यादा से ज्यादा दान करें, लेकिन दान करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसके बारे में किसी को जानकारी न हो।

अक्षय तृतीया पर करें ये दान

अन्न – अक्षय तृतीया पर अन्न का दान सबसे महत्वपूर्ण दान माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मौके पर अन्न का दान करने से घर में बरकत आती है।

वस्त्र – अक्षय तृतीया पर वस्त्र का दान भी बहुत शुभ माना गया है। ऐसे में जरूरतमंदों को कपड़ों का दान जरूर करें।

सोना-चांदी- इस दिन सोने और चांदी का दान भी अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और धन और समृद्धि प्रदान करती हैं।

छाता – अक्षय तृतीया के दिन छाता का दान भी बहुत ही अच्छा माना जाता है। ऐसा करने से जीवन में आने वाली मुश्किलों का अंत होता है।

दान करते समय इन बातों का रखें ध्यान

दान करते समय मन में कोई गलत भाव न रखें।
दान करने के लिए हमेशा अच्छी वस्तुओं का उपयोग करें।
जरूरतमंदों को ही दान करें।
दान करते समय किसी भी प्रकार के अहंकार से बचें।

सोने-चांदी का नहीं है बजट, तो अक्षय तृतीया पर लें ये चीजें

अक्षय तृतीया का पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष माना जाता है। इस दिन सोना-चांदी खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपका बजट सोना-चांदी खरीदने का नहीं है, तो आप अक्षय तृतीया पर अन्य शुभ चीजें भी खरीद सकते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल अक्षय तृतीया का पर्व 30 अप्रैल को मनाया जाएगा।

अक्षय तृतीया पर खरीदें ये शुभ चीजें

मिट्टी के बर्तन – अक्षय तृतीया पर मिट्टी के बर्तन खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। मिट्टी को शुद्ध और पवित्र माना जाता है। इसलिए, मिट्टी के बर्तन खरीदने से घर में सुख-समृद्धि आती है।

पीतल के बर्तन – पीतल के बर्तन भी अक्षय तृतीया पर खरीदना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि पीतल के बर्तन खरीदने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है।

धार्मिक पुस्तकें – अक्षय तृतीया पर धार्मिक पुस्तकें खरीदना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं, इस मौके पर शास्त्र पढ़ने से ज्ञान और सकारात्मकता बढ़ती है।

तुलसी का पौधा – अक्षय तृतीया पर पौधे लगाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में इस मौके पर तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। ऐसा करने से घर में सुख-शांति बनी रहती है।

श्री यंत्र – अक्षय तृतीया पर श्री यंत्र खरीदना बहुत अच्छा माना जाता है। श्री यंत्र को धन और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आप इसे भी खरीद सकते हैं।

कौड़ी – अक्षय तृतीया पर कौड़ी खरीदना उत्तम माना जाता है। कौड़ी को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में आप इस दिन कौड़ी भी खरीद सकते हैं।

गंगाजल – गंगाजल को बहुत ही पवित्र माना जाता है। ऐसे में आप अक्षय तृतीया के दिन गंगाजल घर ला सकते हैं। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी।

अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अक्षय तृतीया को बहुत ही शुभ दिन माना जाता है, इसलिए इस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जा सकता है। अक्षय तृतीया पर सोना-चांदी खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन अगर आपका बजट नहीं है, तो आप अन्य शुभ चीजें भी खरीद सकते हैं।

कपिल शर्मा पर भड़के मुकेश खन्ना, याद किया पुराना किस्सा बोले - नया नया पैदा हुआ...!

हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान मुकेश खन्ना ने बताया कि कैसे मशहूर कॉमेडियन ने उन्हें नजरअंदाज किया। इस वजह से मुकेश ने महाभारत के एक स्पेशल एपिसोड के लिए कपिल शर्मा शो में आने से इनकार कर दिया। उनके बीच विवाद की शुरुआत अवॉर्ड फंक्शन में हुई थी। यह पूरा मामला सालों पहले गोल्ड अवॉर्ड्स में शुरू हुआ था जब कपिल, जो इंडस्ट्री में नए थे, ने करीब 20 मिनट तक उनके बगल में बैठे रहने के बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया।

कपिल ने मुकेश खन्ना को हेलो-हाय नहीं किया, तब भी जब उन्हें अवॉर्ड दिया जा रहा था। इस मुद्दे पर बात करते हुए मुकेश ने कहा, मुझे कपिल शर्मा क्यों पसंद नहीं हैं और मैंने उनके शो में जाने से क्यों इनकार कर दिया, और यह कहानी सभी के लिए एक आंख खोलने वाली कहानी होनी चाहिए, ताकि वे समझ सकें कि फिल्म इंडस्ट्री वास्तव में कैसे काम करती है।

मुकेश ने आगे कहा, गोल्ड अवॉर्ड्स में मुझे एक अवॉर्ड दिया जा रहा था और कपिल शर्मा, जो इंडस्ट्री में नया नया पैदा हुआ था इत्तेफाकन मेरे बगल में आकर बैठ गया और उसने मुझे विश तक नहीं किया। उसने मुझे इग्नोर किया। वह लगभग 20 मिनट तक वहां बैठे रहे और जैसे ही उनका नाम आया, उन्होंने अवॉर्ड लिया और घर चले गए। मुकेश ने कपिल के बर्ताव से अपमानित महसूस किया खासकर तब जब अमिताभ बच्चन और ऋतिक रोशन जैसे दूसरे इंडस्ट्री के सीनियर कलाकारों ने साथ काम ना करने के बावजूद उनका सम्मान किया है। मुकेश ने कहा, मैं अमित जी से कई बार फ्लाइट में मिल चुका हूं। मैं लंदन से वापस आ रहा था और वह भी। हम एक-दूसरे को नहीं जानते थे लेकिन वह जानते थे कि हम दोनों एक्टर हैं, इसलिए हमने बात की। ऋतिक रोशन और मैं एयरपोर्ट पर खड़े थे और वह मुझसे मिले और मुझसे कहा, 'इस समय इस एयरपोर्ट पर दो सुपरहीरो खड़े हैं।'

मुकेश खन्ना ने डबल मीनिंग वाले डायलॉग और अभद्र चुटकुलों का हवाला देते हुए कपिल शर्मा की आलोचना की। उन्होंने ना केवल अपने पिछले मुद्दों के चलते, बल्कि एक सीन के कारण भी शो में आने से इनकार कर दिया जिसमें कपिल ने शक्तिमान की ड्रेस पहनी थी। इसे मुकेश ने कैरेक्टर की वैल्यूज का अपमान माना।

फिल्म कृष 4 प्रियंका चोपड़ा हुई शामिल!

ऋतिक रोशन इन दिनों अपनी दो फिल्मों को लेकर सुर्खियों में छाए हुए हैं, पहली वॉर 2 और दूसरी कृष 4 है। इन दोनों ही फिल्मों के लिए फैंस बेहद एक्साइटेड हैं। इस बीच 'कृष 4' की रिलीज डेट को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। इसी के साथ फिल्म की शूटिंग और कहानी के बारे में जानकारी मिली है।

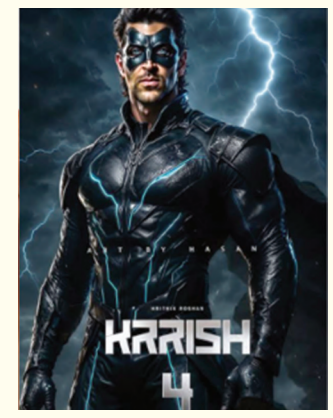

कृष 4 से जुड़े एक करीबी सूत्र के अनुसार, ऋतिक रोशन और आदित्य चोपड़ा ने प्रियंका चोपड़ा को कृष 4 की लीड एक्ट्रेस के लिए लॉक कर लिया है। सोर्स ने कहा, ऋतिक और प्रियंका एक सफल जोड़ी हैं और उनके बीच बेहतरीन वर्क रिलेशन्स है।कृष्ट 4 में PC का आना कोई बड़ी सोचने की बात नहीं थी, क्योंकि कहानी कोई मिल गया से कृष, कृष 3, और अब चौथे भाग के सफर को जारी रखती है। एक्ट्रेस, ऋतिक रोशन की फ्रैंचाइजी को आगे बढ़ाने के विजन से काफी प्रभावित हुईं और उन्हें फिल्म का निर्देशन करने की चुनौतियों को संभालते हुए देखकर खुशी हुई।

मालूम हो कि एक्ट्रेस का नाम प्रभास की अनटाइटल्ड फिल्म के लिए सामने आ रहा था, लेकिन पिछले दिनों खबर आई कि एक्ट्रेस इस फिल्म से बाहर हो गई हैं।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, कृष 4 की कहानी टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट पर आधारित रहेगी, जो मार्वल ब्लॉकबस्टर 'एवेंजर्स: इनफिनिटी वॉर' और 'एवेंजर्स: एंडगेम' से प्रेरित हो सकती है। मेकर्स का मानना है कि फिल्म को कई टाइमलाइन्स में बनाया जाएगा, जिसमें पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक सभी में ये किरदार ट्रैवेल करेंगे। फिल्म के शूटिंग की शुरुआत 2026 में शुरू हो जाएगी।

फिटनेस में यंग एक्टर्स को टक्कर देते हैं सुनील शेट्टी

63 की उम्र में भी दिखते हैं हैंडसम हंक

90 के दशक में बॉलीवुड में एंट्री लेने वाले स्टार्स शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन और अक्षय कुमार आज भी यंग और फिट नजर आते हैं, लेकिन इन सबके बीच सुनील शेट्टी ने अपनी फिटनेस से इन सभी स्टार्स को पीछे छोड़ा हुआ है। शाहरुख खान से सलमान खान तक स्टार्स की उम्र 55 से 60 साल के बीच है। आमिर खान भी 59 साल के हैं, लेकिन 63 की उम्र में सुनील शेट्टी जैसी फिटनेस इनमें से किसी भी स्टार की नहीं है। अक्षय कुमार की फिटनेस भी कम नहीं है, लेकिन उम्र में वह सुनील शेट्टी से 6 साल छोटे हैं। सुनील शेट्टी 60 प्लस होकर भी इतने फिट क्यों हैं, यह एक्टर ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। चलिए जानते हैं

63 में इतने फिट क्यों हैं सुनील शेट्टी?

जब सुनील शेट्टी ने साल 1992 में फिल्म बलवान से बॉलीवुड डेब्यू किया था, तो लोग उनकी मसल्स देखकर हैरान हो गये थे। सुनील को उनकी दमदार बॉडी के चलते ही फिल्मों में काम मिला था। एक्टर को शुरू से ही फिट रहने का शौक है और वह कभी भी अपनी फिटनेस से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। एक इंटरव्यू में अपनी फिटनेस के बारे में एक्टर ने कहा था, '60 की उम्र में मेरे पिता मेरे जैसे फिट नहीं थे, जबकि मेरा और उनका जिम और ट्रेनर एक ही था, हमने एक जैसी डाइट ली, एक जैसे ही गाने सुने, लेकिन मैंने अपनी ट्रेनिंग घर में भी ली, मैंने अपना वर्कआउट किया, लेकिन मेरा वर्कआउट यहीं खत्म नहीं होता है, मैंने अपने खाने, समय, ऑफिस के काम और मेंटल हेल्थ पर भी काम किया, मैंने खुद को गार्डनिंग किया, बस यही अंतर है'।

एक्टर का लाइफस्टाइल

सुनील शेट्टी की फिटनेस के उदाहरण देखने के लिए उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा सकते हैं, जहां एक्टर का लाइफस्टाइल प्रेरित करने वाला है। सुनील शेट्टी दो बच्चों के पिता हैं और अब तो वह नाना भी बन गए हैं। एक्टर की बेटी अथिया शेट्टी ने एक बेबी को हाल ही में जन्म दिया है। इस उम्र में सुनील शेट्टी आज भी बॉलीवुड में एक्टिव हैं और एक्शन सीन करते हैं। एक्टर बॉलीवुड के अलावा मलयालम, तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और इंग्लिश भाषी फिल्मों में काम कर चुके हैं। उनको पिछली बार सीरीज 'हंटर टूटेगा नहीं तोड़ेगा' में एसीपी विक्रम चौहान के किरदार में देखा गया था।

अजय देवगन की रिजेक्ट की हुई इन फिल्मों से शाहरुख खान की चमक गई थी किस्मत

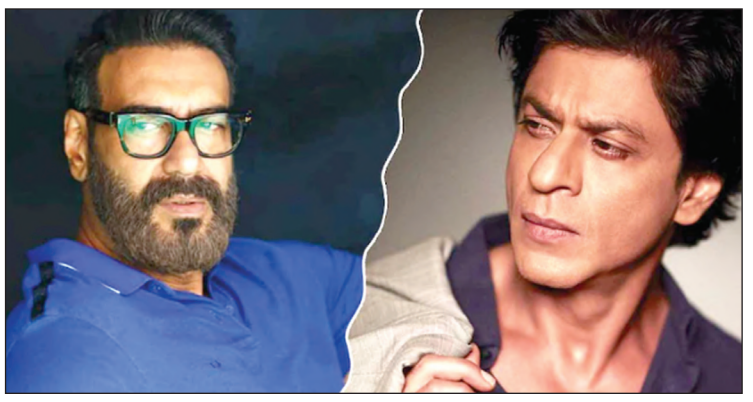

बॉलीवुड के 'सिंघम' अजय देवगन 90 के दशक के वो स्टार हैं, जो शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार और आमिर के टाइम के आसपास पर्दे पर उतरे थे। 90 के दशक के इन सभी स्टार्स के मुकाबले अजय देवगन का डेब्यू सबसे ज्यादा दमदार और हिट रहा था। अजय ने साल 1991 में एक्शन रोमांटिक फिल्म फूल और कांटे से बॉलीवुड में दस्तक दी थी। फिल्म के गाने और एक्टर का दो बाइक पर खड़े होने वाला एक्शन आज भी पॉपुलर है। इसके अगले साल ही अजय ने मार्शल आर्ट फिल्म जिगर की थी, जो सुपरहिट हुई और इसके बाद उनका करियर जम गया। अजय को बॉलीवुड में तीन दशक से ज्यादा का समय हो गया है और इस दौरान एक्टर ने कई ऐसी फिल्में भी ठुकराई जो ब्लॉकबस्टर साबित हुईं।

डर (1993)

सनी देओल और शाहरुख खान स्टारर बेहतरीन फिल्म डर को भुला पाना मुश्किल है। इसमें शाहरुख का रोल काफी खतरनाक और खौफनाक था, जो पहले अजय को ऑफर हुआ था। 90 के दशक में उभरते एक्टर्स नेगेटिव करने से बच रहे थे, लेकिन शाहरुख ने बता दिया कि एक्टिंग में दम हो तो नेगेटिव रोल करके भी हिट हुआ जा सकता है।

करण अर्जुन (1995)

राकेश रोशन के करियर की ब्लॉकबस्टर फिल्म करण-अर्जुन एक कल्ट क्लासिक फिल्म है। यह पहली बार था, जब शाहरुख और सलमान खान पहली बार पर्दे पर साथ में आए थे। शाहरुख ने अर्जुन और सलमान ने करण का रोल प्ले किया था। राकेश रोशन ने करण के रोल के लिए पहले अजय को चुना था। फिल्म की स्क्रिप्ट दमदार ना बताकर अजय ने इसे रिजेक्ट कर दिया।

कुछ-कुछ होता है (1998)

करण जौहर को फिल्म कुछ-कुछ होता है में एक स्पेशल रोल के लिए एक खास एक्टर की जरूरत थी। करण जौहर इस रोल के लिए सभी एक्टर्स के पास गए और लेकिन सलमान से नहीं मिले। बाद में खुद सलमान ने करण को कॉल कर कहा, 'और भी सर्च बाकी है या मैं आज जाऊं? इस पर करण जौहर बहुत खुश हुए। सलमान को अमन वर्मा का रोल मिला, जिसे अजय देवगन समेत कई एक्टर्स ने ठुकरा दिया था। सलमान को सपोर्टिंग रोल के लिए फिल्मफेयर अवार्ड भी मिला था।

सूर्यवंशम (1999)

हर हफ्ते टीवी पर आने वाली अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म सूर्यवंशम में भानु प्रताप के बेटे हीरा ठाकुर का रोल पहले अजय देवगन को ही ऑफर हुआ था, लेकिन 'सिंघम' ने इस रोल को करने से मना कर दिया था, जिसके बाद खुद अमिताभ ने अपने ही बेटे का रोल प्ले किया। फिल्म पिट गई, लेकिन टीवी पर बार-बार आने के चलते यह फिल्म खूब पॉपुलर हो गई है, जिस पर मीम्स भी बनते हैं।

बाजीराव मस्तानी (2015)

संजय लीला भंसाली की फिल्म बाज-ीराव मस्तानी एक हिट फिल्म है, जिसमें रणवीर सिंह, दीपिका पादुकोण और प्रियंका चोपड़ा ने काम किया था। रणवीर से पहले संजय ने अजय को बाजीराव के लिए रोल के लिए चुना था, लेकिन एक्टर ने डेट्स और स्क्रिप्ट से जुड़ी कुछ समस्याओं के चलते फिल्म करने से इनकार कर दिया।

पद्मावत (2018)

संजय लीला भंसाली ने बाजीराव मस्तानी के बाद फिल्म पद्मावत के लिए भी अजय देवगन को अहम रोल ऑफर किया था। शाहिद कपूर ने फिल्म में महरवाल रत्न सिंह का किरदार किया था, जो पहले अजय देवगन को ऑफर हुआ था। 'सिंघम' को यह कैरेक्टर पसंद नहीं आया। बता दें, पद्मवात भी भंसाली घराने की हिट फिल्मों में से एक है।

हसीन दिलरुबा बनकर दिलों पर राज करने वाली तापसी एक फिल्म का चार्ज करती करोड़ों

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू एक बार फिर अपनी फिल्म 'हसीन दिलरुबा' की तीसरी किस्त के लिए चर्चे में हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिये 'फिर आई हसीन दिलरुबा' के अगले पार्ट को लेकर अपडेट दिया है कि यह फिल्म एक बार फिर ओटीटी पर तीन गुना पागलपन के साथ लौटने वाली है। इस बीच एक्ट्रेस अपनी एक फिल्म के लिए कितना चार्ज करती हैं और उनकी नेट वर्थ कितनी है,

तापसी पन्नू एक लग्जरी लाइफ स्टाइल जीती हैं। अपनी फिटनेस और फैशन स्टेटमेंट पर ही एक्ट्रेस लाखों रुपए खर्च कर देती हैं। उछ्इउ की रिपोर्ट के मुताबिक, तापसी पन्नू की नेटवर्थ लगभग 50 करोड़ है। एक्ट्रेस की मोटी कमाई फिल्मों से होती है, जिसके लिए वह एक से दो करोड़ रुपए फीस चार्ज करती हैं। इसके अलावा उनकी तगड़ी कमाई ब्रांड एंडोर्समेंट्स से भी हो जाती है। एक ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए वह 2 करोड़ रुपये वसूलती हैं। तापसी पन्नू के पास मुंबई, महाराष्ट्र में एक 3 इक्ध फ्लैट है, जिसका नाम उन्होंने पन्नू पिंड रखा है। इस घर की कीमत लगभग 10 करोड़ रुपये है। एक्ट्रेस को लग्जरी कार्स का भी काफी शौक है। उनके कलेक्शन में जीप कंपास, BMW 3 सीरीज, BMW X1, ऑडी -8L, मर्सिडीज GLE 25OD जैसी कार्स शामिल हैं।

तापसी पन्नू ने लल्लनटॉप को दिए एक इंटरव्यू में बताया था कि वह अपनी डाइट पर खूब पैसे खर्च करती हैं। उन्होंने कहा था- मैं घर जाऊंगी तो मुझे चार बातें सुनने को मिलेगी। अपने डायटिशियन पर इतना ज्यादा पैसा क्यों खर्च कर रही हो। उन्होंने बताया कि वो 1 लाख हर महीने डायटिशियन को देती हैं। मेरी हर पिक्चर और समय के हिसाब से जरुरत होती है कि किस समय किस तरह का खाना खाना है।

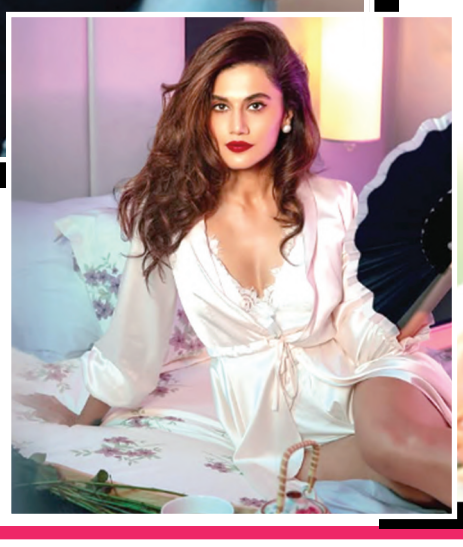

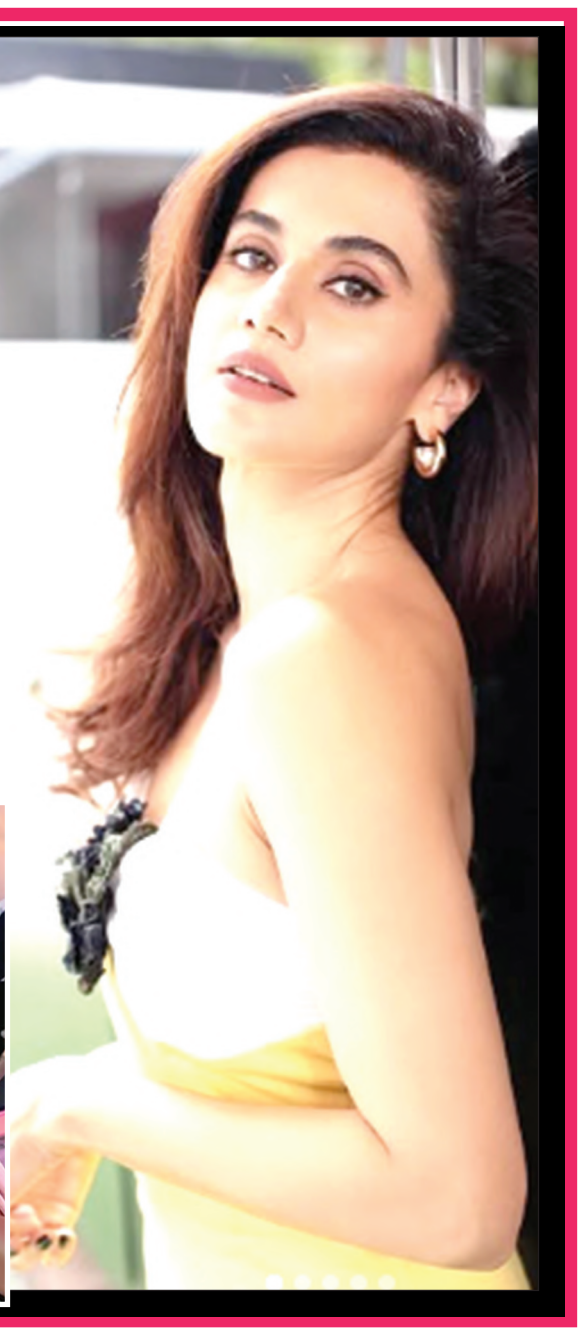

आज का राशिफल

मेष – चू,चे,चो,ला,लि,लू,ले,लो,अ

आज दिन अच्छा है दिन भर उत्साह बना रहेगा. आप अपने प्रियजनों के साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनेगा अपने प्रिय की ख़ामियों को ढूंढने में समय बर्बाद न करें. अविवाहित लोगों को विवाह या प्रेम प्रस्ताव मिल सकते हैं. परिवार में वैचारिक मतभेद खत्म हो सकता हैं. पड़ोस में कोई विवाद होने पर आप स्वयं सकारात्मक रहें.व्यायाम करें स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा।

वृषभ – इ,उ,ए,ओ,वा,वि,वु,वे,वो

आज धरती को प्रणाम करें कर दर्शन करें , दिन बढीया बितेगा . आप अपने कारोबार में अत्यधिक सफल होंगे और ग्राहकों के साथ स्थायी संबंध बनाएंगे. आप अपनी योग्यता को साबित करने के लिए बेहतर अवसरों का लाभ उठाएंगे. आपके सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी. आप बच्चों से खुश रहेंगे और अपने जीवनसाथी के साथ संतोषप्रद जीवन का लाभ उठाएंगे. स्वास्थ्य के सन्दर्भ में आज आप चिड़चिड़े हो सकतें हैं.दिन के पीछले भाग मे कुछ आराम का व्यवहार करें।

मिथुन – क,कि,कृ,घ,ड़,छ,के,को,ह

आज आमदनी मे बढोतरी होगी पैसों की स्थिति में सुधार हो सकता है. इनकम बढ़ाने के कुछ अच्छे मौके भी आपको मिल सकते हैं. जिनसे आप खुद भी हैरान हो सकते हैं. हाल ही में कुछ नए दोस्त मिल सकते हैं. आप अपनी पसंद या मनमर्जी के कामों के लिए उत्सुक होंगे. जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं, उससे आपको फायदा ही होगा. जो खास बात है उसे गंभीरता से ही लें. आज अपनी सोच पॉजिटिव रखें कार्यशैली मे बदलाव करें।

कर्क – ही,हु,हे,हो,डा,डी,डू,डे,डो

आज काम का बोझ ज्यादा रहेगा लेकिन शाम तक पूरा काम आसानी से निपटा लेंगे.साथ ही काम पूरा करने में आपको किसी सहकर्मी की मदद भी मिल सकती है.आपके करियर में अचानक बदलाव आ सकता है, जिससे आपको धन लाभ का अवसर प्राप्त होगा.आज आपके कुछ नए दोस्त बन सकते हैं. वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहेगा.आज आपको कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए और जोखिम भरे काम को करने से बचना चाहिए.शिवजी पर काले तिल चढाए ।

सिंह – म,मी,मू,मे,मो,टा,टी,टू,टे

लोगों से व्यवहार करते समय चौकन्ना रहने की जरुरत हैं उन्नति का कोई बढ़िया अवसर आपको मिल सकता है. स्वास्थ्य बेहतर बना रहेगा. घर में परेशानियाँ पैदा हो सकती हैं लेकिन अपने साथी को छोटी–छोटी बातों के लिए ताने देने से बचें. आज के दिन अधिकांश समय ख़रीदारी और दूसरी गतिविधियाँ में जाएगा. सामान्य रूप से आज आपका दिन मिलाजुला रहेगा. परिवार के बड़े लोगों का आपको आज सहयोग मिलेगा.खर्चा ज्यादा होगा।

कन्या – टो,प,पी,पू,ष,ण,ठ,पे,पो

दिन मिलाझुला रहेगा लेन–देन और निवेश के मामलों में नई नीति अपना होगा . आपके आसपास चहल–पहल भी रहेगी. आपकी एकाग्रता चरम पर होगी और एक साथ कई काम भी संभालने पड़ सकते हैं. लोगों से मिलने या परिवार के साथ कहीं जाने का कार्यक्रम बन सकता है. काम और मेहनत दोनों ज्यादा रहेंगे फिर भी सिद्धि मिलेगी।

तुला – र,री,रू,रे,रो,ता,ति,तू,ते

आज लाभ मिलेगा चिंता मुक्त होंगे किन्तु यदि आप आर्थिक लाभ हेतु आसान तरीकों की तलाश करते हैं तो मुश्किलें ही आएगी काम नही होंगे चलती हुई व्यापारिक गतिविधियों से आपको अच्छा लाभ हो सकता है. वित्तीय मामलों में आपको सावधान रहना चाहिए ख अविवाहितों के जीवन में आज प्रेम का प्रवेश हो सकता है ख छात्रों के लिए समय अनुकूल हैं।

वृश्चिक – तो,न,नी,नू,ने,नो,या,यी,यू

आज आप के काम बनेंगे आप की प्रशंसा होगी कुछ लोग आपसे प्रभावित भी हो सकते हैं.आपकी ऊर्जा बढ़ी हुई रहेगी .उधार दिया हुआ पैसा आज आपको वापस मिल सकता है.धन लाभ के नए रास्ते खुले नज़र आ सकते हैं.आज का दिन खुद में बदलाव लाने वाला है.इससे आपको सफलता मिलेगी । कामकाजी महिलाओं को कोई छोटा उद्योग शुरू करने में घर वालों का सहयोग प्राप्त हो सकता है.गाय को गेहूँ गुड और नंदी को भूसा खिलाए ।

धनु – ये,यो,भ,भी,भू,धा,फा,ढा,भे

आज सूर्य उपासना करें आरोग्यता मिलेगी सूर्य अष्टक का पाठ करें आने वाले खर्चों के प्रबंध को लेकर आपको मिल जुलकर आगे बढने का प्लान बनाना होगा. आज आप अपने जीवनसाथी के साथ सैर–सपाटे का मज़ा ले सकते हैं. साथ में समय गुज़ारने का यह बढ़िया मौक़ा है. आज अपने व्यापार में विस्तार करने के लिए उत्तम दिन है. अगर आप नौकरी करते हैं तो आज ट्रांसफर के योग हैं आज आप गुस्से और व्यवहार मे बदलाव बहुत जरुरी

मकर – भो,ज,जी,खि,खू,खे,खो,ग,गि

आज व्यापार मे और कार्य शैली मे साथ ही साथ बिजनेस में कुछ बदलाव करना पड सकता हैं किसी खास मामले को लेकर परिवार से बातचीत हो सकती है. ऑफिस के काम या अपने किसी शौक के कारण आप व्यस्त हो सकते हैं . कुछ जिम्मेदारियां और जरूरी काम आपको निपटाने पड़ सकते हैं. निवेश करने या किसी को आर्थिक मदद देने के पहले सलाह कर लें. नए जमीन और वाहन खरीदने का विचार बन रहा है

कुम्भ – गु,गे,गो,सा,सी,सू,से,सो,द

आज आय के स्त्रोत खुले रहेंगे वित्तीय मोर्चे पर आज अच्छा लाभ संभव है. आप इस चरण में कई गतिविधियों में शामिल होंगे. व्यापार के कारण यात्रा सम्भव हैं नए संपर्कों से भी लाभ होगा जो भविष्य में फायदेमंद साबित होगा. व्यावसायिक व्यक्ति अपने प्रतिद्वंद्वियों को बहुत पीछे छोड़ देंगे. भूमि , वाहन आदि की बिक्री और खरीद के लिए समय अनुकूल हैं आप सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद लेंगे दाम्पत्यजीवन सुखमय बीतेगा।

मीन – दी,दू,थ,झ,ञ,दे,दो,चा,ची

आज बडे बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर काम आरंभ करें कार्य सिद्ध होंगे जीवनसाथी के साथ रिश्ते बेहतर होंगे.आर्थिक पक्ष आज पहले से मजबूत रहेगा..सोचे हुए काम पूरे हो सकते हैं. आपके मन में नए–नए विचार आ सकते हैं.जिनको आप अपने जीवन में उतारने में कामयाब रहेंगे.सीनियर आपके कामों की प्रशंसा करेंगे.जो लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े हैं, उन्हें कार्यक्षेत्र में पदोन्नति और प्रशंसा मिल सकती है.दोस्तों के साथ मौज–मस्ती में आपका दिन बीत सकता है.शिवजी पर दूध जल चढाए।

आज का पंचांग

दिनांक : 14 अप्रैल 2025 , सोमवार
विक्रम संवत : 2082
मास : वैशाख ,कृष्ण पक्ष
तिथि : प्रतिपदा प्रातः 08:27 तक
नक्षत्र : स्वाति रात्रि 12:13 तक
योग : वज्र रात्रि 10:36 तक
करण : कौलव प्रातः 08:27 तक
चन्द्रराशि : तुला
सूर्योदय : 06:00 , सूर्यास्त 06:31 (हैदराबाद)
सूर्योदय : 06:07 , सूर्यास्त 06:32 (बैंगलोर)
सूर्योदय : 05:59 , सूर्यास्त 06:25 (तिरुपति)
सूर्योदय : 05:53 , सूर्यास्त 06:22 (विजयवाडा)

शुभ चौघड़िया
अमृत : 06:00 से 07:30
शुभ : 09:00 से 10:30
चल : 01:30 से 03:00
लाभ : 03:00 से 04:30
अमृत : 04:30 से 06:00
राहुकाल : प्रातः 07:30 से 09:00
दिशाशूल : पूर्व दिशा
उपाय : दही धनिया खाकर यात्रा का आरंभ करें
दिन विशेष :– संक्रांति पुण्यकाल सूर्योदय से मध्यान्ह तक , डॉ अम्बेडकर जयंती

* पाण्डित्य विषय में सम्पर्क करें *

पं.चिदम्बर मिश्र (टिल्लू महाराज)
हमारे यहाँ पाण्डित्य पूर्ण यज्ञ अनुष्ठान, भागवत कथा एवं मूल पारायण, वास्तुशान्ति, गृहप्रवेश,शतचंडी, विवाह, कुंडली मिलान, नवग्रह शान्ति, ज्योतिष सम्बन्धी शंका समाधान किए जाते हैं
फक्कड़ का मन्दिर, रिकाबगंज, हैदराबाद, (तेलंगाना)
9246159232, 9866165126
chidamber011@gmail.com

राजस्थान सरकार तारबंदी योजना पर दे रही है अनुदान

- जानवर फसल नहीं कर पाएंगे बर्बाद
- किसानों को 50% या 40 हजार तक का अनुदान

जयपुर,13 अप्रैल (एजेंसियां)। राजस्थान में किसानों को खेतों की सुरक्षा के लिए भी अनुदान दिया जाता है। कृषि विभाग और उद्यानिकी विभाग की तारबंदी योजना के तहत ये अनुदान दिया जाता है। दिनों विभागों ने इस योजना के आवेदन की नई गाइडलाइन जारी की है। इस बार तारबंदी योजना के नियमों में बदलाव किया गया है। इस बदलाव के अनुसार, पहले 6 बीघा भूमि होने पर ही तारबंदी योजना का लाभ मिलता था, अब सरकार ने 2 बीघा भूमि पर भी योजना का लाभ देने की घोषणा की है। ऐसे में कम जमीन वाले किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे।

नीलगाय, जंगली पशुओं तथा निराश्रित पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान से बचाने व रोकथाम के लिए तारबंदी कार्य पर 6 बीघा (1।5 हेक्टेयर) के स्थान पर 2 बीघा (0।5 हेक्टेयर) भूमि पर अनुदान दिया जाएगा। नई गाइड लाइन के अनुसार विभाग द्वारा अधिक किसानों तक को लाभान्वित करने के लिए तारबंदी योजना में बदलाव किए हैं। इन बदलावों से किसानों को काफी फायदा होगा। किसान अधिक लाभ उठा सकेंगे वहीं विभाग को लक्ष्य प्राप्त करने में आसानी होगी। गत वर्षों में विभाग की तारबंदी के लक्ष्य पूरे नहीं होने पाने से बजट लेप्स हो जाता है।

इस योजना में अब सभी श्रेणियों के किसानों को लाभ दिया जाएगा। एक किसान के पास न्यूनतम 0।5 हेक्टेयर या 2 बीघा भूमि एक स्थान पर हो, समूह में न्यूनतम 2 किसानों के पास 0।5 हेक्टेयर भूमि होनी चाहिए। योजना में पति–पत्नी को भी अलग–अलग लाभ दिया जाएगा। किसान तारबंदी या जाल बंदी में करंट नहीं छोड़ सकते है।

कटिदार तारबंदी/ चैनलिक/वर्गाकार जाली पर भी अनुदान रहेग। अनुदान पाने के लिए जीएसटी बिल देना होग। व्यक्तिगत 0।5 हेक्टेयर पर अधिकतम 400 रनिंग मीटर तारबंदी करने पर 50% या 40 हजार रुपए तथा लघु सीमांत किसानों को 60% अधिकतम 48 हजार रुपए (8000 रुपए राज्य योजना से) दिया जाएगा। समूह में तारबंदी करने वाले सभी श्रेणियों के किसानों को 50 प्रतिशत या 40 हजार अनुदान दिया जाएगा।

जनता को बेहाल छोड़कर कलेक्टर पहुंचे कश्मीर छुट्टियां मनाने

मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कलेक्टर को झूठ बोलने पर लताड़ा

करौली,13 अप्रैल (एजेंसियां)। क्लास से बंक मारकर और झूठ बोलकर केवल स्कूल तथा कॉलेज के स्टूडेंट ही तफरी नहीं करते हैं बल्कि आला अधिकारी भी ऐसा करने में पीछे नहीं है। राजस्थान में तो ऐसा करते हुए एक कलेक्टर ही पकड़े गए। करौली कलेक्टर नीलाभ सक्सेना जरुरी काम से घर जाने की छुट्टी लेकर गर्मी में कश्मीर की वादियों में तफरी करने पहुंच गए। लेकिन सूबे के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने उनका झूठ पकड़ लिया और जिला स्तरीय अधिकारियों के सामने कलेक्टर साहब की क्लास लगा डाली।

दरअसल सीएस सुधांश पंत हाल ही में सवाई माधोपुर जिले के दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने वहां सवाई माधोपुर और करौली के जिला स्तरीय सभी अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली थी। इस दौरान करौली के अधिकारियों को ऑनलाइन मिटिंग से जोड़ा गया। उस समय करौली जिला कलेक्टर नीलाभ सक्सेना अवकाश पर थे। करौली जिला कलेक्टर को भी ऑनलाइन मीटिंग से जुड़वाया गया। इस दौरान सीएस सुधांश पंत ने कलक्टर से पूछा आप कहा हो? इस पर कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने कहा सर मैं अभी जम्मू–कश्मीर हूं।

कलेक्टर बोले आपने तो होम टाउन जाने के लिए छुट्टी ली थी

बस इतना सुनते ही सीएस सुधांश पंत ने उनको लताड़ लगा डाली। पंत ने कहा कि आपने सीएस से ही झूठ बोला और छुट्टी लेकर कश्मीर पहुंच गए। आपने तो जरूरी काम से होम टाउन (लखनऊ) जाने के लिए छुट्टी ली थी। आप झूठ बोलकर जनता को गर्मी में बेहाल छोड़कर कश्मीर में घूम रहे हो। यदि जिले के लीडर ही इस तरह करेंगे तो अधीनस्थ क्या करेंगे? जनता गर्मी में पानी–बिजली से परेशान हो रही है और आप कश्मीर में छुट्टी मना रहे हो।

सीएस का कड़ा रुख देखकर अन्य अधिकारी सन्न रह गए। वहीं कलेक्टर साहब की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। राजस्थान में इन दिनों गर्मी के कारण बिजली–पानी की खासा दिक्कत हो रही है। बिजली पानी की किल्लत से परेशान लोग सड़कों पर आ रहे हैं। सीएस पंत ने दौसा में अधिकारियों की ली बैठक के दौरान खासतौर पर पीएचईडी विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां कैंसिल करते हुए साफ हिदायत दी थी कि अति आवश्यक होने पर वे जिला कलेक्टर से ही छुट्टी ले सकेंगे। लेकिन करौली में तो खुद कलेक्टर ही छुट्टी पर थे।

सरकारी स्कूल में मिला शराब का गोदाम पुलिस देखकर रह गई हैरान

भीलवाड़ा पुलिस ने स्कूल से 31 लाख की अवैध शराब जब्त की

भीलवाड़ा,13 अप्रैल (एजेंसियां)। राजस्थान में शराब तस्करी जोरों पर है। आए दिन पुलिस अवैध शराब से भरे ट्रक के ट्रक पकड़ती है। शराब तस्कर भी पुलिस को चकमा देने के लिए नित नए–नए तरीके अपनाते हैं। लेकिन इस बार तस्करों ने अवैध शराब को छिपाने के लिए जो ठिकाना चुना उसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। भीलवाड़ा जिले में तस्करों ने अवैध शराब को एक बंद पड़े स्कूल में छिपा दिया। पुलिस ने जब स्कूल को खुलवाकर देखा तो उसमें करीब 31 लाख रुपये की अवैध शराब मिली। पुलिस ने इस शराब को जब्त कर लिया है।

भीलवाड़ा के करेड़ा थानाधिकारी पूरणमल ने बताया कि शनिवार को इलाके के शिवपुर गांव में देवीलाल मेवाड़ा के फार्म हाउस पर हरियाणा निर्मित शराब की ट्रक खाली होने की सूचना मिली थी। मुखबिर की सूचना पर करेड़ा थाना पुलिस और डीएसटी ने संयुक्त रूप से वहां छापा मारा। लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। इस बीच पुलिस को बंद पड़े स्कूल भवन में शराब छिपाई हुई होने की सूचना मिली। इस पर पुलिस ने वहां के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की तलाश ली।

तलाशी के दौरान स्कूल के एक बंद कमरे में भारी मात्रा में अवैध शराब भरी हुई मिली। पुलिस ने वहां से हरियाणा निर्मित विभिन्न ब्रांड की शराब के 353 कार्टन बरामद किए। स्कूल में बनाए गए इस शराब के गोदाम को देखकर सभी हैरान रह गए। स्कूल से जब्त की गई शराब का बाजार मूल्य करीब 31 लाख 1760 रुपये है। जांच में सामने आया कि मर्ज होने के कारण यह स्कूल बंद कर दिया गया था। तस्करों ने इसी बात का फायदा उठाया और वहां अवैध शराब का ट्रक खाली करवा दिया।

शराब तस्करों को लगा कि स्कूल भवन होने के कारण किसी को शक नहीं होगा। लेकिन मुखबिर ने उनके प्लान पर पानी फेर दिया। अब पुलिस शराब तस्करों का पता लगाने में जुटी है। यहां यह शराब किसने रखवाई इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की कड़ी से कड़ी जोड़ने में लगी है। इस मामले में स्थानीय लोगों की मिलीभगत से भी इनकार नहीं किया जा रहा है।

खाटूश्यामजी जा रहे परिवार की कार ट्रेलर से टकराई, 5 लोगों की मौत

जयपुर,13 अप्रैल (एजेंसियां)। राजस्थान के दौसा–मनोहरपुर हाईवे पर आज सुबह–सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया है। यहां जमवारामगढ़ इलाके में एक ट्रेलर और कार में आमने–सामने से जबर्दस्त भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद दोनों वाहन पलट गए। हादसे में कार में सवार पांचों लोगों की मौत हो गई। ये सभी एक ही परिवार के थे और खाटूश्यामजी के दर्शनों के लिए जा रहे थे। ये सभी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। हादसे की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को कार से निकलवाकर उनको स्थानीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।

जानकारी के अनुसार हादसा सुबह करीब सवा आठ बजे दौसा–मनोहरपुर हाईवे पर स्थित नेकावाला टोल प्लाजा के पास हुआ। ट्रेलर और कार दोनों आमने सामने से इस कदर भिड़े कि वहां तेज धमाका हुआ। उसके बाद दोनों वाहन खाई में पलट गए। हादसा होते ही वहां लोगों की भीड़ लग गई। लोगों ने पुलिस को सूचित किया अपने स्तर पर लोगों को बचाने का प्रयास शुरू कर दिया। कार में पांच लोग सवार थे। ये लोग यूपी से खाटूश्यामजी दर्शन करने जा रहे थे।

कार पलटने से पांचों लोग उसमें बुरी तरह से फंसकर रह गए। इस बीच पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। बाद में पुलिस और लोगों ने मिलकर कार में फंसे घायलों को जैसे तैसे करके बाहर निकाला। लेकिन तब तक दो लोगों की मौत हो चुकी थी। बाद में पुलिस ने मृतकों और घायलों को तत्काल स्थानीय अस्पताल में पहुंचाया। वहां तीनों घायलों को भी मृत घोषित कर दिया गया। मृतकों में दो पुरुष, दो महिलाएं और एक मासूम बच्चा शामिल है। पुलिस ने मृतकों की शिनाख्त कर उनके परिजनों को सूचित किया। एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत से उनके परिजन बहदवास हो गए और वे अस्पताल दौड़े। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस वाहनों को खाई से निकलवाने में जुटी है।

हरियाणा में गर्मी से अस्पतालों में मरीजों की बढ़ी संख्या!

दस्त, बुखार और उल्टी के मरीजों की संख्या अधिक

अंबाला,13 अप्रैल (एजेंसियां)। हरियाणा में इन दिनों मौसम ने करवट ली है और अप्रैल माह की शुरुआत से ही लगातार गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं बदलते मौसम के कारण लोगों को काफी परेशानी शुरू हो रही हैं, तो दूसरी तरफ हस्पतालो में भी जझऊ में मरीजों की लगातार संख्या बढ़ रही हैं। बता दें कि बढ़ती गर्मी के साथ साथ ज्यादतर मरीज उलटी,दस्त व फीवर के ही निकलकर सामने आ रहे हैं। क्योंकि इस मौसम मे ज्यादातर लोग लापरवाई करते हैं और जिस कारण उन्हें ये परेशानी झेलनी पड़ती है।

हस्पताल में अपनी पत्नी का इलाज करवाने आये एक प्रीतम सिंह ने बताया कि मौसम बदलने के कारण उनकी पत्नी को दस्त लग गए हैं और जिसका इलाज करवाने के लिया वह नागरिक अस्पताल आए हैं। उन्होंने कहा कि नागरिक हस्पताल काफी अच्छा है और मरीजों का इलाज भी डॉक्टर सही तरह से कर रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि सरकारी हस्पतालों मे भी ज्यादातर मरीज पहुंचे रहे हैं, जहाँ पर डॉक्टर्स इलाज के साथ–साथ उन्हें इस गर्मी से बचाव की भी सलाह दे रहे हैं।

ज्यादा जानकारी देते हुए नागरिक हस्पताल के डॉक्टर जितेंद्र चौहान ने बताया कि बढ़ती गर्मी के कारण यहाँ मरीजों की संख्या बढ़ रही है, और ज्यादातर मरीज लूज़ मोशन व फीवर के आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मौसम में सबसे पहले तो अपने आपको बचाना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादातर लू लगने का खतरा रहता हैं, जिससे फीवर हो सकता हैं। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में हमें बासी खाना व कटे हुए फल वगैरह खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसके कारण भी हम बीमार हो सकते हैं।

बारिश और ओले गिरने से 2 लोगों की मौत

मंडियों में भीगी गेंहू, 4 जिलों में ओलावृष्टि के बाद मौसम हुआ सुहावना

चंडीगढ़,13 अप्रैल (एजेंसियां)। उत्तर भारत में मौसम के करवट बदलने के बाद हरियाणा में बारिश और ओले गिरे हैं। यहां पर बिजली गिरने से दो लोगों की मौत भी हो गई। वहीं, अनाज मंडियों में बारिश के पानी में गेंहू की फसल भीगने से किसानों को खासा नुकसान हुआ। शुक्रवार को प्रदेश के कई इलाकों में बादल छाए हुए हैं। वहीं, कुछ जगह हल्की धूप भी निकली है।

जानकारी के अनुसार, गुरुवार दिन और शाम के बाद हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश हुई। इस दौरान जींद, कैथल और सोनीपत में ओले भी गिरे। उधर, फतेहाबाद में आसमानी बिजली गिरने से मां की मौत हो गई, जबकि 13 साल की बेटी घायल है। रेवाड़ी के धारूहेड़ा में आंधी में पोल गिरने से युवक की मौत हो गई।

टोहाना विधानसभा के गांव नागला में में बिजली गिरने की यह घटना सामने आई। घटना के समय महिला और उसकी 13 वर्षीय बेटी खेत से चने इकट्ठा कर घर लौट रही थीं। अचानक मौसम खराब हो गया और तेज हवाओं के साथ बिजली गरजने लगी और बारिश से बचने के लिए दोनों एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गईं। तभी पेड़ पर बिजली गिर गई, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई और बेटी घायल हो गई। घायल बेटी को तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। महिला के पति सुभाष ने बताया कि उनकी पत्नी और बेटी खेत में चने इकट्ठा कर रही थीं। मौसम खराब होता देख वे घर लौट रही थीं, लेकिन रास्ते में तेज बारिश आ गई। बारिश से बचने के लिए वे एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गईं, तभी बिजली गिरने से उनकी पत्नी की मौत हो गई और बेटी गंभीर रूप से घायल हो गई।

चरखी दादरी में अनाज मंडी में हजारों क्विंटल अनाज खराब मौसम के बीच खुले में पड़ा हुआ है। बीती रात बारिश होने से गेहूं और सरसों की ढेरियां और बैग भीग गए। गुरुवार को श्रमिक ढेरियों और बैग के पास से पानी निकालते नजर आए। हालांकि, मार्केट कमेटी के अधिकारी अनाज के ज्यादा नहीं भीगने और तिरपाल तेज हवा में उड़ने की बात कहकर आढ़तियों का बचाव करते दिखे। वहीं, धीमी गति से उठान होने के कारण मंडी में लगातार परेशानियां बढ़ रही हैं।गौरतलब है कि चरखी दादरी सहित प्रदेश के अन्य जिलों में गेहूं और सरसों की आवक जोरों पर है। क्षेत्र के किसान बनाए गए खरीद केंद्रों पर एमएसपी के तहत सरकारी खरीद में फसल बेचने के लिए संबंधित मंडी और खरीद केंद्रों पर पहुंच रहे हैं।

विनेश ने इनाम की राशि से खेल अकादमी बनाने की बनाई योजना

चंडीगढ़,13 अप्रैल (एजेंसियां)। हरियाणा के जींद के जुलाना से कांग्रेस विधायक और पूर्व ओलंपिक कुश्ती खिलाड़ी विनेश फोगाट को सरकार ने पेरिस ओलंपिक में बढ़िया प्रदर्शन करने के लिए चार करोड़ रुपये और प्लॉट इनाम में दिया है। सरकार ने विनेश को चार ऑप्शन दी थी, जिसमें से अब विनेश ने नकद राशि और प्लॉट का विकल्प चुना है। वहीं, इस चार करोड़ रुपये की राशि को लेकर विनेश ने अपनी अगली प्लानिंग भी शेयर की है। साथ ही सरकार का भी आभार जताया है।

विनेश फोगाट ने सोशल मीडिया पर पोस्ट में लिखा कि खिलाड़ी की मेहनत को सम्मान मिले–यही असली जीत है। मुझे जनता ने बहुत कुछ दिया है–प्यार, सम्मान, विश्वास, हिम्मत और हौंसला। अब वक्त है इस सबका ऋण चुकाने का।आगे विनेश लिखती हैं कि एक जनप्रतिनिधि होने के नाते और जिस संघर्ष का मैं हिस्सा रही हूँ, उसे देखते हुए मेरी ज़िम्मेदारियाँ अब सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि उन हज़ारों सपनों की हैं जो खेल के ज़रिए एक सुरक्षित वातावरण में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं।। यह हमेशा मेरा सपना रहा है कि मैं अगली पीढ़ी के खिलाड़ियों के लिए बेहतर सुविधाएं और

अच्छा खेल वातावरण दे सकूँ। अब वह समय आ गया है। सर्व–समाज और हरियाणा सरकार द्वारा मुझे ओलंपिक्स में मेरे प्रदर्शन के लिए जो मान–सम्मान दिया गया है मैं उसके लिए हमेशा आभारी रहूँगी।विनेश ने कहा कि सरकार द्वारा दी जाने वाली यह पुरस्कार राशि केवल एक इनाम नहीं है–यह एक अवसर है, एक ज़रिया है उस सपने को साकार करने का, जो मैं सालों से देखती आ रही हूँ। इसलिए इस पुरस्कार राशि का उपयोग अंतरराष्ट्रीय लेवल की खेल एकेडमी की स्थापना में किया जाएगा, जहाँ युवा खिलाड़ी बेहतरीन संसाधनों के साथ अपनी प्रतिभा को नई ऊँचाइयों तक ले जा सकें। एक ऐसी अकैडमी जहाँ युवा खिलाड़ी न सिर्फ संसाधनों की कमी से मुक्त हों, बल्कि उन्हें वो सम्मान और प्रेरणा भी मिले जो हर मेहनती खिलाड़ी का अधिकार है। इसीलिए मुझे आप सब के सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यह सिर्फ मेरा नहीं, हम सबका सपना है और इसे पूरा करना भी हम सबकी ज़िम्मेदारी है।

शुभ लाभ DAILY

भीम संवाद में सीएम नीतीश बोले–

हमने सब जाति के लिए काम किया

पटना (एजेंसियां)।

भारत रत्न डॉ. भीम राव अंबेडकर की जयंती को लेकर आज बिहार की सियासी गलियारे में काफी हलचल है। सुबह भाजपा के केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया के नेतृत्व में पदयात्रा निकाली गई। दोपहर जनता दल यूनाईटेड की ओर से भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बापू सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार मुख्य अतिथि का तौर पर शामिल हुए। लेकिन, सीएम नीतीश कुमार ने ही मंत्री अशोक चौधरी का स्वागत किया। उन्होंने एक नहीं दो दो बार शॉल ओढ़ाकर मंत्री अशोक चौधरी का स्वागत किया।

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि मैं बाबासाहेब को नमन करता हूं। आप सभी बिहार वासियों को उनकी जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। सीएम ने कहा कि मैं तो उनके घर पर भी कई बार गया हूं। उनके घर पर परिवार के लोगों से भी मिला हूं। देश के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया है। संविधान की रचना कोई मामूली बात है। एक बार फिर से लालू राबड़ी राज की याद दिलाते हुए सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पहले कोई कुछ काम नहीं करता था।

जब हमलोग सरकार में आए तो लोगों के लिए बहुत काम किया। इतना ज्यादा महिलाओं के लिए काम किया। सब जाति के लिए हमने काम किया है। कुछ दिन पहले मैं प्रगति यात्रा पर निकला था। जहां कमी दिखी, उसे पूरा करने का निर्देश दिया है। वहीं मंत्री अशोक चौधरी से कहा कि इनको मैं बधाई देता हूं। इनसे हम यही कहेंगे। जितना काम पूरे देश में किया जा रहा है। आप सभी जगह जो हमारा काम है, उसे पूरा कराइएगा।

सीएम के अलावा केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, मंत्री विजय चौधरी, पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा समेत सभी वरीय नेता और कार्यकर्ता समारोह में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि नवंबर 2005 में पहली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे। तब से लेकर आज तक बाबासाहेब के बताए रास्ते पर चल रहे हैं।

नीतीश कुमार ने नारा दिया था कि न्याय के साथ विकास। इसके 2006 से बाबा साहेब की जयंती पर यह कार्यक्रम चला आ रहा है। ललन सिंह ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि 2005 से पहले बिहार में कोई काम नहीं हुआ था। इनलोगों ने 15 साल तक बिहार को बर्बाद कर दिया। तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग दिन में हसीन सपना देख रहे हैं, लेकिन कभी सीएम नहीं बन पाएंगे।

दंपती को तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर पति की मौके पर मौत, पत्नी गंभीर

पटना (एजेंसियां)।

कैमूर जिले के कुदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत लहुरबारी पुल के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब दंपति कपड़े की फेरी के लिए बाइक से कोचस जा रहे थे।

मृतक की पहचान कुदरा थाना क्षेत्र के खरहना गांव निवासी नगीना साह के लगभग 35 वर्षीय पुत्र मुन्ना कुमार गुप्ता के रूप में हुई है।

जानकारी के अनुसार, मुन्ना गुप्ता अपनी पत्नी गुड़िया देवी के साथ बाइक से कोचस जा रहे थे। लहुरबारी पुल के पास सामने से आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे दोनों पति-पत्नी सड़क पर गिर पड़े। तभी पीछे से आ रहे ट्रक ने मुन्ना गुप्ता को रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

घटना की सूचना पर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल दंपति को कुदरा पीएचसी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मुन्ना गुप्ता को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल गुड़िया देवी को बेहतर इलाज के लिए भभुआ सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है।

सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हादसे के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

इस संबंध में खरहना गांव के मुखिया अशोक कुमार चौरसिया ने बताया कि मृतक के तीन छोटे-छोटे बच्चे हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर है। मुखिया ने सरकार से मांग की है कि पीड़ित परिवार को अविलंब उचित मुआवजा दिया जाए ताकि बच्चों का पालन-पोषण हो सके।

जेसीओ और उनकी पत्नी के साथ बर्बरता पर सेना नाराज

डीजीपी से शिकायत की तब निलंबित हुए थानेदार

पटना (एजेंसियां)।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में सेना के जूनियर कमीशंड अधिकारी (जेसीओ) अजीत कुमार और उनके परिवार के साथ बिहार पुलिस ने बेरहमी से पीटा था। इतना ही नहीं जब सूबेदार अजीत कुमार ने विरोध किया तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

बात जब सेना मुख्यालय पहुंचा तो अधिकारियों ने कड़ी नाराजगी जताई। फौरन सेना के अधिकारियों ने बिहार के डीजीपी विनय कुमार से मुलाकात की और उनसे कार्रवाई की अपील की। इसके बाद डीजीपी के आदेश पर तेल्हारा थाना के थानेदार को निलंबित कर दिया गया है। अब आईजी स्तर के अधिकारी मामले की जांच कर रहे हैं। डीजीपी ने सेना के अधिकारी को दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है।

नालंदा के तेल्हारा थाना क्षेत्र चांदपुर गांव में सूबेदार अजीत कुमार चैती छठ के अवसर पर छुट्टी लेकर अपने घर आए थे। उन्होंने बताया कि उनके भाई और सरपंच मंटू कुमार पर दुष्कर्म का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मंटू पर प्राथमिकी दर्ज की है। जब मंटू नहीं मिला तो तेल्हारा थाने की पुलिस ने नौ अप्रैल की रात को अजीत कुमार के घर छापेमारी की।

पुलिस ने बिना वारंट और पूर्व सूचना के दीवार फांदकर घर में घुसे। विरोध करने पर घर मौजूद लोगों को बेरहमी से पीटा। इतना ही नहीं मुझे, मेरी पत्नी, भाभी, भतीजी, बहन को घर से खींचकर ले गए और सभी को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा। इतना ही नहीं पुलिस के कार्य में बाधा का आरोप लगाकर मुझे और मेरे भतीजे पर केस कर दिया।

वहीं मारपीट में जख्मी हुए सेना के सूबेदार अजीत कुमार की एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इसमें उनके शरीर पर चोट के कई निशान दिख रहे हैं। वहीं पुलिस का कहना है कि हमलोग दुष्कर्म केस के आरोपी को गिरफ्तार करने गए थे। लेकिन, अजीत कुमार और उसके सहयोगी छापेमारी करने पहुंची पुलिस दल के साथ उलझ गए और सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए अभद्र भाषा का प्रयोग किया। इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया और बुधवार की सुबह नोटिस देकर जमानत पर रिहा कर दिया गया। इधर, सेना के अधिकारियों की नाराजगी के बाद थानाध्यक्ष राजेश कुमार ठाकुर को निलंबित कर दिया है। आईजी गरिमा मल्लिक खुद इस मामले की जांच कर रही हैं।

दवाइयों के पैकेट की आड़ में हो रही थी तस्करी

लीज पार्सल में छिपाकर लाई गई शराब की खेप बरामद

मुज्जफरपुर (एजेंसियां)।

मुजफ्फरपुर जंक्शन पर रेल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है।

स्टेशन के पार्सल कार्यालय के पास से महंगे ब्रांड की अवैध विदेशी शराब की भारी खेप बरामद की गई है। जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में प्लेटफॉर्म संख्या एक के पास पार्सल कार्यालय के समीप यह शराब पकड़ी गई। जब्त की गई शराब की कीमत लगभग 10 लाख रुपये आंकी गई है।

शराब को बड़ी चालाकी से दवाइयों के पैकेट की आड़ में छिपाकर भेजा गया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि शराब की यह खेप किसी ट्रेन की लीज पार्सल वैन के जरिए मुजफ्फरपुर पहुंचाई गई थी। इस बात की जानकारी मिलते ही रेल पुलिस ने बिना नाम-पते वाले पैकेट्स पर विशेष नजर रखनी शुरू की थी।

जांच के दौरान रेलवे पुलिस को प्लेटफॉर्म संख्या एक पर पहुंचे एक संदिग्ध पैकेट पर शक हुआ, जिसे जब्त कर खोला गया तो उसमें से अलग-अलग ब्रांड की कुल 280 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुईं। अनुमान है कि शराब माफियाओं ने इस खेप को मंगवाकर स्टेशन पर ही किसी को सौंप दिया था, लेकिन पुलिस की सतर्कता से यह पकड़ में आ गई।

जीआरपी थानाध्यक्ष रंजीत कुमार ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि लीज पार्सल वैन के जरिए अवैध शराब की तस्करी हो रही है। सूचना मिलते ही आरपीएफ और जीआरपी की टीम ने संयुक्त जांच अभियान शुरू किया और इसी दौरान यह खेप बरामद हुई।

पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि शराब की खेप किस ट्रेन से आई और इसे लेने कौन आया था। पार्सल इंचार्ज से भी इस संबंध में पूछताछ की जा रही है। रेल पुलिस अब शराब माफियाओं की पहचान में जुट गई है और जल्द ही इस पूरे नेटवर्क का खुलासा होने की उम्मीद है।

सहरसा में युवक की निर्मम हत्या हत्या कर सड़क किनारे फेंका धड़

सिर को अपने साथ ले गए अपराधी

सहरसा (एजेंसियां)।

सहरसा के पतरघट थाना क्षेत्र के गोलमा फ़ोरसाहा सड़क किनारे सिर कटी लाश मिलने से हड़कंप मच गया। शनिवार मध्य रात्रि इस वारदात की सूचना पर पतरघट थाना पुलिस पहुंची तो दंग रह गई। सड़क किनारे केवल युवक का धड़ पड़ा था। सिर गायब थे। पुलिस को जांच में पता चला कि निर्मम हत्या के बाद अपराधी युवक का सिर काटकर उसे अपने साथ ले गए। पुलिस ने फॉरेंसिक और डॉग स्क्वॉड टीम की मदद से मामले की जांच में जुट गई।

मृतक की पहचान गोलमा गांव के निवासी निर्मल साह के रूप में हुई है। वह फास्ट फूड की दुकान चलाता था। लोगों का कहना है कि सिर को कहीं अपराधियों ने पहचान छिपाने के उद्देश्य से घटनास्थल से कुछ दूरी पर बह रहे शीतलपट्टी धार में न फेंक दिया हो। पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। परिवार वालों ने धड़ देखकर निर्मल साह की पहचान की है।इधर, जिले के चार अलग अलग थानों की पुलिस मृतक के सिर को खोजने में जुटी है।

मृत निर्मल साह के बड़े बेटे रवि कुमार ने बताया कि उनके पिता हर रोज की तरह शनिवार के दिन दोपहर तीन से चार बजे के बीच गोलमा थाना क्षेत्र के ही फोरसाहा के समीप फास्ट फूड बेचने गए थे। रोजाना रात नौ बजे तक वह घर लौट आते थे। शनिवार रात 10 बजे तक घर नहीं लौटे तो परिवार वालों ने खोजबीन शुरू की। इस बीच उनके मोबाइल पर फोन भी किया लेकिन वह उठा नहीं रहे थे। इसके बाद हमलोग ग्रामीणों की मदद से उनकी खोजबीन की तो फोरसाहा के सड़क किनारे उनकी सिर कटी लाश देख सन्न रह गए। रवि कुमार ने बताया कि पुलिस से अपील है कि वह इस मामले को गंभीरता से ले और हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी करे। पुलिस का कहना है कि सिर की तलाश जारी है। धड़ को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। हत्यारे की तलाश में छापेमारी चल रही है। कुछ लोगों से पूछताछ चल रही है। मामले में आगे की कार्रवाई चल रही है।

किसी भी परिस्थिति में किसानों को प्रभावित नहीं होने देगी सरकार : डिप्टी सीएम

पटना (एजेंसियां)।

उप मुख्यमंत्री-सह-कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि हाल के दिनों में प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आई आंधी और असमय वर्षापात के कारण किसानों की फसलों को क्षति पहुंचने की संभावना है। सभी जिलों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर सरकार स्थिति का गहनता से मूल्यांकन कर रही है। इसके मद्देनजर आवश्यक राहत एवं सहायता कार्यों की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आपदा और अवसर दोनों समय में राज्य के किसानों के साथ हम खड़े हैं। किसी भी स्थिति में हम अपने अन्नदाताओं का अहित नहीं होने देंगे। विजय सिन्हा ने बताया कि जिलों में व्यापक स्तर पर खेतों में खड़ी फसलों का तेज हवा और भारी वर्षा के कारण प्रभावित होने की संभावना व्यक्त की गई है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान हो सकता है। आंधी और वर्षापात से गेहूं, गर्मा मूंग, उड़द, तिल, मक्का, मूंगफली, पान, अरहर, केला और प्याज समेत कई उद्यानिक फसलों के प्रभावित होने की भी संभावना है। इनमें से कई फसलें कटाई के बिल्कुल निकट थीं, जिससे किसानों को अधिक नुकसान होने की आशंका है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि भौतिक सत्यापन कर वास्तविक फसल क्षति का तत्काल आकलन करें। जिला पदाधिकारियों के स्तर से क्षति प्रतिवेदन प्राप्त होने पर प्रभावित किसानों को आवश्यक सहायता देने की कार्रवाई त्वरित गति से की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सभी जिला कृषि पदाधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे प्रभावित क्षेत्रों का त्वरित सर्वेक्षण करें और नुकसान का विस्तृत आकलन कर मुख्यालय को शीघ्र सूचित करें। इसके आधार पर सरकार किसानों के लिए मुआवजा एवं अन्य सहायता की व्यवस्था करेगी।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सक्षम नेतृत्व में राज्य की सरकार किसानों को हर संभव सहायता पहुंचाएगी।

भाजपा के संजय सरावगी का लालू-तेजस्वी पर तीखा तंज

राजद के डीएनए में कानून का उल्लंघन करना

दरभंगा (एजेंसियां)।

दरभंगा की शहरी विधानसभा में भाजपा के सक्रिय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान राज्य सभा सांसद डॉ. धर्मशीला गुप्ता और बिहार सरकार के मंत्री संजय सरावगी ने सम्मेलन का उदघाटन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस सम्मेलन का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए तैयार करना है।

बिहार सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री संजय सरावगी ने मुस्लिम समाज द्वारा शनिवार को निकाले गए विरोध जुलूस के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर हमला किया। उन्होंने कहा कि राजद के ऊ्छ- में ही कानून के खिलाफ काम करना शामिल है। इसके बाद उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव द्वारा वक्फ कानून के विरोध करने वाले बयान पर हमला किया।

उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी यादव के पिता लालू प्रसाद यादव भी कानून का उल्लंघन करते रहे हैं, जिस कारण आजतक राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी सजायाफ्ता हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राजद के शासन में मुख्यमंत्री आवास से अपराध और अपराधियों का संरक्षण होता था। इस बात को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कहता है, बल्कि खुद उनके रिश्तेदारों और सत्ता में भागीदार रहे संबंधियों और नेताओं ने मीडिया के सामने आकर स्वीकार करते पूरी कहानी का खुलासा किया था।

संजय सरावगी ने तेजस्वी यादव द्वारा सोशल मीडिया एक्स पर अपराध के विषय में लिखकर सत्ता पर सवाल उठाने पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि तेजस्वी को 2005 के शासनकाल में अपराध का डेटा भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहिए। मंत्री ने कहा कि वे अपने शासनकाल का अभी के अपराध का डेटा दोनों पोस्ट करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। आज बिहार में कानून और सुशासन का राज है। बिहार के लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लोगों को अब जब, जहां और जिस समय जाना होता है, चले जाते हैं। उन्हें कोई डर या भय नहीं रहता है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, सम्पादक गोपाल अग्रवाल द्वारा श्री शेषसाई इंटरप्राइजेज प्लॉट नंबर. 98/1, को-ऑपरेटिव इंडस्टीयल एस्टेट, गांधी नगर, बालानगर के पास मेडचेल-मल्काजगिरि जिला. हैदराबाद 500037, तेलंगाना स्टेट से मुद्रित तथा प्लॉट नं. ए-23/5 तथा 6, दूसरा माला, ओपीआईई, बालानगर, हैदराबाद, मेडचल मलकाजगिरी जिला, तेलंगाना राज्य-500037 से प्रकाशित। आर. एन. आई रजिस्टर्ड नं. TELHIN/2019/78163, फोन नं. 040-29551811. E-mail : dailyshubhlabh@gmail.com